भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
(सामान्य, सामाजिक, आर्थिक तथा राजस्व प्रक्षेत्र)
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या - 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii – x
अध्याय - I		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1 - 1.4	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.5 - 1.7	2
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.8 - 1.10	2 - 3
अंश पूँजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक	1.11 - 1.12	4
वित्त लेखों के साथ समाधान	1.13 - 1.14	5
सा.क्षे.उ. का निष्पादन	1.15 - 1.20	5 - 7
लेखों के अंतिमीकरण में बकाया	1.21 - 1.25	7 - 9
लेखों पर टिप्पणियाँ एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	1.26 - 1.30	9 - 14
लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली	1.31	14
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.32	14 - 15
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.33 - 1.34	15
अध्याय - II		
सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की उर्जा संचरण गतिविधि से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
कार्यकारी सारांश	--	17 - 18
प्रस्तावना	2.1 - 2.5	19 - 20
लेखापरीक्षा क्षेत्र	2.6	20
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.7	21
लेखापरीक्षा मापदंड	2.8 - 2.9	21 - 22
संचरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण	2.10	22 - 23
लेखापरीक्षा निष्कर्ष		
नियोजन एवं विकास	2.11 - 2.12	23 - 29
संचरण प्रणाली का परियोजना प्रबन्धन	2.13 - 2.14	29 - 34
संविदा प्रबन्धन	2.15	34 - 37
संचरण प्रणाली का निष्पादन	2.16 - 2.24	37 - 44
ग्रिड प्रबंधन	2.25 - 2.29	44 - 48
उर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा	2.30	49
सामग्री प्रबंधन	2.31 - 2.33	49 - 51

अनुश्रवण एवं नियंत्रण	2.34 - 2.35	51 - 52
निष्कर्ष		52-53
अनुशंसाएँ		53
अध्याय - III		
लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन		
सरकारी कम्पनियाँ		
झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
आयकर एवं अग्रिम कर की कम अदायगी के फलस्वरूप आयकर तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.1	55 - 57
झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड		
श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली नहीं करना	3.2	57 - 58
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड		
कंडक्टर की अधिप्राप्ति पर निधियों का अवरोध	3.3	59 - 60
झारखण्ड राज्य के सरकारी कम्पनियों में निगमित शासन	3.4	
प्रस्तावना	3.4.1	60 - 61
निदेशक मंडल	3.4.2	61 - 64
प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता	3.4.3	65 - 66
सामान्य	3.4.4	66 - 67
निष्कर्ष	3.4.5	67
सांविधिक निगम		
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड		
डी.सी.एस. नियंत्रक काड्र्स की अधिप्राप्ति में देरी के कारण उत्पादन की हानि	3.5	68 - 69
सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	3.6	69 - 71
परिशिष्ट		
क्र.सं.	**विवरण**	
1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2012 को प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति को दर्शाता अद्यतन विवरणी	1.8	73 - 74
2	अद्यतन वर्ष के लिए तैयार लेखे के अनुसार सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.15	75 - 76
3	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अंश पूँजी, ऋण, अनुदान तथा सहाय्य, प्राप्त प्रत्याभूति, बकायों की माफी, अपलिखित ऋण तथा अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण तथा मार्च 2012 की समाप्ति पर प्रत्याभूति प्रतिबद्धता, को दर्शाती विवरणी	1.11	77
4	राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके	1.23	78 - 79

	लेखे बकाया हैं, में किए गए निवेश को दर्शाती विवरणी		
5	सांविधिक निगम के वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी	1.15	80
6	सांविधिक निगम के कार्यकारी परिणाम का विवरणी	1.15	81
7	बोर्ड की संगठनात्मक संरचना	2.2	82
8	2011-12 तक पाँच वर्षों के दौरान वोल्टेजवार क्षमता के अनुसार अभिवृद्धि की योजना, वास्तविक अभिवृद्धि तथा कमी की विवरणी	2.12	83 - 84
9	झारखण्ड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची एवं उनकी प्रदत्त पूँजी	3.4.1	85
10	अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के उल्लंघन की विवरणी	3.4.2	86 - 87
11	अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल में उपस्थिति की विवरणी	3.4.2	88
12	प्रबंध निदेशक, जिनका कार्यकाल एक साल से कम था, का विवरणी	3.4.2	89
13	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अधीन कम्पनियों के निबंधक को कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये वार्षिक रिटर्न की विवरणी	3.4.3	90 - 91
14	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अधीन कम्पनी निबंधक को वार्षिक लेखे दाखिल करने से संबंधित विवरणी	3.4.3	92
15	कम्पनियों द्वारा किये गये वार्षिक आम सभा की विवरणी	3.4.4	93 - 94
16	कंडिकायें/निष्पादन लेखा परीक्षा, जिसका उत्तर अप्राप्त था, की विवरणी	3.6.1	95
17	विभागावार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन की विवरणी	3.6.3	96
18	विभागावार प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर, जो अप्राप्त थे, की विवरणी	3.6.3	97

प्रस्तावना

1. सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं, जिनकी लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैः

(i) सरकारी कम्पनियाँ

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा की शर्त्तों) अधिनियम, 1971 यथा समय-समय पर संशोधित धारा 19(क) के अधीन झारखण्ड सरकार के समक्ष प्रस्तुती हेतु तैयार किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

4. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, जो एक सांविधिक निगम है, और झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। इस निगम/आयोग के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आए, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके। 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

6. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगम (झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड) की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 से शासित होती है। 31 मार्च 2012 तक झारखण्ड राज्य में 13 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (12 कम्पनियां तथा एक सांविधिक निगम) थे, जिनमें 7,588 कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 2011-12 में ₹ 2,139.72 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.72 प्रतिशत था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2012 को, 13 सा.क्षे.उ. में ₹ 6,192.40 करोड़ का निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। यह 2006-07 में ₹ 2,550.95 करोड़ से 142.75 प्रतिशत बढ़ा। 2011-12 में कुल निवेश का करीब 91.19 प्रतिशत उर्जा क्षेत्र में था। 2011-12 में, सरकार ने ₹ 1,179.41 करोड़ पूंजी, ऋण और अनुदान/सहाय्य के लिए दिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान, 13 सा.क्षे.उ. में से पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा चार सा.क्षे.उ. को ₹ 809.62 करोड़ की हानि हुई। शेष चार सा.क्षे.उ. ने अपने लेखों को प्रस्तुत नहीं किया। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, वर्ष 2010-11 एवं 1995-96 में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड तथा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 722.82 करोड़ एवं ₹ 86.59 करोड़ का भारी हानि वहन किया। कार्यशील सा.क्षे.उ. को हानि मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन और अनुश्रवण में कमियों के कारण हुआ। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,280.54 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 57.19 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा जिसे बेहतर प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता था। इस प्रकार, सा.क्षे.उ. के कामकाज में सुधार लाने और हानियों को कम करने की अपार संभावनाएं हैं।

बकाया लेखे

सितम्बर 2012 तक सभी 13 सा.क्षे.उ. के कुल 52 लेखे बकाया थे। सा.क्षे.उ. को लेखों की तैयारी से संबंधित कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ बकाया लेखों की निकासी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता

सा.क्षे.उ. के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान आठ पूर्ण हुए लेखों में से छः लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षकों ने गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिये। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण पर कुछ कमजोर क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं।

(अध्याय - I)

2. सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखा परीक्षा

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की उर्जा संचरण गतिविधि से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया था। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कार्यकारी सारांश निम्नवत हैं।

प्रस्तावना

झारखण्ड में विद्युत उत्पादन, संचरण तथा वितरण झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाता है सिवाय दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) कमान क्षेत्र में जहाँ डी.वी.सी. द्वारा संचरण किया जाता है एवं बोर्ड द्वारा वितरण किया जाता है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के परिणामस्वरूप बोर्ड का गठन मार्च 2001 में किया गया था। बोर्ड ने 2007-08 के दौरान 33 के.वी. पर डी.वी.सी. तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी.) द्वारा बोर्ड को संचारित की गई 2,777 एम.यू. उर्जा सहित 7,412 एम.यू. उर्जा संचारित किया जो 2011-12 में 29 प्रतिशत बढ़कर डी.वी.सी. तथा डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी. द्वारा संचारित 3,114 एम.यू. सहित 9,560 एम.यू. हो गयी। 2010-11 में बोर्ड का आवर्त्त ₹2,011 करोड़ था जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.86 प्रतिशत था। 31 मार्च 2012 को बोर्ड के नामावली में 465 कर्मचारी थे जिन्हें संचरण कार्य में लगाया गया था।

संचरण नेटवर्क नियोजन

बोर्ड ने 11वीं योजना अवधि के लिए संचरण नेटवर्क में अभिवृद्धि तथा विद्यमान नेटवर्क के रखरखाव हेतु एक योजना बनायी थी। बोर्ड के पास आंतरिक संसाधन नहीं था और वह पूंजीगत खर्चो के वित्तपोषण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.)/झारखण्ड सरकार (जी.ओ.जे.) पर निर्भर था। कार्य योजना के अनुसार 2007-08 से 2011-12 के अवधि में ₹ 6,275.59 करोड़ की आवश्यकता के विरूद्ध आर.ई.सी./ जी.ओ.जे. ने मात्र ₹463.24 करोड़ की निधि निर्गत किया। बोर्ड राशि का उपयोग करने में असमर्थ रहा तथा 31 मार्च 2012 को ₹89.50 करोड़ का शेष बिना खर्च का रहा। बोर्ड ने ₹ 6,275.59 करोड़ की अनुमानित लागत से 48 ग्रिड उप केन्द्रों (ग्रि.उ.के.) तथा अनुषंगी संचरण लाईनों के वृद्धि हेतु योजना 10 चालू ग्रि.उ.के. तथा 10 अनुषंगी संचरण लाइनों सहित बनायी, जिसके विरूद्ध 10 चालू ग्रि.उ.के. तथा पाँच अनुषंगी लाईन पूर्ण की जबकि पाँच संचरण लाइनें पूर्ण नहीं हो सकी। 14 ग्रि.उ.के. तथा अनुषंगी संचरण लाइनों को कार्य योजना में अक्सर परिवर्तन के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका जबकि 24 ग्रि.उ.के. तथा अनुषंगी संचरण लाइनों के लिए, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी तथा अन्य कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया।

परियोजना प्रबंधन

दुमका, डाल्टेनगंज, जपला, लोहरदगा, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज तथा कांके में ग्रि.उ.के. तथा देवघर-दुमका, दुमका-लालमटिया, लालमटिया-साहेबगंज, दुमका-पाकुड़ में संचरण लाइनों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, वन तथा रेलवे क्रासिंग अनुमति, आरेख तथा परिमाण संशोधन का अनुमोदन, प्रेषण निर्देश, रोड परमिट निर्गत करने, सामग्रियों की जाँच तथा बोर्ड द्वारा भुगतान में विलम्ब के कारण 12 से 51 माह के पश्चात पूर्ण हुआ। सिमडेगा में ग्रि.उ.के. तथा सिमडेगा-गुमला, लोहरदगा-गुमला, लोहरदगा-लातेहार तथा लातेहार-डाल्टेनगंज संचरण लाइन पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के 27 से 36 माह के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो सकी। लातेहार, डाल्टेनगंज तथा कांके में ग्रि.उ.के. को 35 माह से 61 माह की अवधि तक संबद्ध संचरण लाइनों के पूर्ण नहीं होने के कारण उर्जान्वित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹49.14 करोड़ की निधि अवरूद्ध रही।

संविदा प्रबन्धन

बोर्ड ने दुमका ग्रि.उ.के. तथा दुमका-देवघर (पैकेज-ए), दुमका-लालमटिया-साहेबगंज (पैकेज-बी) एवं दुमका-पाकुड़ (पैकेज-सी) संचरण लाइनों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के शर्त्तो में परिवर्तन किया तथा आई.ई.ई.एम.ए. मूल्य परिवर्तन सूचकांक के लिए आधार तिथि तोल-मोल तिथि से एक माह पूर्व की जगह निविदा खोलने की तिथि से एक माह पूर्व कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.38 करोड़ अत्यधिक भुगतान मूल्य परिवर्तन पर किया गया।

सचंरण प्रणाली का निष्पादन

220/132 के.वी. के रूपान्तरण क्षमता में अन्तराल 2007-08 में 623 एम.वी.ए. से बढ़कर 2011-12 में 1,348 एम.वी.ए. हुआ, जबकि 132/33 के.वी. में अन्तराल 2007-08 में 1,277 एम.वी.ए. से बढ़कर 2011-12 में 1,408 एम.वी.ए. हो गया था। डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में स्वयं के संचरण प्रणाली के कमी के कारण बोर्ड को अधिक दर पर ऊर्जा क्रय करना पड़ा, इस प्रकार 2011-12 में ₹ 299.53 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया। संचरण हानि 2008-09 में 5.04 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 5.50 प्रतिशत हुआ। 2008-09 से 2011-12 के दौरान संचरण हानि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.71 करोड़ की हानि हुई।

400 के.वी. पर टी.टी.पी.एस.-पी.टी.पी.एस. तथा टी.टी.पी.एस.-बिहारशरीफ लाइनों के आवेशित नहीं होने के कारण बोर्ड को 2007-08 से 2011-12 की अवधि में 603.38 एम.यू. ऊर्जा अन्य स्त्रोतों से अधिक दर पर क्रय करने के कारण ₹ 102.41 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा।

ग्रिड प्रबंधन

ग्रिड कोड की आवश्यकता के अनुसार अधिविकर्षण के संबंध में बोर्ड ने ग्रिड अनुशासन का पालन किया।

आपदा प्रबंधन

मई 2010 से अप्रैल 2012 की अवधि में पाँच टावरों के गिरने के बावजूद भी ₹ 7.61 करोड़ की लागत से खरीदा गया (अक्टूबर 2009) आपातकालीन पुनर्स्थापन प्रणाली (ई.आर.एस.) हटिया-II ग्री.उ.के. में व्यर्थ पड़ा रहा। बिना ई.आर.एस. के प्रयोग किये टावर निर्माण करने में बोर्ड को पाँच से 23 दिन लगा, जिसके कारण वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उर्जा 12 दिनों तक बाधित रही।

उर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा

ऊर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा नहीं किया गया था, चूँकि जादूगोड़ा ग्रि.उ.के. में कुछ फीडर मीटर रहित था जबकि सात ग्रि.उ.के. में मीटर त्रुटिपूर्ण थे तथा पाँच से अधिक वर्षों तक मीटर बदले नही गये एवं पिछले 24 वर्षों तक मीटरों की जाँच भी नहीं की गई थी। नमूना जाँच किये गये 13 ग्रि.उ.के. में से आठ ग्रि.उ.के. में उर्जा का निर्यात, आयातित उर्जा से अधिक था जो इंगित करता है कि मीटर दोषपूर्ण थे।

सामग्री प्रबंधन

मासिक उपभोग के संख्या के रूप में 2007-08 के दौरान अन्तिम रहतिया 19 माह का था जो 2009-10 में घटकर चार माह रह गया, परंतु 2010-11 में पुनः बढ़ कर 18 माह हो गया। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में रहतिया का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

निष्कर्ष एंव अनुशंसाएँ

बोर्ड के पास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त निधि नहीं थी तथा वह जी.ओ.जे./आर.ई.सी. पर निर्भर था। योजना अवधि में जी.ओ.जे. द्वारा आवंटित तथा आर.ई.सी. द्वारा निर्गत निधि का भी पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाया। बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा संचरण परियोजनाओं पर गठित कार्य बल की अनुशंसाओं का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप समय उल्लंघन हुआ। परियोजनाएँ मित्तव्ययी तथा दक्षतापूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई। संविदाओं के सौंपने में, एन.आई.टी./सी.वी.सी. की शर्त्तों का पालन नहीं हुआ। केवल खराबी का ही रखरखाव किया जा रहा था चूँकि बोर्ड के द्वारा संचालन एवं रखरखाव नियमावली नहीं बनाई गई थी। बड़ी आपदा के प्रभाव शमन हेतु खरीदी गई आपातकालीन पुनर्स्थापन प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया। बोर्ड ने अपने सभी ग्रि.उ.के. तथा फीडरों में मीटर नहीं लगाया था। बोर्ड ने कोई भी क्रय नीति तथा भंडार नियंत्रण तंत्र नहीं बनाया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में संचरण परियोजनाओं को अविलम्ब पूरा करना ताकि योजनाओं का पूर्ण लाभ उपयुक्त लाभार्थियों को पहुँचाना सुनिश्चित हो, सभी ग्रि.उ.के. तथा फीडरों में ठीक तरह से मीटर लगाना तथा दोषपूर्ण मीटरों को बदलना डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में संचरण लाइनों की स्थापना करना तथा उच्च संचरण हानि को झा.रा.वि.नि.आ. के अनुमान्य मानकों के अंदर लाने के क्षेत्र में ध्यान केन्द्रित करना शामिल है।

(अध्याय - II)

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

प्रतिवेदन में शामिल किये गये लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधन की कमियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्न प्रकार की हैः

नियमों, दिशा-निर्देशों, प्राक्रियाओं, संविदाओं के निबंधनों एवं शर्त्तो के अनुपालन न करने के कारण दो मामलों में ₹ 1.04 करोड़ की परिहार्य हानि।

(कंडिकाएँ 3.1 एवं 3.2)

अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण योजना के कारण एक मामले में ₹ 0.79 करोड़ का परिहार्य ब्याज का बोझ।

(कंडिका 3.3)

अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के कारण एक मामले में ₹ 2.53 करोड़ के अंशदान की हानि।

(कंडिका 3.5)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश निम्न प्रकार हैः

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम के संदर्भ में आयकर विवरणी दाखिल करने में विलम्ब के कारण वर्ष 2007-08 के व्यापार लाभ के विरूद्ध वर्ष 2005-07 के दौरान हुए व्यापार हानि के विकलन में विफलता और 2007-10 वर्षों के लिए अग्रिम कर की नहीं/कम अदायगी करने के फलस्वरूप आयकर एवं आयकर पर ब्याज ₹ 85.51 लाख का परिहार्य भुगतान।

(कंडिका 3.1)

कार्य निष्पादन के लिए ठोस योजनाओं के बिना ए.सी.एस.आर. डॉग कंडक्टर की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप ₹ 95.74 लाख निधि का अवरोध और **तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड** को ₹ 78.83 लाख का परिहार्य ब्याज का बोझ।

(कंडिका 3.3)

वार्षिक रखरखाव अनुबंध करने में **झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड** की विफलता, अतिरिक्त नियंत्रण कार्ड्स की भंडार में अनुपलब्धता और वितरित नियंत्रण प्रणाली के लिए नियंत्रक कार्ड्स की अधिप्राप्ति में विलंब के परिणामस्वरूप पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई संख्या-4, 516.50 घंटा तक बंद रहा। इसके फलस्वरूप 17.97 एम.यू. की विद्युत उत्पादन की हानि तथा ₹ 2.53 करोड़ के अंशदान की हानि हुई।

(कंडिका 3.5)

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

अध्याय -I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य की सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। राज्य के सा.क्षे.उ. की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

1.2 झारखण्ड राज्य में 31 मार्च 2012 को 12[1] सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे। कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध नहीं थी। सितम्बर 2012 तक अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 में राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,139.72 करोड़ का आवर्त्त प्राप्त किया। यह आवर्त्त 2011-12 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 1.72[2] प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 के दौरान सा.क्षे.उ. ने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कुल ₹ 786.68 करोड़ का घाटा वहन किया। 31 मार्च 2012 को इन्होंने कुल 7,588 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

1.3 राज्य के सा.क्षे.उ. में 29 विभागीय उपक्रमें (वि.उ.) जो वाणिज्यिक क्रियाकलापों को कार्यान्वित करते हैं किन्तु वे सरकारी विभागो के अंग हैं तथा एक स्वायत्त संस्थान, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) जिसका एकमात्र लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं, शामिल नहीं हैं।

1.4 वर्ष 2011-12 के दौरान एक सा.क्षे.उ.[3] स्थापित हुआ और कोई भी सा.क्षे.उ./सांविधिक निगम बन्द नहीं हुआ।

---

[1] झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.), झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको), झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको), झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.), ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट), झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.), कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड (के.ई.एल.), झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.), झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल), झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.) तथा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.)।

[2] प्रतिशत राज्य के वर्ष 2011-12 के जी.डी.पी. के आँकड़ों पर आधारित है, जो नवम्बर 2011 के वर्तमान मूल्यों (नई श्रृखंला) पर लिया गया है।

[3] जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.5 सरकारी कम्पनियों का लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार अधिशासित होता है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

1.6 राज्य के सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाती है।

1.7 सांविधिक निगम (झा.रा.वि.बो.) का लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा अधिशासित है तथा इसका सी.ए.जी. एक मात्र लेखापरीक्षक है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

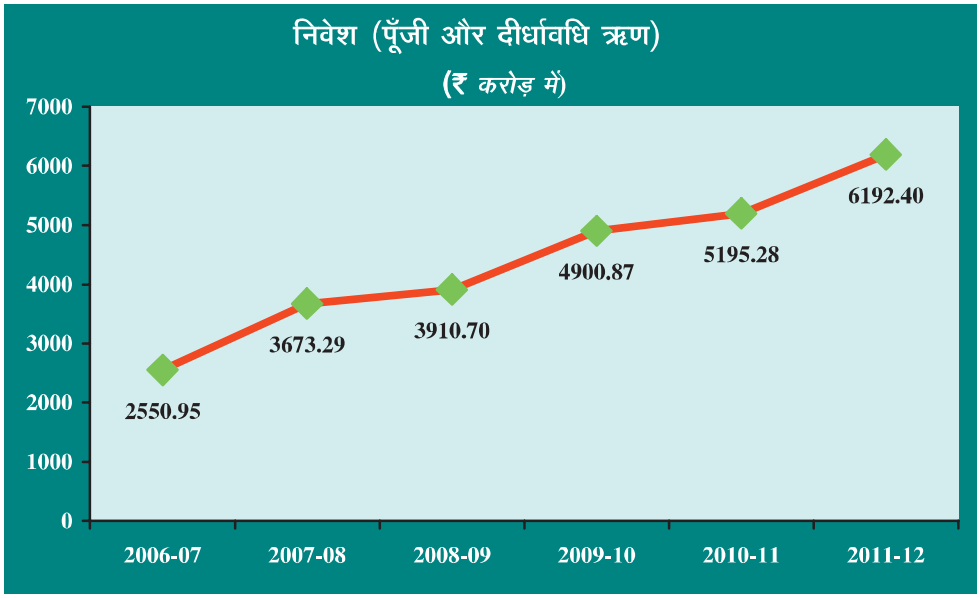
1.8 31 मार्च 2012 को 13 सा.क्षे.उ. (एक सांविधिक निगम सहित) में ₹ 6,192.40 करोड़ का कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। विस्तृत ब्यौरा निम्न तालिका में दिये गये हैं –

(₹ करोड़ में)

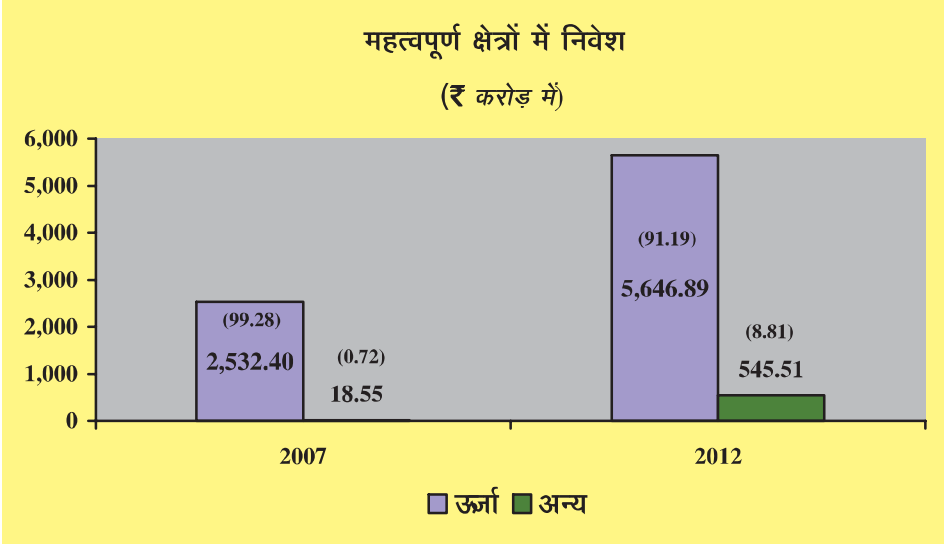
सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
170.10	1157.42	1327.52	-	4864.88	4864.88	6192.40

राज्य के सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के सारांशकृत स्थिति का ब्यौरा ***परिशिष्ट-1*** में दिये गये हैं।

1.9 31 मार्च 2012 को सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 2.75 *प्रतिशत* पूँजी में और 97.25 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों में था। सा.क्षे.उ. में निवेश 142.75 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ वर्ष 2006-07 में ₹ 2,550.95 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 6,192.40 करोड़ हो गया, जैसा कि निम्न रेखाचित्र में दिखाया गया है।



1.10 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 के अन्त तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनके प्रतिशत निम्न बार चार्ट में प्रकट किये गये हैं।



(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)

सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में था। पिछले छः वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़ते प्रवृति को दर्शाता है। यह वर्ष 2006-07 में ₹ 2,532.40 करोड़ से 122.99 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 5,646.89 करोड़ हो गया जो सरकार एवं अन्य निकायों के द्वारा मुख्यतः झा.रा.वि.बो. और टी.वी.एन.एल. को दिये ऋण के कारण हुआ।

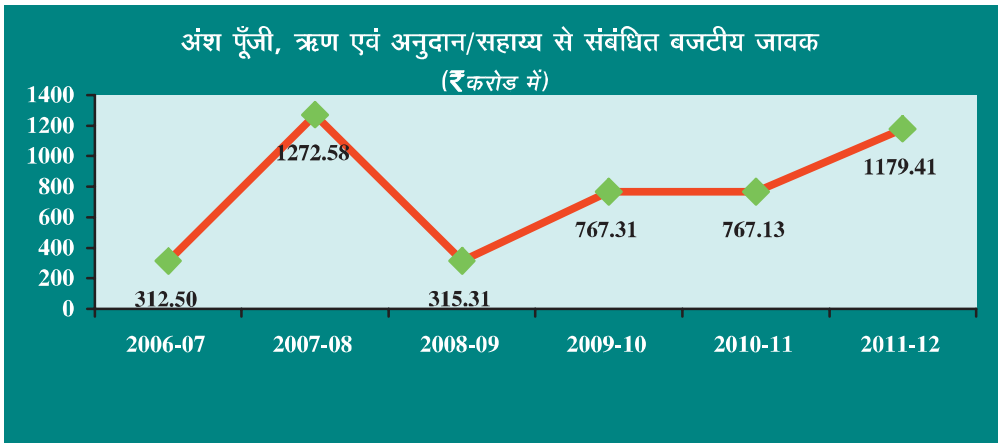
अंश पूँजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक

1.11 राज्य के सा.क्षे.उ. के संबंध में मार्च 2012 के अन्त में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा ***परिशिष्ट-3*** में दिये गये हैं।

वर्ष 2011-12 को समाप्त हुये तीन वर्षों का अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का सारांशीकृत ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की संख्या[4]	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से अंश पूँजी जावक	4	2.75	3	3.00	4	20.50
2.	बजट से दिये गये ऋण	1	362.76	1	313.55	2	408.91
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्ति	2	401.80	3	450.58	1	750.00
4.	**कुल जावक**		**767.31**		**767.13**		**1179.41**

1.12 पिछले छः वर्षों में अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा निम्न रेखाचित्र में दर्शाये गये हैं:



झा.रा.वि.बो. को सहाय्य के रूप में बजटीय सहायता (₹ 750 करोड़) तथा जे.एस.एफ. सी.एस.सी.एल. में निवेश (₹ 243.96 करोड़) करने के कारण, बजटीय जावक, वर्ष 2010-11 में ₹ 767.13 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 1,179.41 करोड़ हो गया।

[4] कुल जावक सा.क्षे.उ. के कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है (जी.आर.डी.ए., झारक्राफ्ट, जे.टी.डी.सी., जे.एस.बी.सी.एल, जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल तथा झा.रा.वि.बो.)।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति से संबंधित आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में अंकित आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग द्वारा अन्तर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2012 तक की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

(₹ *करोड़ में*)

संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	26.30	170.05	143.75
ऋण	6579.71	5702.40	877.31

1.14 हमने पाया कि आठ[5] सा.क्षे.उ. के आँकड़ों में अन्तर पाया गया और इन अन्तरों का समाधान 2001-02 से ही लम्बित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि के अंतर को पिछले वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों मे प्रतिवेदित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

सा.क्षे.उ. का निष्पादन

1.15 सा.क्षे.उ. के वित्तीय परिणामों और सांविधिक निगम के वित्तीय स्थिति तथा कार्यपरिणामों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः ***परिशिष्ट - 2, 5 एवं 6*** में दिये गये है। राज्य के जी.डी.पी. से सा.क्षे.उ. के आवर्त्त का प्रतिशत राज्य की अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के क्रियाकलापों के परिणाम को दिखाता है। निम्न तालिका 2006-07 से 2011-12 की अवधि में सा.क्षे.उ. के आवर्त्त साथ-साथ राज्य के जी.डी.पी. का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

(₹ *करोड़ में*)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आवर्त्त [6]	30.77	364.90	1552.32	1565.52	1442.90	2139.72
राज्य का जी.डी.पी.	73579	87620	75710.78	83077.90	108400.86	124160.16[7]
राज्य के जी.डी.पी. से आवर्त्त का प्रतिशत	0.04	0.42	2.05	1.88	1.33	1.72

राज्य की जी.डी.पी. के विरूद्ध सा.क्षे.उ. के आवर्त्त का *प्रतिशत* वर्ष 2010-11 में 1.33 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 1.72 हो गया है। आवर्त्त का *प्रतिशत* भी परिवर्तनीय प्रवृति को दर्शा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान आवर्त्त में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

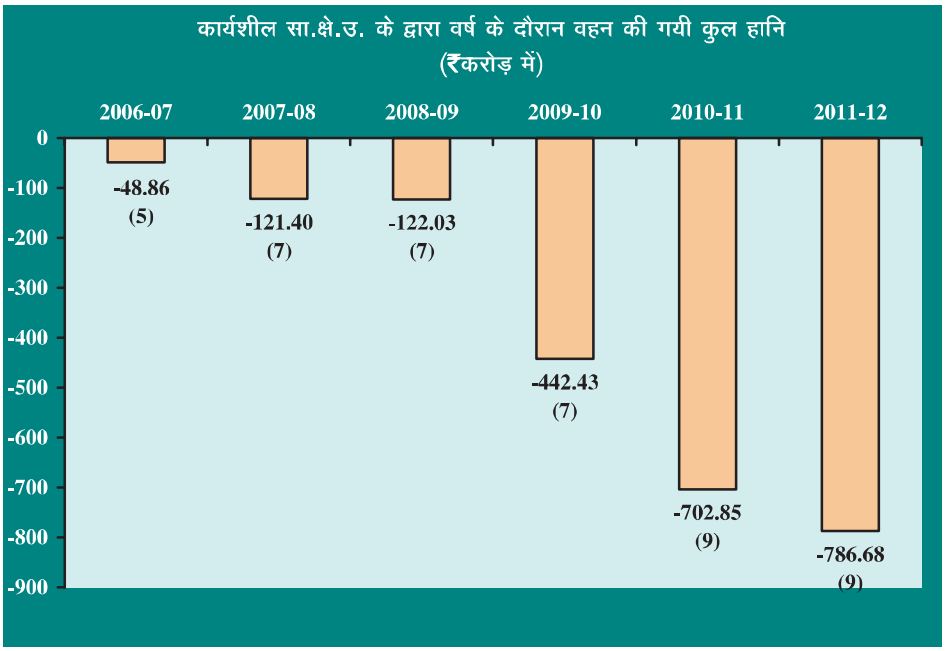
---

[5] टी.वी.एन.एल., जिडको, जे.टी.डी.सी., झारक्राफ्ट, जी.आर.डी.ए., जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल., झालको तथा झा.रा.वि.बो.।

[6] 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त्त।

[7] आँकड़े राज्य के वर्ष 2011-12 के जी.डी.पी. पर आधारित है, जो नवम्बर 2011 के वर्तमान मूल्यों (नई श्रृखंला) पर लिया गया है।

1.16 2006-07 से 2011-12 के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. के द्वारा वहन किये गये सकल हानि (शुद्ध) ₹ 48.86 करोड़ से बढ़कर ₹ 786.68 करोड़ हो गई जैसा की निम्न रेखाचित्र में दिया गया है:



(अंतिमीकृत लेखों के आधार पर, कोष्ठक में आँकड़े संबंधित वर्ष में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 13 सा.क्षे.उ. में से पाँच[8] सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.94 करोड़ का संचयी लाभ अर्जित किया जबकि चार[9] सा.क्षे.उ. ने ₹ 809.62 करोड़ की संचयी हानि वहन की। 2010-11 और 1995-96 के अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्रमशः झा.रा.वि.बो. (₹ 722.82 करोड़) और टी.वी.एन.एल. (₹ 86.59 करोड़) द्वारा भारी हानियाँ उठायी गयी। सितम्बर 2012 तक शेष चार[10] सा.क्षे.उ. ने अपना कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया।

1.17 सा.क्षे.उ. की हानि मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, योजना, उनके क्रियाकलापों के कार्यान्वयन, उनके संचालन और अनुश्रवण में कमियों के कारण आरोपित है। सी.ए.जी. के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,280.54 करोड़ की हानियाँ वहन की एवं ₹ 57.19 करोड़ का निरर्थक निवेश किया। शुद्ध हानि, नियंत्रणीय हानि तथा निरर्थक निवेश का वर्ष-वार विवरण निम्न तालिका में दिये गये है:

[8] जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी. तथा जे.टी.डी.सी.।
[9] झालको, जिडको, टी.वी.एन.एल. तथा झा.रा.वि.बो.।
[10] जी.आर.डी.ए., के.ई.एल., जे.एस.बी.सी.एल. तथा जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
शुद्ध हानि	442.43	702.85	786.68	1931.96
सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रणीय हानियाँ	1142.38	2650.89	487.27	4280.54
निरर्थक निवेश	0.41	46.17	10.61	57.19

1.18 सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी उपर्युक्त हानियाँ लेखापरीक्षा की नमूना जाँच पर आधारित है। वास्तविक नियंत्रणीय हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती थी। उपरोक्त, सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों में प्रभावशाली प्रबंधन एवं नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत को इंगित करती है।

1.19 अधतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के सा.क्षे.उ. से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मापदंड निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण	2537.65	3550.89	3774.90	4760.27	5050.68	6022.30
आवर्त्त [11]	30.77	364.90	1552.32	1565.52	1442.90	2139.72
ऋण/आवर्त्त अनुपात	82:1	10:1	2:1	3.04:1	3.50:1	2.81:1
ब्याज भुगतान	3.61	6.00	-	123.55	194.75	477.72
संचित हानि	42.90	265.45	269.30	589.81	1646.52	6385.11

1.20 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं किया था जिसके अंतर्गत सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रदत्त पूंजी पर न्यूनतम वापसी देना है। अपने अद्यतन अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार पाँच[12] सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.94 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का समापन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर करना होता है। उसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का समापन, लेखापरीक्षा और विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दिए गए तालिका में कार्यरत सा.क्षे.उ. के विवरण तथा उनके लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति (सितम्बर 2012) को दर्शाता है:

[11] 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. का आवर्त्त।

[12] जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., जे.टी.डी.सी., झारक्राफ्ट, तथा जे.एस.एम.डी.सी.।

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	9	10	11	12	13
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	3	7	14	12	8
3.	बकाये लेखे की संख्या	43	48*	46*	46	52*
4.	प्रत्येक सा.क्षे.उ. का बकाया औसत(3/1)	4.78	4.80	4.18	3.83	4.00
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखाओं का अंतिमीकरण होना बाकी था	9	10	11	12	13
6.	बकाये की सीमा (वर्ष)	1 से 14	1 से 15	1 से 16	1 से 17	1 से 16

1.22 2007-08 में नौ सा.क्षे.उ. के संदर्भ में बकाये लेखों की संख्या वर्षों के दौरान 43 से बढ़कर 2011-12 में 13 सा.क्षे.उ. के संदर्भ में 52 हो गयी थी।

1.23 राज्य सरकार ने नौ सा.क्षे.उ. में एक सांविधिक निगम सहित ₹ 1,390.21 करोड़ (अंश पूँजी ₹ 47.50 करोड़, ऋण ₹ 590.91 करोड़, अनुदान ₹ 751.80 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया जिनमें लेखें अंतिमीकृत नहीं हुये हैं जिसका विवरण ***परिशिष्ट-4*** में दिया गया है। लेखों और उनके अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गए निवेश और व्यय का लेखा जोखा उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था उसकी प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश, राज्य के विधायिका के संवीक्षा से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सार्वजनिक कोष की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है।

1.24 प्रशासनिक विभागों को इन इकाईयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है और यह सुनिश्चित करना है कि ये सा.क्षे.उ. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण नियत अवधि में कर लिये हैं। यद्यपि, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को अगस्त 2011 में बकाया लेखों के अंतिमीकरण के तथ्य को आकृष्ट किया गया, पर कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के निवल परिसंपत्तियों का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। अक्टूबर 2012 में प्रधान महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग का ध्यान इन लेखों के बकाया अंतिमीकरण हेतु भी आकृष्ट किया गया था एवं बकाये लेखों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता को उजागर किया था।

* कुछ सा.क्षे.उ. के लेखों के सौंपने के कारण, इन सा.क्षे.उ. के लेखे एक से अधिक वर्ष तक बकाया हैं यथा 2008-09 - झारक्राफ्ट - 2 बकाया लेखे, 2009-10 - के.ई.एल. - 1 बकाया लेखे, 2011-12 - जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल. - 1 बकाया लेखे।

1.25 उपर्युक्त बकाये की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को इसका अनुश्रवण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखों का समापन समय पर सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

1.26 वर्ष 2011-12 के दौरान छः कम्पनियों ने अपने आठ लेखाओं (बकाये लेखों सहित) को प्रधान महालेखाकार को 30 सितम्बर 2012 तक अग्रसारित किया। इसमें से तीन कम्पनियों[13] के तीन लेखाओं का पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो लेखों पर आयोग्य प्रमाण पत्र एवं छः लेखों पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिये। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और सी.ए.जी. के पूरक प्रतिवेदन इंगित करता है कि लेखाओं के रख-रखाव की गुणवत्ता में वृहद रूप से सुधार की जरूरत है। सी.ए.जी. के टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैः

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	1	0.23
2.	लाभ में कमी	2	0.74	2	7.70	3	3.52
3.	हानि में वृद्धि	1	0.03	-	-	-	-
4.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	-	-	-	-	-

1.27 कम्पनियों के लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैः

***झारखण्ड राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड* (2004-05)**

- ₹ 5000 से कम मूल्य की वस्तुओं पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास नहीं करने के कारण अचल सम्पत्तियों और लाभ को ₹ 1.48 लाख से अधिक आकलित किया गया।

***झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड* (2005-06)**

- ₹ 22.69 लाख ब्याज द्वारा अर्जित आय का लेखांकन नहीं करने के कारण वर्ष के लिए लाभ ₹ 22.69 से कम आकलित किया गया।
- ₹ 0.95 करोड़ के भारी भूमि चलित मशीन शुल्क तथा ₹ 2.21 करोड़ के किराया शुल्क में वृद्धि के कम प्रावधान के कारण ₹ 3.16 करोड़ लाभ अधिक आकलित किया गया।
- प्रारम्भिक व्यय को विकलित नहीं करने के कारण ₹ 26.44 लाख लाभ अधिक आकलित किया गया।

[13] झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी. तथा जे.टी.डी.सी.।

झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (2010-11)

- वर्ष 2010-11 के दौरान पूँजीगत अनुदान को राजस्व अनुदान के रूप में लेखांकन के कारण वर्ष के चालू दायित्वों एवं प्रावधानों और लाभ को ₹ 3 लाख से अधिक आकलित किया गया।

- वर्ष 2009-10 के दौरान जेनरेटर क्रय के लिए प्राप्त पूँजीगत अनुदान को राजस्व अनुदान के रूप में लेखांकन करने के कारण ₹ 4.72 लाख पूर्व अवधि के समायोजन एवं पूँजीगत अनुदान को कम तथा लाभ को अधिक आकलित किया गया।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखे (झा.रा.वि.बो.)

1.28 वर्ष के दौरान, 2010-11 का वार्षिक लेखा झा.रा.वि.बो. से प्राप्त किया गया जिसका सी.ए.जी. एकल लेखापरीक्षक है। वर्ष 2010-11 तक के लेखों का लेखापरीक्षा पुरा हो चुका था। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लेखे 2010-11 के दौरान प्राप्त किये गये थे लेकिन पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प्र.) 2011-12 में अंतिमीकृत किये गये। सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि खातों के रख-रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की जरूरत है। झा.रा.वि.बो. के लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2005-06 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 110.87 करोड़ से कम आकलित किया गया -

  - प्रयोग करने योग्य कोयले के स्टॉक की दैनिक प्राप्ति एवं खपत प्रतिवेदन के वर्तमान दर पर विचार न करना - ₹ 42.23 करोड़।

  - तेल भंडार में शामिल अनुपयोगी तेल के लिए प्रावधान न करना - ₹ 1.28 करोड़।

  - अंतिम निपटान पर कुमारधुवी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड से अवसूलनीय राशि का समायोजन न करना - ₹ 4.67 करोड़।

  - कम प्राप्त कोयले का दावा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) से प्राप्य के रूप में लेखांकन यद्यपि इस प्रकार के दावे को पिछले वर्षों में सी.सी.एल. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था - ₹ 14.09 करोड़।

  - बकाए अधिभार की राशि को विविध प्राप्य के रूप में लेखांकन यद्यपि इस प्रकार के दावे सी.सी.एल. द्वारा स्वीकार नहीं किये गये थे - ₹ 2.48 करोड़।

  - कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों से वसूलनीय राशि का लेखांकन जिसका कोई अभिलेख झा.रा.वि.बो. के पास उपलब्ध नहीं था एवं इस तरह वसूली की संभावना नगण्य थी - ₹ 1.31 करोड़।

- वर्ष 2005-06 के दौरान कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) में किए गए योगदान पर ब्याज का प्रावधान न करना - ₹ 60.15 लाख।

- वर्ष 2005-06 के लिए अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को देय ग्रेज्यूटी एवं पेंशन का कम प्रावधान करना - ₹ 43.07 करोड़।

- वर्ष 2005-06 के लिए रेलवे को देय विलम्ब शुल्क के बकाए खर्च का प्रावधान न करना - ₹ 1.14 करोड़।

वर्ष 2006-07 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 822.50 करोड़ से कम आकलित किया गया -

  - अंतिम निपटान के समय राज्य सरकार से वसूलनीय राशि का समायोजन न करना - ₹ 713.49 करोड़।

  - वर्ष 2006-07 के लिए अवकाश कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का कम प्रावधान - ₹ 88.69 करोड़।

  - समूह बचत योजना (जी.एस.एस.), 1986 के तहत प्राप्त निधि पर ब्याज भारित न करना - ₹ 9.75 करोड़।

  - सेवानिवृति लाभ जैसे जी.एस.एस. और अर्जित अवकाश का फरवरी एवं मार्च 2007 हेतु प्रावधान न करना - ₹ 1.15 करोड़।

  - चालू वर्ष एवं पिछले वर्षों (2001-02 से 2005-06) में कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज का प्रावधान न करना - ₹ 9.42 करोड़।

वर्ष 2007-08 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 368.98 करोड़ कम आकलित किया गया -

  - वर्ष 2007-08 में विविध देनदारों के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान नहीं करना - ₹ 231.32 करोड़।

  - इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) के अतिरिक्त सुरक्षा जमा पर विलंबित भुगतान अधिभार (वि.भु.अ.) भारित करना अपितु ई.सी.एल. एक सरकारी उपक्रम होने के कारण अतिरिक्त सुरक्षा जमा करने हेतु बाध्य नहीं है - ₹ 1.07 करोड़।

  - सा.भ.नि. पर ब्याज का कम प्रावधान (चालू वर्ष ₹ 16.58 करोड़ तथा गत वर्ष ₹ 74.84 करोड़) - ₹ 91.42 करोड़।

  - वर्ष 2007-08 हेतु अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के देय ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का कम प्रावधान - ₹ 45.17 करोड़।

वर्ष 2008-09 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 434.29 करोड़ कम आकलित किया गया -
    - मार्च 2009 में विद्युत की बिक्री से प्राप्त आय का लेखांकन न करना - ₹ 37.51 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 में निवेश पर अर्जित ब्याज आय पर देय नहीं का लेखांकन न करना - ₹ 2.79 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 में विविध देनदारों के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान न करना - ₹ 271.33 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 में 01.01.2006 से बकाया वेतन की राशि का लेखाबही में प्रावधान न करना - ₹ 168.38 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 में ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का कम प्रावधान - ₹ 34.88 करोड़।

वर्ष 2009-10 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 266.56 करोड़ कम आकलित किया गया -
    - वर्ष 2009-10 के लिए निवेश पर अनुपार्जित ब्याज का लेखाकरण न करना - ₹ 4.35 करोड़।
    - पूँजीगत प्रगतिशील कार्य का अचल सम्पत्ति में हस्तांतरण न करना, जो कि 31.03.2010 तक चालु हो चुका था - ₹ 8.56 करोड़।
    - दामोदर घाटी निगम द्वारा अप्रैल 2008 से अप्रैल 2009 के अवधि से संबंधित ईंधन लागत अधिभार (ई.ला.अ.) के दावे का प्रावधान न करना - ₹ 149.02 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का कम प्रावधान - ₹ 21.65 करोड़।
    - राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गा.ग्रा.वि.यो.) के अंतर्गत प्राप्त निधि पर काल्पनिक ब्याज एवं वित्त प्रभार का पूँजीकरण - ₹ 91.68 करोड़।

वर्ष 2010-11 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 107.99 करोड़ कम आकलित किया गया -
    - प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के कार्यालय द्वारा दावा किए गए 2003-04 से 2010-11 अवधि का लेखापरीक्षा शुल्क का कम प्रावधान - ₹ 3.76 करोड़।

- झारखण्ड सरकार से अंतिम निपटान पर अवसूलनीय राशि पर विलंबित भुगतान अधिभार भारित करना - ₹ 6.00 करोड़।
- पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) द्वारा 2010-11 से संबंधित पूरक विद्युत क्रय बिल के दावे का प्रावधान न करना - ₹ 2.99 करोड़।
- सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड से खरीदे गए कोयले पर स्वच्छ उर्जा उपकर ₹ 50 प्रति लाख टन (एम.टी.) की दर से तथा झारखण्ड मूल्य संबंर्धित कर चार प्रतिशत की दर से भारित न करना - ₹ 3.24 करोड़।
- जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक कर्मचारियों के देय बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का प्रावधान न करना - ₹ 1.85 करोड़।
- रा.गा.ग्रा.वि.यो. के अंतर्गत प्राप्त निधि पर काल्पनिक ब्याज एवं वित्त प्रभार का पूँजीकरण - ₹ 92.68 करोड़।
- 01.04.2007 से 31.03.2010 की अवधि के लिए पी.जी.सी.आई.एल. को देय संचरण शुल्क का कम प्रावधान - ₹ 9.80 करोड़।
- वर्ष 2010-11 के लिए निवेश पर अर्जित ब्याज आय पर देय नहीं का लेखांकन न करना - ₹ 12.33 करोड़।

1.29 झा.रा.वि.बो. के लेखों पर सी.ए.जी. के टिप्पणी का कुल मौद्रिक मूल्य निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

क्र.सं.	विवरण	2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	3	56.98
2.	हानि में वृद्धि	6	2140.29
3.	आर्थिक तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	40.81
कुल		**6**	**2238.08**

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ

1.30 सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउन्टेट) को सी.ए.जी. के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ए) के अन्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनके द्वारा लेखापरीक्षित की गई कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। 2011-12 के दौरान छः कम्पनियों[14] के अंतिमीकृत लेखों के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा किये गये मुख्य टिप्पणियों का सारांश सोदाहरण निम्न तालिका में दिये गये है:

[14] जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी., टी.वी.एन.एल. तथा जे.टी.डी.सी.।

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ अनुशंसाये की गई थी	परिशिष्ट-2 के अनुसार कम्पनियों का क्रम संख्या
1.	भंडार एवं पूर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का तय न होना	5	ए-01, ए-06, ए-07, ए-08, ए-10
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	1	ए-10
3.	अचल परिसम्पतियों की संचिका का पूर्ण विवरण जैसे मात्रात्मक विवरण तथा उसकी स्थिति, का संधारण नहीं होना	3	ए-01, ए-04, ए-08

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.31 2011-12 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सा.क्षे.उ. में ₹ 25.16 करोड़ की वसूली हेतु प्रबंधन को इंगित किये गये थे, जिनमें से ₹ 31.16 लाख के मामले झा.रा.वि.बो. द्वारा स्वीकार किये गये, अपितु अभी तक झा.रा.वि.बो. द्वारा वसूली नहीं की गयी थी (सितम्बर 2012)।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.32 निम्न तालिका झा.रा.वि.बो. के लेखों पर सी.ए.जी. द्वारा जारी किये गये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दिखलाती है:

क्र. सं.	सांविधिक निगम	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र.विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		
			पृ.ले.प्र. का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विलम्ब का कारण
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	--	2001-02	20.08.2010	झा.रा.वि.बो. द्वारा पर्याप्त मात्रा में पृ.ले.प्र. का मुद्रण नहीं करने के कारण विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया।
			2002-03	07.02.2011	
			2003-04	07.03.2011	
			2004-05	07.06.2011	
			2005-06	09.11.2011	
			2006-07	15.12.2011	
			2007-08	31.01.2012	
			2008-09	30.03.2012	
			2009-10	30.03.2012	
			2010-11	26.04.2012	

पृ.ले.प्र. को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायिकी नियंत्रण कमजोर होता है एवं बाद में वित्तीय जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2012)।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.33 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत अप्रैल 2003 में विद्युत टैरिफ का युक्तिसंगत व्याख्या, विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण के संबंध में सुझाव देने और लाईसेंस निर्गत करने हेतु किया गया है। 2011-12 के दौरान, झा.रा.वि.नि.आ. ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर दो एवं अन्य मामलों में 24 आदेश जारी किये।

1.34 चिन्हित लक्ष्यों के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के मध्य एक संयुक्त वचनबद्धता पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर अप्रैल 2001 को किया गया। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक हुई उपलब्धि की प्रगति को निम्न तालिका में बतलाया गया है।

क्र. सं.	लक्ष्य		उपलब्धि [15]
1.	बिक्री हेतु प्राप्त विद्युत के 18 *प्रतिशत* तक तंत्र हानि को कम करना		तंत्र हानि घटकर 35.04 प्रतिशत रह गयी (नवम्बर 2010)
2.	100 प्रतिशत उपभोक्ताओं का मीट्रिकरण	एकल चरण (शहरी)	87.78 प्रतिशत
		एकल चरण (ग्रामीण)	64.13 *प्रतिशत*
		निम्न विभव (एल.टी.)	96.03 प्रतिशत
		उच्च विभव (एच.टी.)	98.14 प्रतिशत

[15] झा.रा.वि.बो. ने अबतक उपलब्धि की सूचना नहीं भेजी थी। इसलिए नवम्बर 2010 के आँकड़े लिए गए थे।

अध्याय-II

सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय -II

2. सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की उर्जा संचरण गतिविधि से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

झारखण्ड में विद्युत उत्पादन, संचरण तथा वितरण झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाता है सिवाय दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) कमान क्षेत्र में जहाँ डी.वी.सी. द्वारा संचरण किया जाता है एवं बोर्ड द्वारा वितरण किया जाता है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के परिणामस्वरूप बोर्ड का गठन मार्च 2001 में किया गया था। बोर्ड ने 2007-08 के दौरान 33 के.वी. पर डी.वी.सी. तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी.) द्वारा बोर्ड को संचारित की गई 2,777 एम.यू. उर्जा सहित 7,412 एम.यू. उर्जा संचारित किया जो 2011-12 में 29 प्रतिशत बढ़कर डी.वी.सी. तथा डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी. द्वारा संचारित 3,114 एम.यू. सहित 9,560 एम.यू. हो गयी। 2010-11 में बोर्ड का आवर्त्त ₹ 2,011 करोड़ था जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.86 प्रतिशत था। 31 मार्च 2012 को बोर्ड के नामावली में 465 कर्मचारी थे जिन्हें संचरण कार्य में लगाया गया था।

संचरण नेटवर्क नियोजन

बोर्ड ने 11वीं योजना अवधि के लिए संचरण नेटवर्क में अभिवृद्धि तथा विद्यमान नेटवर्क के रखरखाव हेतु एक योजना बनायी थी। बोर्ड के पास आंतरिक संसाधन नहीं था और वह पूंजीगत खर्चो के वित्तपोषण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.)/झारखण्ड सरकार (जी.ओ.जे.) पर निर्भर था। कार्य योजना के अनुसार 2007-08 से 2011-12 के अवधि में ₹ 6,275.59 करोड़ की आवश्यकता के विरूद्ध आर.ई.सी./जी.ओ.जे. ने मात्र ₹ 463.24 करोड़ की निधि निर्गत किया। बोर्ड राशि का उपयोग करने में असमर्थ रहा तथा 31 मार्च 2012 को ₹ 89.50 करोड़ का शेष बिना खर्च का रहा। बोर्ड ने ₹ 6,275.59 करोड़ की अनुमानित लागत से 48 ग्रिड उप केन्द्रों (ग्रि.उ.के.) तथा अनुषंगी संचरण लाईनों के वृद्धि हेतु योजना 10 चालू ग्रि.उ.के. तथा 10 अनुषंगी संचरण लाइनों सहित बनायी, जिसके विरूद्ध 10 चालू ग्रि.उ.के. तथा पाँच अनुषंगी लाईन पूर्ण की जबकि पाँच संचरण लाइनें पूर्ण नहीं हो सकी।

14 ग्रि.उ.के. तथा अनुषंगी संचरण लाइनों को कार्य योजना में अक्सर परिवर्तन के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका जबकि 24 ग्रि.उ.के. तथा अनुषंगी संचरण लाइनों के लिए, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी तथा अन्य कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया।

परियोजना प्रबंधन

दुमका, डाल्टेनगंज, जपला, लोहरदगा, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज तथा कांके में ग्रि.उ.के. तथा देवघर-दुमका, दुमका-लालमटिया, लालमटिया-साहेबगंज, दुमका-पाकुड़ में संचरण लाइनों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, वन तथा रेलवे क्रासिंग अनुमति, आरेख तथा परिमाण संशोधन का अनुमोदन, प्रेषण निर्देश, रोड परमिट निर्गत करने, सामग्रियों की जाँच तथा बोर्ड द्वारा भुगतान में विलम्ब के कारण 12 से 51 माह के पश्चात पूर्ण हुआ। सिमडेगा में ग्रि.उ.के. तथा सिमडेगा-गुमला, लोहरदगा-गुमला, लोहरदगा-लातेहार तथा लातेहार-डाल्टेनगंज संचरण लाइन पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के 27 से 36 माह के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो सकी। लातेहार, डाल्टेनगंज तथा कांके में ग्रि.उ.के. को 35 माह से 61 माह की अवधि तक संबंद्ध संचरण लाइनों के पूर्ण नहीं होने के कारण उर्जान्वित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.14 करोड़ की निधि अवरूद्ध रही।

संविदा प्रबन्धन

बोर्ड ने दुमका ग्रि.उ.के. तथा दुमका-देवघर (पैकेज-ए), दुमका-लालमटिया-साहेबगंज (पैकेज-बी) एवं दुमका-पाकुड़ (पैकेज-सी) संचरण लाइनों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के शर्त्तो में परिवर्तन किया तथा आई.ई.ई.एम.ए. मूल्य परिवर्तन सूचकांक के लिए आधार तिथि तोल-मोल तिथि से एक माह पूर्व की

जगह निविदा खोलने की तिथि से एक माह पूर्व कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.38 करोड़ अत्यधिक भुगतान मूल्य परिवर्तन पर किया गया।

सचंरण प्रणाली का निष्पादन

220/132 के.वी. के रूपान्तरण क्षमता में अन्तराल 2007-08 में 623 एम.वी.ए. से बढ़कर 2011-12 में 1,348 एम.वी.ए. हुआ, जबकि 132/33 के.वी. में अन्तराल 2007-08 में 1,277 एम.वी.ए. से बढ़कर 2011-12 में 1,408 एम.वी.ए. हो गया था। डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में स्वयं के संचरण प्रणाली के कमी के कारण बोर्ड को अधिक दर पर ऊर्जा क्रय करना पड़ा, इस प्रकार 2011-12 में ₹ 299.53 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया। संचरण हानि 2008-09 में 5.04 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 5.50 प्रतिशत हुआ। 2008-09 से 2011-12 के दौरान संचरण हानि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.71 करोड़ की हानि हुई।

400 के.वी. पर टी.टी.पी.एस.-पी.टी.पी.एस. तथा टी.टी.पी.एस.-बिहारशरीफ लाइनों के आवेशित नहीं होने के कारण बोर्ड को 2007-08 से 2011-12 की अवधि में 603.38 एम.यू. ऊर्जा अन्य स्त्रोतों से अधिक दर पर क्रय करने के कारण ₹ 102.41 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा।

ग्रिड प्रबंधन

ग्रिड कोड की आवश्यकता के अनुसार अधिविकर्षण के संबंध में बोर्ड ने ग्रिड अनुशासन का पालन किया।

आपदा प्रबंधन

मई 2010 से अप्रैल 2012 की अवधि में पाँच टावरों के गिरने के बावजूद भी ₹ 7.61 करोड़ की लागत से खरीदा गया (अक्टूबर 2009) आपातकालीन पुनर्स्थापन प्रणाली (ई.आर.एस.) हटिया-II ग्रि.उ.के. में व्यर्थ पड़ा रहा। बिना ई.आर.एस. के प्रयोग किये टावर निर्माण करने में बोर्ड को पाँच से 23 दिन लगा, जिसके कारण वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उर्जा 12 दिनों तक बाधित रही।

उर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा

ऊर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा नहीं किया गया था, चूँकि जादूगोड़ा ग्रि.उ.के. में कुछ फीडर मीटर रहित था जबकि सात ग्रि.उ.के. में मीटर त्रुटिपूर्ण थे तथा पाँच से अधिक वर्षों तक मीटर बदले नही गये एवं पिछले 24 वर्षों तक मीटरों की जाँच भी नहीं की गई थी। नमूना जाँच किये गये 13 ग्रि.उ.के. में से आठ ग्रि.उ.के. में उर्जा का निर्यात, आयातित उर्जा से अधिक था जो इंगित करता है कि मीटर दोषपूर्ण थे।

सामग्री प्रबंधन

मासिक उपभोग के संख्या के रूप में 2007-08 के दौरान अन्तिम रहतिया 19 माह का था जो 2009-10 में घटकर चार माह रह गया, परंतु 2010-11 में पुनः बढ़ कर 18 माह हो गया। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में रहतिया का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

निष्कर्ष एंव अनुशंसाएँ

बोर्ड के पास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त निधि नहीं थी तथा वह जी.ओ.जे./आर.ई.सी. पर निर्भर था। योजना अवधि में जी.ओ.जे. द्वारा आवंटित तथा आर.ई.सी. द्वारा निर्गत निधि का भी पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाया। बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा संचरण परियोजनाओं पर गठित कार्य बल की अनुशंसाओं का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप समय उल्लंघन हुआ। परियोजनाएँ मित्तव्ययी तथा दक्षतापूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई। संविदाओं के सौंपने में, एन.आई.टी./सी.वी.सी. की शर्तों का पालन नहीं हुआ। केवल खराबी का ही रखरखाव किया जा रहा था चूँकि बोर्ड के द्वारा संचालन एवं रखरखाव नियमावली नहीं बनाई गई थी। बड़ी आपदा के प्रभाव शमन हेतु खरीदी गई आपातकालीन पुनर्स्थापन प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया। बोर्ड ने अपने सभी ग्रि.उ.के. तथा फीडरों में मीटर नहीं लगाया था। बोर्ड ने कोई भी क्रय नीति तथा भंडार नियंत्रण तंत्र नहीं बनाया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में संचरण परियोजनाओं को अविलम्ब पूरा करना ताकि योजनाओं का पूर्ण लाभ उपयुक्त लाभार्थियों को पहुँचाना सुनिश्चित हो, सभी ग्रि.उ.के. तथा फीडरों में ठीक तरह से मीटर लगाना तथा दोषपूर्ण मीटरों को बदलना डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में संचरण लाइनों की स्थापना करना तथा उच्च संचरण हानि को झा.रा.वि.नि.आ. के अनुमान्य मानकों के अंदर लाने के क्षेत्र में ध्यान केन्द्रित करना शामिल है।

प्रस्तावना

2.1 भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने 2012 तक सभी को विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्त्ति को ध्यान में रखते हुए, फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) तैयार किया। एन.ई.पी. में संचरण प्रणाली में पर्याप्त एवं यथासमय निवेश की जरूरत के अलावा देश के लिए मजबूत तथा समेकित उर्जा प्रणाली को विकसित करने पर जोर दिया गया। इसमें, केन्द्रीय/राज्य संचरण उपयोगिताओं के समन्वय के साथ राष्ट्रीय तथा राजकीय ग्रिडों के विकास की जरूरत को भी ध्यान में रखा गया। झारखण्ड में विद्युत उत्पादन, संचरण तथा वितरण झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाता है सिवाय दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) कमान क्षेत्र[1] में जहाँ डी.वी.सी. द्वारा संचरण किया जाता है एवं बोर्ड द्वारा वितरण किया जाता है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के परिणामस्वरूप बोर्ड का गठन मार्च 2001 में किया गया था।

संगठनात्मक ढाँचा

2.2 बोर्ड का प्रबंधन झारखण्ड सरकार (जी.ओ.जे.) द्वारा नियुक्त छः सदस्यों के शासी निकाय में निहित है। बोर्ड के दैनिक कार्यकलाप अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी हैं। सदस्य (वित्त), सदस्य (वितरण तथा संचरण), सदस्य (तकनीकी), प्रधान सचिव, उर्जा विभाग एवं वित्त सचिव अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष द्वारा बोर्ड मुख्यालय के मुख्य अभियंताओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के तीन महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंताओं के सहयोग से, विद्युत संचरण तथा संचरण प्रणाली के परिचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। संगठनात्मक चार्ट ***परिशिष्ट-7*** में दर्शायी गई है।

परिचालन का क्षेत्र तथा संचरण नेटवर्क

2.3 निर्बाध कामकाज तथा इसके दक्षतापूर्ण परिचालन करने के लिए, बोर्ड ने अपने परिचालन क्षेत्र को प्रत्येक महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता के नेतृत्व में तीन[2] संचरण क्षेत्रों, पाँच[3] संचरण अंचल तथ 11[4] संचरण प्रमण्डलों में बाँटा है (मार्च 2012 तक)।

2.4 वर्ष 2007-08 के दौरान, 7,412 मिलियन इकाई (एम.यू.) उर्जा (डी.वी.सी. तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी.) द्वारा 33 किलो वोल्ट (के.वी.) पर बोर्ड को संचारित 2,777 एम.यू. सहित) संचारित हुआ था जो 2011-12 में 9,560 एम.यू. (डी.वी.सी. तथा डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी. द्वारा संचारित 3,114 एम.यू. सहित) बढ़ा अर्थात 2007-12 की अवधि में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बोर्ड ने 2007-12 की अवधि में, 1,060 मेगावोल्ट एम्पीयर (एम.वी.ए.) क्षमता के दस[5] ग्रि.उ.के. तथा 402

---

[1] सम्पूर्ण धनबाद और बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरीडीह, चतरा, पलामू, राँची, लोहरदगा एवं दुमका के कुछ क्षेत्र।

[2] राँची, जमशेदपुर तथा दुमका (देवघर में)।

[3] राँची, जमशेदपुर, चाईबासा, देवघर तथा दुमका।

[4] राँची, डाल्टेनगंज, गुमला, आदित्यपुर, चाण्डिल, गोलमुरी, चाईबासा, देवघर-I, देवघर-II, लालमटिया तथा दुमका।

[5] हटिया-II में 220/132 के.वी. तथा दुमका, चक्रधरपुर, डाल्टेनगंज, जपला, साहेबगज, पाकुड़, काँके, लोहरदगा तथा लातेहार में 132/33 के.वी.।

परिपथ किलोमीटर (सी.के.एम.) के पाँच[6] लाइनों का निर्माण के साथ साथ विद्यमान रूपांतरण क्षमता को 120 एम.वी.ए. संवर्धित किया। 31 मार्च 2012 को बोर्ड के पास 3,268 (एम.वी.ए.) की अधिष्ठापित क्षमता के साथ 2,524 (सी.के.एम.) तथा 29 (ग्रि.उ.के.) का एक संचरण नेटवर्क था, जो 220 के.वी. पर 5,887 एम.यू. की वार्षिक संचारण में सक्षम था।

वित्तीय स्थिति एवं मानवशक्ति

2.5 2010-11 में बोर्ड का आवर्त्त ₹ 2,011 करोड़ था, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.86 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2011 को वर्ष की हानि तथा संचयी हानियाँ क्रमशः ₹ 723 करोड़ तथा ₹ 6,079 करोड़ थी। 31 मार्च 2012 को 771 कर्मचारियों के स्वीकृत मानवशक्ति के विरूद्ध बोर्ड की नामावली में 465 कर्मचारी थे जिन्हें संचरण कार्य में लगाया गया था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र

2.6 मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा में 2007-08 से 2011-12 तक संचरण कार्य से संबंधित बोर्ड के निष्पादन की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में मुख्यालय (राँची) के विभिन्न स्कंधों, राज्य भार वितरण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) तीन[7] क्षेत्रों में से दो[8], चयनित क्षेत्रों के दो अंचलों[9], राँची अंचल को उर्जा का संचारण करने वाले सभी उत्पादन स्टेशनों तथा राँची एवं जमशेदपुर अंचलों के अन्तर्गत स्थित सभी तीन 220/132 के.वी. ग्रि.उ.के. के अभिलेखों की जाँच शामिल थी। देवघर अंचल का भी चयन देवघर तथा जामताड़ा के दो 132/33 के.वी. ग्रि.उ.के. में अत्यधिक भार रहने के कारण किया गया था। विस्तृत जाँच के लिए 2007-12 की अवधि के दौरान निर्मित किए गए दस ग्रि.उ.के., पाँच लाईनों तथा 120 एम.वी.ए. विद्यमान रूपांतरण क्षमता का संवर्द्धन में से आठ[10] ग्रि.उ.के. (क्षमताः 740 एम.वी.ए.), चार[11] लाईनों (क्षमताः 282 सी.के.एम.) तथा 100 एम.वी.ए. विद्यमान रूपांतरण क्षमता का संवर्द्धन का चयन किया गया था।

---

[6] 132 के.वी. दुमका-लालमटिया, लालमटिया-साहेबगंज, दुमका-देवघर, दुमका-पाकुड़ तथा 220 के.वी. हटिया-लोहरदगा।

[7] राँची, जमशेदपुर तथा दुमका (देवघर में)।

[8] राँची, जमशेदपुर।

[9] राँची, जमशेदपुर।

[10] दुमका, डाल्टेनगंज, जपला, साहेबगंज, पाकुड़ , कांके, लोहरदगा तथा लातेहार।

[11] दुमका-लालमटिया, लालमटिया-साहेबगंज, दुमका-देवघर तथा दुमका-पाकुड़।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.7 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि :

योजना एवं विकास

- ❖ राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना के दिशा निर्देशों तथा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) के निर्देशों के अनुसार भावी योजना तैयार किया गया था तथा योजना बनाने में विफलता के असर, यदि हो तो, उसका आकलन;
- ❖ संचरण प्रणाली को मित्तव्ययी, दक्षतापूर्ण तथा प्रभावकारी रूप से विकसित तथा स्थापित किया गया था;

संचरण प्रणाली का परिचालन एवं अनुरक्षण

- ❖ संचरण प्रणाली का परिचालन तथा अनुरक्षण मित्तव्ययी, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी रूप से किया जाता था;
- ❖ अप्रत्याशित रूकावटों के विरूद्ध सुरक्षित परिचालन के लिए एक आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित किया गया था;
- ❖ प्रभावकारी विफलता विश्लेषण प्रणाली स्थापित किया गया था;
- ❖ प्रभावकारी एवं दक्षतापूर्ण उर्जा अंकेक्षण प्रणाली की स्थापना की गई थी;

सामग्री प्रबंधन

- ❖ सामग्री अधिप्राप्ति के लिए एक दक्षतापूर्ण, मित्तव्ययी एवं प्रभावकारी प्रणाली था तथा सामग्री नियत्रंण प्रणाली स्थापित किया गया था;
- ❖ रहतिया प्रबंधन एवं अप्रचलित भंडार के निपटान के लिए एक प्रभावकारी प्रणाली थी;

अनुश्रवण एवं नियंत्रण

- ❖ दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली एवं आंतरिक नियत्रंण रूपरेखा मौजूद थी।

लेखापरीक्षा मापदंड

2.8 लेखापरीक्षा मापदण्ड के निम्नलिखित स्त्रोत थेः-

- ❖ राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना के प्रावधान;
- ❖ मित्तव्ययिता, दक्षता, प्रभावी, समरूपता तथा आचार के सिद्धान्तों के संदर्भ में संविदा प्रदान करने की मानक प्रक्रिया;
- ❖ जून 1994 में उर्जा मंत्रालय (एम.ओ.पी.) द्वारा निर्गत संचरण योजना मापदण्ड का नियमावली (एम.टी.पी.सी.);
- ❖ योजना, परिचालन, संयोजन संहिता को सम्मिलित किए हुए ग्रिड संहिता;

- ❖ झारखण्ड सरकार (जी.ओ.जे.)/एम.ओ.पी. द्वारा निर्देश;
- ❖ झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.)/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा निर्गत मानदण्ड/दिशानिर्देश;
- ❖ बोर्ड के द्वारा लाइनों के अनुरक्षण के लिए देश में संचरण प्रणाली में सर्वोत्तम प्रथाओं को अद्यतन करने के लिए समिति का प्रतिवेदन (जनवरी 2002); तथा
- ❖ उर्जा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2005 में गठित संचरण परियोजनाओं पर कार्यदल का प्रतिवेदन।

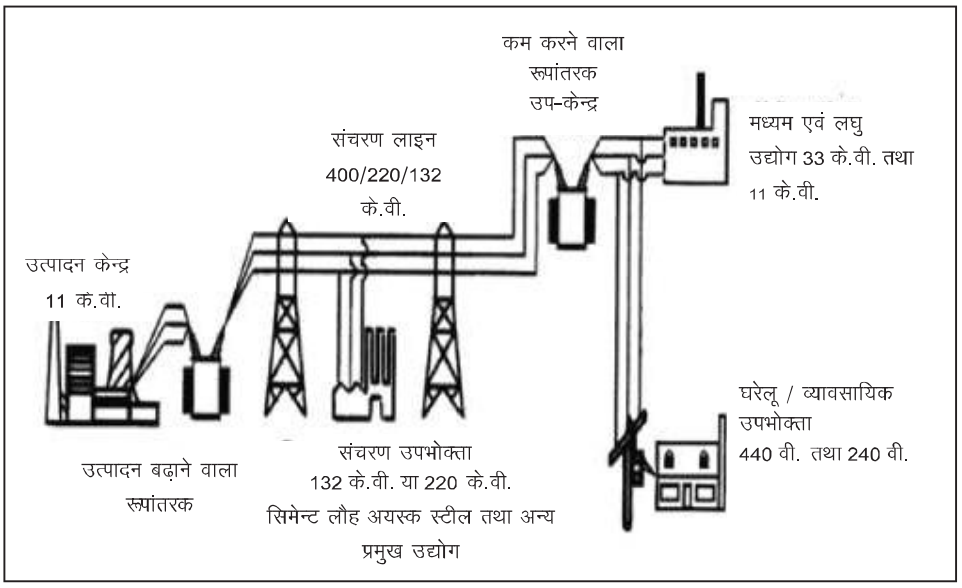
2.9 28 मार्च 2012 को अयोजित "प्रवेश सम्मेलन" में हमने बोर्ड से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या की। इसके पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्ष बोर्ड तथा राज्य सरकार को 16 जुलाई 2012 को प्रतिवेदित किया गया। 30 अक्टूबर 2012 को आयोजित "निकासी सम्मेलन" में बोर्ड के अध्यक्ष तथा विशेष सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ प्रारूप प्रतिवेदन के निष्कर्षों को उत्तर के साथ विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तर दिया (जनवरी 2013)। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय उत्तरों पर विचार किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्त्ती कंडिकाओं में परिचर्चित है।

संचरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

2.10 विद्युत के संचरण को उच्च वोल्टेज सामान्यतः 132 के.वी. तथा अधिक पर, लम्बी दूरी तक उर्जा का अधिक मात्रा में स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत संचरण से पहले संचरण में हानि कम करने तथा ग्रिड की दक्षता को बढ़ाने के लिए उर्जा संयंत्रों में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टेज विद्युत में अपवर्धन किया जाता है। उच्च ताप विद्युत प्रणाली के अंतर्गत ग्रि.उ.के. में ऐसी सुविधाएँ हैं जिसका उपयोग एक स्तर से दूसरे स्तर पर ताप के बढ़ाने/घटाने, विद्युत प्रणालियों को जोड़ने तथा प्रणाली के अंदर तथा बाहर स्विचिंग यंत्र के रूप में किया जाता है। उत्पादन संयंत्रों में ग्रि.उ.के. अपवर्धन लम्बी दूरी पर संचरण के लिए वोल्टेज के वृद्धि के लिए रूपांतरक का उपयोग करता है।

संचरण लाइनें उच्च वोल्टेज के विद्युत उर्जा को प्रवाहित करते है। तत्पश्चात, वोल्टेज कम करने वाला ग्रि.उ.के. उपभोक्ताओं के वितरण के लिए उप संचरण वोल्टेज स्तर के वोल्टेज को कम करता है। वितरण प्रणाली में लाईन, पोल, रूपांतरक तथा विशिष्ट वोल्टेज पर विद्युत वितरण के लिए अन्य यंत्र की जरूरत शामिल है।

विद्युत शक्ति को संग्रहित नहीं किया जा सकता है अतः उत्पादन आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक वितरण प्रणाली को उत्पादित उर्जा को माँग के अनुसार संतुलन सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड प्रबंधन नामक नियंत्रण की प्राधिकृत प्रणाली की आवश्यकता है। संचरण प्रक्रिया की सचित्र प्रस्तुति निम्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है:



लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नियोजन एवं विकास

2.11 केन्द्रीय संचरण उपयोगिता (सी.टी.यू) तथा राज्य संचरण उपयोगिताओं (एस.टी.यू.) पर राष्ट्रीय विद्युत योजना के आधार पर सभी संबंधित अभिकरणों से समन्वय कर नेटवर्क नियोजन एवं विकास करने का मुख्य उत्तरदायित्व है। दसवीं योजना के अन्त तक (मार्च 2007), देश में संचरण प्रणाली 765/ एच.वी.डी.सी./ 400/230/220/ के.वी. पर संरचण लाईन 1.98 लाख सी.के एम. थी, जिसे ग्यारहवीं योजना के अन्त अर्थात मार्च 2012 तक 2.93 लाख सी.के.एम. तक बढ़ाने की योजना थी। 2006-07 के अन्त तक, राष्ट्रीय विद्युत योजना ने कुल अन्तर-क्षेत्रीय संचरण क्षमता 14,100 एम.डब्ल्यू आकलित की थी और जिसे 11वीं योजना में 23,600 एम. डब्ल्यू. वृद्धि नियोजित कर अंतर-क्षेत्रीय संचरण क्षमता को 37,700 एम.डब्ल्यू. तक ले जाने की योजना थी।

संचरण नेटवर्क एवं इनकी वृद्धि

2.12 बोर्ड की संचरण नेटवर्क 2007-08 के प्रारम्भ में 19 ग्रि.उ.के. में 2,088 एम.वी.ए. रूपांतरण क्षमता एवं 2,122 (सी.के.एम.) की संचरण लाईनें सम्मिलित थी। संचरण नेटवर्क मार्च 2012 के अन्त तक बढ़कर 29 ग्रि.उ.के. जिसकी रूपांतरण क्षमता 3,268 एम.वी.ए. तथा 2,524 सी.के.एम. संचरण लाईन हुई।

अंतर्राज्यीय संचरण प्रणाली के नियोजन एवं विकास और विद्यमान नेटवर्क के रख-रखाव की जिम्मेदारी बोर्ड की है। नियोजना क्षमता वृद्धि के लिए मांग का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त्त है।

विद्यमान नेटवर्क के रख-रखाव तथा संरचण नेटवर्क में अभिवृद्धि हेतु, बोर्ड ने 23 नए ग्रि.उ.के. का निर्माण (क्षमता 3,900 एम.वी.ए.), 480 एम.वी.ए. तथा इसके अनुषंगी संचरण लाईनों (2,495 सी.के.एम.) का संवर्धन एवं 10 चालू ग्रि.उ.के. (1,060 एम.वी.ए.) एवं अनुषंगी संरचण लाईनों (870 सी.के.एम.) के पूर्ण करने हेतु ग्यारवीं योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के लिए एक कार्य योजना बनायी (अक्टूबर 2006)। योजना का वित्तीय परिव्यय ₹ 2,073 करोड़ का था। तदनन्तर, भविष्य की संचरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 12 अतिरिक्त ग्रि.उ.के. (क्षमता 3,650 एम.वी.ए.) का निर्माण, 510 एम.वी.ए. एवं उसके अनुषंगी संचरण लाईनों (3,224 सी.के.एम.) का संवर्धन अनुमोदित किया गया (नवम्बर 2008) ताकि उर्जा उत्पादकों से उर्जा निष्कर्षण हो और वित्तीय परिव्यय राज्यीय योजना के अन्तर्गत ₹ 5,818.52 करोड़, ₹ 406 करोड़ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) से वित्त पोषित सहित पुनरीक्षित किया गया। यद्यपि, वार्षिक योजनाएँ (2007-12) ₹ 5,687.99 करोड़ की बनाई गईं थी। बोर्ड ने 2011-12 के दौरान, ₹ 587.60 करोड़ की अनुमानित लागत पर तीन अतिरिक्त ग्रि.उ.के. (क्षमता 1,230 एम.वी.ए.) तथा उसके अनुषंगी संचरण लाइन (246 सी.के.एम.) के निर्माण की योजना बनाई। योजना अवधि के दौरान अपने व्ययों को पूरा करने के लिए बोर्ड के पास कोई आन्तरिक संसाधन नहीं थे, और वह आर.ई.सी. एवं झारखण्ड सरकार से मिलने वाली निधि पर निर्भर था।

2007-08 से 2011-12 तक अतिरिक्त उच्च विभव (ई.एच.टी.) स्तर पर बोर्ड की संचरण क्षमता का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

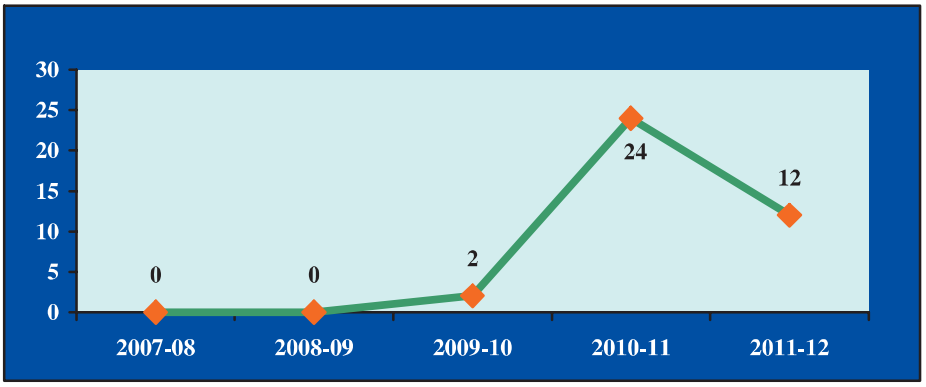
क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
ए. उप-केन्द्रों की संख्या (संख्या)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	19	21	25	29	29	19
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि	2	4	6	24	12	48[12]
3	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	2	4	4	0	0	10
4	वर्ष के अंत में कुल उप-केन्द्र (1+3)	21	25	29	29	29	29
5	अभिवृद्धि में कमी (2-3)	0	0	2	24	12	38
बी. रूपान्तरण क्षमता (एम.वी.ए.)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में क्षमता	2088	2488	2878	3248	3258	2088
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि/संवर्द्धन	400	390	770	4340	4450	10350
3	वर्ष के दौरान क्षमता अभिवृद्धि	400	390	370	10	10	1180
4	वर्ष के अंत में कुल क्षमता (1+3)	2488	2878	3248	3258	3268	3268
5	अभिवृद्धि/संवर्द्धन में कमी	0	0	400	4330	4440	9170
सी. संचरण लाईनें (सी.के.एम.)							
1	वर्ष के प्रारम्भ में क्षमता	2122	2335	2384	2384	2524	2122
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि/संवर्द्धन	213	135	537	3800	2150	6835
3	वर्ष के दौरान क्षमता अभिवृद्धि	213	49	0	140	0	402
4	वर्ष के अंत में कुल क्षमता (1+3)	2335	2384	2384	2524	2524	2524
5	वृद्धि/संवर्धन में कमी	0	86	537	3660	2150	6433

(स्रोत : बोर्ड के अभिलेखों से संकलित)

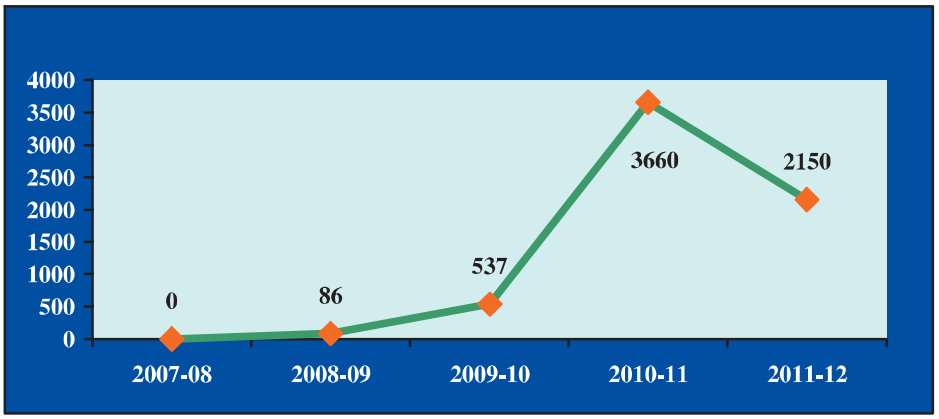
[12] ग्यारहवीं योजना काल में अग्रेषित किया गया दस चालू ग्रि.उ.के. सहित।

2007-08 से 2011-12 की अवधि में 10,350 एम.वी.ए. क्षमता सहित 48 ग्रि.उ.के. के अभिवृद्धि एवं 6,835 सी.के.एम. की संचरण लाईनों को बिछाने के लक्ष्य के विपरीत, बोर्ड ने 1,180 एम.वी.ए. की रूपातंरण क्षमताओं एवं 402 सी.के.एम. की संचरण लाईनों सहित मात्र दस ग्रि.उ.के. की निर्माण/संवर्धन पूर्ण कर सकी। दस निर्मित ग्रि.उ.के. में से तीन ग्रि.उ.के. कांके, लातेहार एवं डालटेनगंज प्रत्येक की रूपांतरण क्षमता 100 एम.वी.ए. को नवम्बर 2012 तक अनुषंगी संचरण लाईनों[13] के पूर्ण नहीं होने के कारण 35 से 61 माह तक ऊर्जान्वित नहीं किया गया।

रेखा चित्रः संख्या में ग्रिड उप-केन्द्रों की अभिवृद्धि में कमी



रेखा चित्रः परिपथ किलोमीटर में लाइनों की अभिवृद्धि/संवर्धन में कमी



2007-08 से 2011-12 की अवधि में वोल्टेजवार नियोजित क्षमता अभिवृद्धि, वास्तविक अभिवृद्धि क्षमता में कमी इत्यादि का विवरण, ***परिशिष्ट-8*** में दिया गया है। क्षमता अभिवृद्धि में कमी के मुख्य कारण बोर्ड एवं झारखण्ड सरकार की निर्णयहीनता एवं निधिओं की अनुपलब्धता थी जैसा कि निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैः

[13] 132 के.वी. हटिया-काँके, लोहरदगा-लातेहार, लातेहार-डाल्टेनगंज तथा डाल्टेनगंज-जपला।

2007-08 से 2011-12 के दौरान संचरण परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना, आर.ई.सी. एवं झारखण्ड सरकार से निधियों की प्राप्ति तथा उनके विरूद्ध वास्तविक खर्चों का ब्योरा निम्न तालिका में दिये गये है:

(₹ *करोड़ में*)

वर्ष	कार्यक्रम का अनुमानित मूल्य	ग्रिड उपकेन्द्रों /संचरण लाईनों की संख्या (सी0के0 एम0)	प्रारम्भिक शेष	झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	प्राप्त निधि		कुल निधि की प्राप्ति	वास्तविक खर्च	अन्तिम शेष
					आर.ई.सी.	झारखण्ड सरकार			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	(4+8-9)=10
2007-08	260.19	2/213	6.86	-	197.99	-	197.99	79.49	125.36
2008-09	433.60	4/135	125.36	-	30.73	-	30.73	155.76	0.33
2009-10	2933.11	6/537	0.33	90.77	104.83	-	104.83	31.66	73.50
2010-11	1735.54	24/3800	73.50	338.50	52.00	75.00	127.00	51.89	148.61
2011-12	913.15	12/2150	148.61	150.00	-	2.69	2.69	61.80	89.50
कुल	**6275.59**	**48/6835**		**579.27**	**385.55**	**77.69**	**463.24**	**380.60**	

(स्रोत : बोर्ड द्वारा दिये गये आँकड़े)

हमने यह पाया कि 2007-08 से 2011-12 के दौरान, परियोजित कार्य के अनुसार ₹ 6,275.59 करोड़ की आवश्यकता के विरूद्ध झारखण्ड सरकार ने ₹ 579.27 करोड़ स्वीकृत किया तथा ₹ 77.69 करोड़ विरमित की। उपर्युक्त अवधि के दौरान, आर.ई.सी. ने ₹ 385.55 करोड़ विरमित किया। बोर्ड इस राशि का उपयोग करने में असमर्थ रहा और 31 मार्च 2012 को अव्यय राशि ₹ 89.50 करोड़ था। इस प्रकार, 2007-08 से 2011-12 की अवधि में ₹ 6,275.59 करोड़ की आवश्यकता में से बोर्ड ने मात्र ₹ 463.24 करोड़ पाया जिसमें से मात्र ₹ 380.60 करोड़ ही उपयोग कर सका। इसके परिणामतः संचरण नेटवर्क में नियोजित अभिवृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाया, जैसा कि निम्न कंडिकाओं में विवेचित है।

❖ *ग्यारहवीं योजना काल में पूर्ण होने वाले नियोजित चालू परियोजनाओं की स्थिति*

जैसा की कंडिका 2.12 में उल्लेखित है, बोर्ड ग्यारहवीं योजना काल (2007-2012) में 10 चालू ग्रि.उ.के. तथा अनुषंगी संचरण लाईनों को पूर्ण करने हेतु नियोजित किया। इनमें से, आठ[14] ग्रि.उ.के., छः[15] संचरण लाईनें तथा रिहन्द-सोन नगर में एक लाईन आगत-लाईन निर्गत (एल.आई.एल.ओ.) का निर्माण आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये ऋणों से करना था तथा दो[16] ग्रिड उपकेन्द्रों एवं चार[17] संचरण लाईनों को झारखण्ड सरकार से प्राप्त ऋण से करना था।

हमने प्रेक्षित किया कि दोनों ग्रिड उपकेन्द्रों तथा चार संचरण लाईनों का नियोजन जो झारखण्ड सरकार के ऋण से नियोजित थे, पूर्ण हो गये थे।

---

[14] 220/132 के.वी. ग्रि.उ.के. हटिया में तथा 132/33 के.वी. ग्रि.उ.के., लोहरदगा, लातेहार, जपला, काँके, पाकुड़, साहेबगंज और डाल्टेनगंज में।

[15] 220 के.वी. हटिया-लोहरदगा, लोहरदगा-लातेहार, लातेहार-डाल्टेनगंज एवं डाल्टेनगंज-गढ़वा, 132 के.वी. हटिया-काँके और गढ़वा-जपला मे।

[16] चक्रधरपुर एवं दुमका।

[17] देवघर-दुमका, दुमका-लालमटिया, लालमटिया-साहेबगंज और दुमका-पाकुड़।

हमने पुनः प्रेक्षित किया कि आर.ई.सी. से प्राप्त ₹ 385.55 करोड़ ऋण में सेः

- ❖ सभी आठ नियोजित ग्रि.उ.के. पूर्ण हुए।
- ❖ निर्माण हेतु छः नियोजित संचरण लाईनों में से एक संचरण लाईन (हटिया-लोहरदगा) पूर्ण हुआ। रिहन्द-सोननगर में लाईन आगत-लाईन निर्गत (एल.आई.एल.ओ.) भी पूर्ण हुआ।
- ❖ दो[18] संचरण लाईनों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था (नवम्बर 2012) ।
- ❖ ऋणों की स्वीकृति की तिथि से 59 माह विलम्ब के पश्चात शेष तीन[19] संचरण लाईनों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) दिसम्बर 2011 में निर्गत की गई। फिर भी निविदा अंतिमीकृत नहीं हो पायी (जुलाई 2012)।

ग्यारहवीं योजना के दौरान पाँच संचरण लाइन अपूर्ण होने के कारण उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई।

इस प्रकार ग्यारहवीं योजनाकाल के दौरान पूर्ण हेतु नियोजित 10 ग्रि.उ.के., 10 संचरण लाईनों तथा एक लाईन आगत-लाईन निर्गत (एल.आई.एल.ओ.) में से पाँच संचरण लाईनें मार्च 2012 तक पूर्ण नहीं की जा सकी। इन लाईनों के पूर्ण नहीं होने से उपभोक्ताओं को किये जाने वाली विद्युत आपूर्त्ति की गुणवत्ता प्रभावित होगी, चूँकि इनके नतीजतन कम वोल्टेज तथा अस्थायी विद्युत आपूर्त्ति होगी जैसा कि बाद के कंडिका 2.14.1 तथा 2.14.3 में विवेचित है।

❖ *ग्यारहवीं योजनाकाल में पूर्ण हेतु नियोजित नये परियोजनाओं की स्थिति*

वर्तमान नेटवर्क के रख-रखाव एवं संचरण नेटवर्क में अभिवृद्धि हेतु, बोर्ड ने 23[20] नए ग्रि.उ.के. तथा इसके अनुषंगी संचरण लाईनों, जो झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित थे, के निर्माण हेतु ग्यारहवीं योजना काल (2007-08 से 2011-12) में एक योजना बनाया (अक्टूबर 2006)। इसके पश्चात 12[21] अतिरिक्त ग्रि.उ.के. तथा उनके अनुषंगी संचरण लाईनों का निर्माण अनुमोदित किया (नवम्बर 2008)। बोर्ड ने 2011-12 में, पुनः तीन[22] अतिरिक्त ग्रि.उ.के. तथा अनुषंगी संचरण लाईनों के निर्माण हेतु योजना बनायी। तथापि, योजना काल में खर्चो की पूर्त्ति हेतु बोर्ड के पास आन्तरिक संसाधनों का अभाव था और बोर्ड आर.ई.सी. एवं झारखण्ड सरकार से प्राप्त निधियों पर निर्भर था।

---

[18] लोहरदगा-लातेहार एवं लातेहार-डाल्टेनगंज।

[19] हटिया-काँके, डाल्टेनगंज-गढ़वा और गढ़वा-जपला।

[20] 400/220 के.वी. ग्रि.उ.के. - पतरातू, चान्डील; 220/132 के.वी. ग्रि.उ.के. - दुमका, चाईबासा, गोबिन्दपुर; 132/33 के.वी. चाईबासा, गोबिन्दपुर, मधुपुर, सिमडेगा, मानगो, रामचन्द्रपुर, खूँटी, बुण्डू, गिरिडीह, रामगढ़, रातू रोड, गोड्डा, हजारीबाग, चाईबासा, चतरा, गोबिन्दपुस-II ,गढ़वा एवं मनोहरपुर।

[21] 400/220 के.वी. ग्रि.उ.के. - चाईबासा, जसीडीह, तोरपा; 220/132 के.वी. ग्रि.उ.के.- हजारीबाग, जसीडीह, चतरा , शिकारीपाड़ा; 132/33 के.वी. ग्रि.उ.के. - हजारीबाग, चतरा, चक्रधरपुर ,जामा एवं आम्रापाड़ा।

[22] 400/220 के.वी. ग्रि.उ.के. लातेहार में, 220/132 के.वी. ग्रि.उ.के. लातेहार एवं लोहरदगा में।

हमने प्रेक्षित किया कि:

- आर.ई.सी. ने ₹ 984.87 करोड़ का ऋण, दस[23] ग्रि.उ.के. तथा उसकी अनुषंगी संचरण लाईनों के निर्माण हेतु इस शर्त के साथ स्वीकृत किया (फरवरी 2009) कि झारखण्ड सरकार द्वारा ऋण की अदायगी की गारन्टी बिना शर्त्त देना होगा।

- बोर्ड (मार्च 2009) तथा उर्जा विभाग (जुलाई 2010) आर.ई.सी. द्वारा किये गये शर्त्तो पर सहमत हुए, परंतु वित्त विभाग बिना शर्त गारन्टी के उपलब्ध करने से सहमत नहीं था (अगस्त 2010 तथा मार्च 2011), चूँकि बोर्ड की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी।

- बोर्ड तथा उर्जा विभाग ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) को नामांकन के आधार पर कार्य देने को प्रस्ताव किया (दिसम्बर 2010)। तथापि, वित्त विभाग का यह दृष्टिकोण था (मार्च 2011) कि बोर्ड को नामाकंन आधार पर कार्य सौंपने के बजाय निविदा प्रक्रिया में जाना चाहिए।

- इसी बीच में, उन क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क उपलब्ध नहीं था वहाँ संचरण नेटवर्क अत्यावश्यकता के कारण, झारखण्ड सरकार ने राज्य योजना के अन्तर्गत दो[24] ग्रि.उ.के. तथा इसके अनुषंगी संचरण लाईनों के निर्माण की स्वीकृति दी (अक्टूबर 2009 तथा मार्च 2010)। इनमें से, प्रारम्भ में आर.ई.सी. ऋण के अंतर्गत सिमडेगा में एक ग्रि.उ.के. का कार्य निष्पादन किया जाना प्रस्तावित था। बाद में (सितम्बर 2011) झारखण्ड सरकार ने तीन[25] अतिरिक्त ग्रि.उ.के. तथा अनुषंगी संचरण लाईनों को आर.ई.सी. द्वारा किए वित्त पोषण में शामिल किया।

- झारखण्ड सरकार ने आर.ई.सी. के द्वारा 12 ग्रि.उ.के. तथा उनके अनुषंगी संचरण लाईनों, जो आर.ई.सी. द्वारा वित्त पोषित थे, के निर्माण हेतु पी.जी. सी.आई.एल. को नामांकन के आधार पर नियुक्ति हेतु तकनीकि अनुमोदन (जनवरी 2012) तथा प्रशासनिक अनुमोदन (जुलाई 2012) की स्वीकृति दी।

- झारखण्ड सरकार ने राज्य योजना से ₹ 147 करोड़ विमोचित किया (सितम्बर 2012) तथा आर.ई.सी. से स्वीकृत राशि ₹ 984.87 करोड़ ऋण के रूप में राज्य सरकार को विमोचन हेतु आग्रह किया गया।

अतः, ग्यारहवीं योजना काल में नियोजित 14 ग्रि.उ.के., तथा अनुषंगी संचरण लाईनों, जी.ओ.जे./आर.ई.सी. वित्त पोषित को समय-समय पर योजना में हुए परिवर्त्तनों के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। शेष 24 ग्रि.उ.के. तथा अनुषंगी संचरण लाइनों का जिनको ग्यारहवीं योजना काल में पूर्ण करना था, के संदर्भ में विस्तृत परियोजना

[23] 220/132 के.वी. ग्रि.उ.के. गोबिन्दपुर , चाईबासा और दुमका में, 132/33 के.वी. ग्रि.उ.के. मनोहरपुर, सिमडेगा, मानगो, रामचन्द्रपुर, मधुपुर, गोबिन्दपुर और चाईबासा में।

[24] सिमडेगा और चतरा।

[25] 400/220 के.वी. ग्रि.उ.के.लातेहार में, 220/132 के.वी. ग्रि.उ.के. लातेहार और लोहरदगा में।

प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) एवं क्रियान्वयन से संबंधित अन्य कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है (नवम्बर 2012)।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (जनवरी 2013) और कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष पद मे बार-बार परिवर्त्तनों के कारण परियोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। पी.जी.सी.आई.एल. को सुपुर्द कार्य अब बारहवीं योजना में नियोजित है। पी.जी.सी.आई.एल., ग्रि.उ.के. तथा संचरण लाइनों के लिए निविदा आमंत्रित किया है।

संचरण प्रणाली का परियोजना प्रबन्धन

2.13 एक संचरण परियोजना में अवधारणा से चालू होने तक की विभिन्न गतिविधियाँ सम्मिलित होती है। एक संचरण परियोजना में मुख्य गतिविधियाँ हैं (1) परियोजना सूत्रीकरण, मूल्यांकन तथा अनुमोदन अवस्था तथा (2) परियोजना क्रियान्वयन अवस्था। उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने परियोजना क्रियान्वयन अवधि को कम करने के लिए संचरण परियोजनाओं पर एक कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन (फरवरी 2005) इस दृष्टिकोण से किया कि:

- ❖ संचरण परियोजना क्रियान्वयन के विवेचनात्मक तत्वों का विश्लेषण,
- ❖ संचरण परियोजनाओं में देरी को कम करने के उपाय की अनुशंसा,
- ❖ सी.टी.यू. और एस.टी.यू. में प्रचलित उत्तम चलन के अनुसार क्रियान्वयन, एवं
- ❖ 24 माह की अवधि के लिए एक आदर्श संचरण परियोजना अनुसूची का सुझाव

कार्य बल ने संचरण प्रणालियों को पूर्ण करने में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्यवाहियों का सुझाव एवं अनुशंसा दी (जुलाई 2005):

- ❖ परियोजना मूल्यांकन तथा अनुमोदन अवस्था के पहले/समानान्तर विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियाँ जैसे सर्वेक्षण, अभिकल्पना और परीक्षण, वन एवं अन्य सांविधिक अनुमति के लिए कार्यवाही, निविदा गतिविधियों इत्यादि के लिए कदम उठाना तथा संचरण लाइन परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन की प्राप्ति पर निर्माण गतिविधियों के साथ आगे बढ़ना;
- ❖ संचरण परियोजनाओं को स्पष्ट परिभाषित पैकेजों में बांटना, ताकि कम से कम तालमेल एवं अंतरापृष्ठीयता के साथ पैकेजों के लिए अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन किया जा सके और साथ ही कुशल अधिप्राप्ति मूल्य के लिए प्रतिस्पर्धा आहुत करने में सुविधा आकर्षित हो; और
- ❖ टावर संरचना का मानकीकृत डिजाइन किया जाना, ताकि परियोजना क्रियान्वयन में 6-12 माह का बचत किया जा सके।

2.14 हमने देखा कि बोर्ड ने कार्य बल की अनुशंसाओं का पालन नही किया, जो परियोजनाओं के समय पर पूर्ण करने में सहायक होते। यह विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियों, जैसे कि सर्वेक्षण, अभिकल्पना और परीक्षण, वन एवं अन्य सांविधिक अनुमति हेतु कार्यवाही, निविदा गतिविधियाँ इत्यादि को करने में विफल रहा, जो कि परियोजना मूल्यांकन तथा अनुमोदन अवस्था के पूर्व समय पर परियोजना की पूर्णता के लिए आवश्यक था, जैसा कि कार्य बल समिति ने अनुशंसित किया था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि संचरण परियोजनाओं को पैकेजों में बाँटा गया, बोर्ड ने निविदा को समय पर अंतिम रूप नहीं कर पाया जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में असमान्य देरी हुई। इस प्रकार, कार्य बल समिति की समय पर परियोजना पूर्ण करने के विस्तृत दिशा निर्देशों के होते हुए भी, बोर्ड ग्रिड उप-केन्द्रों तथा अनुषंगी संचरण लाइनों को पूर्ण करने के अनुसूचित समय का पालन नहीं किया जिसके परिणास्वरूप समय आधिक्य हुआ जैसा कि निम्न तालिका में विस्तृत विवरण हैः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रदत्त लागत (₹ करोड़)/ एल.ओ.आई. माह	समाप्ति की निर्धारित तिथि (माह)	समाप्ति की वास्तविक तिथि (माह)	समय आधिक्य (माह)	कारण
1	दुमका में 132/33 के.वी. ग्रि.उ.के. तथा 132 के.वी. देवघर-दुमका संचरण लाइन (पैकेज ए)	35.89 दिसम्बर 2004	जून 2006	जनवरी 2009 (ग्रि.उ.के.) तथा सितम्बर 2010 (संचरण लाइन)	31 (ग्रि.उ.के.) 51 (संचरण लाइन)	वन अनुमति, रेलवे अनुमति, मार्ग का अधिकार मुद्दा तथा भुगतान में विलम्ब
	दुमका-लालमटिया एवं लालमटिया-साहेबगंज संचरण लाइन (पैकेज बी)	58.49 दिसम्बर 2004	जून 2006	जून 2007 दिसम्बर 2008	12 30	
	दुमका-पाकुड़ संचरण लाइन (पैकेज सी)	19.39 अप्रैल 2005	अक्टूबर 2006	जनवरी 2011	51	
2	डाल्टेनगंज एवं जपला में ग्रि.उ.के.	32.06 अगस्त 2005	फरवरी 2007	अक्टूबर 2007 (डाल्टेनगंज) सितम्बर 2008 (जपला)	8 (डाल्टेनगंज) 19 (जपला)	रेखाचित्रों तथा मात्रा परिवर्तन सुधार का अनुमोदन, , प्रेषण निर्देश तथा रोड परमिट, सामग्री के निरीक्षण तथा भुगतान करने में विलंब
3	220 के.वी. लोहरदगा-लातेहार (पैकेज ए) तथा लातेहार-डाल्टेनगंज (पैकेज बी) संचरण लाइन	34.06 (पैकेज ए) 34.80 (पैकेज बी) मई 2008	नवम्बर 2009	पूर्ण नहीं (नवम्बर 2012 तक)	36	वन एवं रेलवे पारगमन की अनुमति मे विलम्ब
4	लोहरदगा, लातेहार (पैकेज ए) पाकुड़, साहेबगंज और कॉके (पैकेज बी) में ग्रि.उ.के.	45.51 (पैकेज ए) 69.74 (पैकेज बी) सितम्बर 2006	मार्च 2008	नवम्बर 2008 (लोहरदगा), जनवरी 2009 (लातेहार), दिसम्बर 2009 (पैकेज बी)	8 (लोहरदगा) 10 (लातेहार) 21 (पैकेज बी)	भूमि अधिग्रहण, रेखाचित्रों के अनुमोदन, मात्रा में परिवर्तन, प्रेषण निर्देशों के निर्गमन एवं रोड परमिट, सामग्री के निरीक्षण तथा भुगतान करने में विलंब
5	सिमडेगा में ग्रि.उ.के. तथा सिमडेगा-गुमला एवं लोहरदगा-गुमला संचरण लाइन	101.35 फरवरी 2009	अगस्त 2010	पूर्ण नहीं (नवम्बर 2012 तक)	27	भूमि अधिग्रहण , वन एवं रेलवे पारगमन की अनुमति में विलंब।
6	चतरा में ग्रि.उ.के. तथा चतरा-लातेहार एवं पी.टी.पी.एस.-चतरा संचरण लाइन	कार्य प्रदान नहीं हुआ	-	-	-	-

(स्रोत :- बोर्ड के अभिलेखों से संकलित)

उपर्युक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित हुआ, निम्न हैः-

2.14.1 दुमका में ग्रि.उ.के., देवघर-दुमका, दुमका-लालमटिया, लालमटिया-साहेबगंज और दुमका-पाकुड़ संचरण लाइन।

देवघर ग्रि.उ.के. से संचरण नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण बोर्ड, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों को 33 के.वी. लाइन से क्रमशः डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी. से उर्जा क्रय कर और लालमटिया ग्रि.उ.के. से उर्जा आपूर्त्ति कर रहा था। इसके कारण कम वोल्टेज तथा अस्थिर विद्युत आपूर्त्ति हुई, इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों[26] से खरीदी गई उर्जा के औसत लागत से अधिक लागत पर डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी. से उर्जा की क्रय की गई। इसलिए, बोर्ड ने दुमका में ग्रि.उ.के. तथा देवघर-दुमका, दुमका-लालमटिया, लालमटिया-साहेबगंज और दुमका-पाकुड़ संचरण लाइनों के निर्माण के लिए निश्चय पत्र (एल.ओ.आई.) निर्गत किया (दिसम्बर 2004/अप्रैल 2005)।

सांविधिक अनुमतियाँ लेने की प्रक्रिया शुरू करने में चार से 54 माह के विलंब के कारण संचरण लाइनें 12 से 51 माह के विलंब के पश्चात पूर्ण हुये।

हमने यह अवलोकित किया कि बोर्ड ने निश्चय पत्र (एल.ओ.आई.) के निर्गत होने के चार से 54 माह के विलम्ब के उपरांत सांविधिक अनुमतियाँ लेने की प्रक्रिया शुरू की। सभी संचरण लाइन 12 से 51 माह के विलम्ब से पूर्ण हुए। हमने यह भी देखा कि वन विभाग ने परियोजना में प्रयोग में आने वाले वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा अनुपूरक वनरोपन योजना से संबंधित दुमका-पाकुड़ संचरण लाइन के लिए ₹ 76.05 लाख का दावा किया (नवम्बर 2008)। बोर्ड द्वारा अप्रैल 2010 में किये गये भुगतान तक इस लाइन पर नवम्बर 2008 से अप्रैल 2010 के मध्य 16 माह तक कोई कार्य नहीं हो सका। बोर्ड ने वन विभाग की अनुमति की प्रत्याशा में लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ की और अन्ततः यह कार्य वन विभाग की अनुमति के बिना पूर्ण हुआ (जनवरी 2011)।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा कहा कि परियोजना राज्य योजना के अंतर्गत वित्त पोषित करना था, परन्तु निधि प्रवाह में कमी थी, बोर्ड ने अपने निधि में से राशि का भुगतान किया।

तथ्य यह रह जाता है कि झारखण्ड सरकार को समर्पित आकलन में बोर्ड ने वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने में भुगतेय राशि का कोई प्रावधान नहीं किया था। वन विभाग से मांग की प्राप्ति के उपरान्त 12 माह का विचारणीय समय झारखण्ड सरकार से निधि के लिए आग्रह करने में लगा (नवम्बर 2009)।

[26] दामोदर घाटी निगम, राष्ट्रीय वाष्प शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा पावर ट्रेडिंग निगम लिमिटेड।

2.14.2 डाल्टेनगंज और जपला में ग्रिड उप-केन्द्र

डाल्टेनगंज प्रमंडल तथा जपला अनुमंडल को ऊर्जा की आपूर्ति 33 के.वी. लाइन के माध्यम से दूर स्थित ग्रि.उ.के. क्रमशः गढ़वा रोड तथा सोननगर (बिहार) से किया जाता था, जिस कारण अपर्याप्त तथा बारम्बार अवरोधों के साथ अस्थिर विद्युत आपूर्त्ति हुई। अतः, बोर्ड ने डाल्टेनगंज और जपला में ग्रि.उ.के. के निर्माण हेतु निश्चय पत्र (एल.ओ.आई.) निर्गत किया (अगस्त 2005)।

हमने अवलोकित किया कि कार्यप्रवृत अग्रिम एवं चलन्त खाता भुगतान करने, रेखाचित्रों का अनुमोदन, आदेश के मात्राओं में संशोधन, प्रेषण निर्देशों और रोड परमिट निर्गत करने तथा सामग्री के निरीक्षण इत्यादि में 483 से 663 दिनों का विलम्ब था। डाल्टेनगंज एवं जपला में ग्रि.उ.के. का निर्माण अक्टूबर 2007 तथा सितम्बर 2008 में क्रमशः आठ और 19 माह के समय आधिक्य के उपरान्त पूर्ण हुआ। बोर्ड ने डाल्टेनगंज तथा जपला ग्रि.उ.के. के निर्माण के लिए ₹ 22.02 करोड़ का भुगतान किया (मई 2012)। यद्यपि जपला में ग्रि.उ.के. को ऊर्जान्वित किया गया परन्तु लातेहार-डाल्टेनगंज तथा डाल्टेनगंज-गढ़वा संचरण लाइनों के पूर्ण नहीं होने के कारण डाल्टेनगंज का ग्रि.उ.के. पूर्ण होने की तिथि से 61 माह तक ऊर्जान्वित नहीं किया गया (नवम्बर 2012)।

डाल्टेनगंज ग्रि.उ.के. के उर्जान्वित न होने से ₹ 11.01 करोड़ अवरूद्ध।

अतः, ग्रि.उ.के. को आवेशित नहीं करने से योजना का उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी और ऊर्जा की आपूर्त्ति दूर स्थित ग्रि.उ.के. से होती रही, जिसके परिणामस्वरूप डाल्टेनगंज में अस्थिर आपूर्त्ति तथा ₹ 11.01 करोड़[27] अवरूद्ध हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) और कहा कि डाल्टेनगंज स्थित ग्रि.उ.के. को शीघ्र ही आवेशित कर दिया जाएगा।

2.14.3 लोहरदगा - लातेहार और लातेहार - डाल्टेनगंज संचरण लाइन

संचरण लाइन के निर्माण के लिए एक निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) जनवरी 2005 में निर्गत की गई तथा एल.ओ.आई. न्यूनतम निविदाकर्त्ता रामजी पावर कन्सट्रक्शन लिमिटेड (आर.पी.सी.एल.) को निर्गत किया गया (जुलाई 2005)। तथापि, बोर्ड ने अपने 38वीं बोर्ड बैठक में कार्यादेश निर्गत नहीं करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2005), क्योंकि ठेकेदार ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों में ₹ 19.70 करोड़ का जाली बैंक गारन्टी (बी.जी.) जमा किया था। बाद में, 2005-06 के दौरान निर्गत एक एन.आई.टी. को पर्याप्त संख्या में निविदाकर्त्ताओं के भाग न लेने के कारण रद्द किया गया। बोर्ड ने पुनः एक एन.आई.टी. निर्गत किया (अक्टूबर 2006) जिसमें आई.वी.आर.सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड (आई.वी.आर.सी.एल.) न्यूनतम निविदाकर्त्ता था। हमने अवलोकित किया कि बोर्ड ने कार्य बल के अनुशंसाओं का पालन नहीं किया तथा वन विभाग की अनुमति (मई 2009) तथा रेलवे पारगमन की अनुमति लेने की शुरूआत (जुलाई 2010), एल.ओ.आई. निर्गत करने की तिथि (मई 2008) से क्रमशः 12 तथा 26 माह के पश्चात किया गया। रेलवे पारगमन के लिए अनुमति दिसम्बर 2010 में प्रदान किया गया। यद्यपि वन विभाग की अनुमति अभी भी

सांविधिक अनुमतियाँ लेने की प्रक्रिया शुरू करने में 12 से 26 माह के विलंब के कारण संचरण लाइनों का कार्य पूरा नहीं हो सका (नवम्बर 2012)।

[27] ₹ 22.02 करोड़ (दो ग्रि.उ.के. के लिये)/ 2 = ₹ 11.01 करोड़ एक ग्रि.उ.के.के लिए।

प्रतिक्षित था (मई 2012)। इस प्रकार, कार्य पूरा नहीं हुआ था तथा पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (नवम्बर 2012) से 36 माह के बाद भी उपभोक्ताओं को निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण उर्जा नहीं मिल पाया था।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2013) कि वन तथा रेलवे अनुमतियाँ लेने के प्रस्तावों में अत्यधिक प्रलेखनों जैसे कि मार्ग का सर्वेक्षण जाँच, मार्ग निर्धारण, वृक्ष गणना इत्यादि की जरूरत होती है।

प्रत्योत्तर, विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियों जैसे कि सर्वेक्षण तथा वन एवं अन्य सांविधिक अनुमति लेने की प्रक्रिया, परियोजना मूल्यांकन तथा अनुमोदन अवस्था के अग्रिम/समान्तर करने के संबंध में कार्य बल की अनुसंशाओं पर विचार नहीं करने के विषय में मौन है।

2.14.4 लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज तथा काँके में ग्रि.उ.के.

लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ तथा साहेबगंज को ऊर्जा की आपूर्ति दूर स्थित 33 के.वी. लाइन से क्रमशः डाल्टेनगंज ऊर्जा उप-केन्द्र (पी.एस.एस.), मांडर पी.एस.एस. तथा पाकुड़ के सीमा में स्थित धुलियान (डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी.) ग्रि.उ.के. तथा लालमटिया से किया गया परिणामस्वरूप, बारम्बार व्यवधानों के साथ अपर्याप्त एवं अस्थिर विद्युत आपूर्त्ति होती रही। राँची में विद्यमान 132/33 के.वी. ग्रि.उ.के. कांके की पूरी विद्युत आवश्यकता को संभालने में असमर्थ था। अतः, बोर्ड ने लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज और काँके में ग्रि.उ.के. के निर्माण हेतु निश्चय पत्र निर्गत किया (सितम्बर 2006)।

हमने अवलोकित किया कि बोर्ड ने परियोजना को पूर्ण करने में तीव्रता लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए कार्य बल द्वारा सुझाए गए अनुशंसाओं का अनुपालन नहीं किया तथा उपरोक्त ग्रि.उ.के. के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण, कार्यप्रवृत अग्रिम निर्गत तथा भुगतान करने, नक्शा तथा परिमाण संशोधन अनुमोदन, प्रेषण निर्देश तथा रोड परमिट निर्गत करने एवं सामग्रियों के निरीक्षण में 558 से 1257 दिनों का विलम्ब हुआ। ग्रि.उ.के. निर्माण नियत तिथि (मार्च 2008) से आठ से 21 माह के विलम्ब के पश्चात पूर्ण हुआ। लोहरदगा तथा साहेबगंज में ग्रि.उ.के. को पूर्ण होने के बाद उर्जान्वित किया गया। तथापि, पाकुड़ में ग्रि.उ.के. को दुमका-पाकुड़ संचरण लाइन के विलम्बित निर्माण के कारण निर्माण पूर्ण होने की तिथि (दिसम्बर 2009) से 13 माह के विलम्ब के बाद उर्जान्वित किया गया (जनवरी 2011)। बोर्ड ने उपरोक्त ग्रि.उ.के. के निर्माण के लिए ₹ 93.74 करोड़ का भुगतान किया (मई 2012)। इसके अतिरिक्त, लोहरदगा-लातेहार, लातेहार-डाल्टेनगंज तथा हटिया-काँके संचरण लाइनों के पूर्ण नहीं होने के कारण काँके तथा लातेहार में ग्रि.उ.के. को क्रमशः पूर्ण होने के 35 तथा 46 माह के पश्चात भी उर्जान्वित नहीं किया गया था (नवम्बर 2012)। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उर्जा से वंचित रहना पड़ा तथा ग्रि.उ.के. के लिए संवेदकों को भुगतान की गई ₹ 38.13 करोड़[28] अवरूद्ध रही।

कांके तथा लातेहार में ग्रि.उ.के. के उर्जान्वित नहीं होने के कारण ₹ 38.13 करोड़ अवरूद्ध।

[28] तीन ग्रि.उ.के. के लिए ₹ 52.47 करोड़/3 + 2 ग्रि.उ.के. के लिए ₹ 41.27 करोड़ /2 = ₹ 38.13 करोड़

2.14.5 सिमडेगा में ग्रि.उ.के. तथा सिमडेगा-गुमला एवं लोहरदगा-गुमला संचरण लाईन

सांविधिक अनुमतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने में 12 से 26 माह विलंब के कारण ग्रि.उ.के. तथा संबंधित संचरण लाइन पूर्ण नहीं हो पायी (नवम्बर 2012)।

सिमडेगा में ग्रि.उ.के. नहीं होने के कारण, बोर्ड कामडारा ग्रि.उ.के. से 33 के.वी. पर विद्युत आपूर्ति कर रहा था। बोर्ड ने सिमडेगा में ग्रि.उ.के.तथा संबंधित संचरण लाईन के निर्माण अगस्त 2010 तक पूर्ण करने के लिए जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एल.ओ.आई. निर्गत किया (फरवरी 2009)। हमने अवलोकित किया कि झारखण्ड सरकार ने ₹ 90.77 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया (अक्टूबर 2009) तथा ₹ 40 करोड़ का ऋण निर्गत किया (अगस्त 2010)। बोर्ड ने कार्य बल की अनुशंसाओं का अनुपालन नहीं किया तथा एल.ओ.आई. निर्गत करने की तिथि से क्रमशः 26 तथा 12 माह के विलम्ब से वन विभाग की अनुमति तथा रेलवे पारगमन अनुमति प्राप्त करने के लिए कदम उठाया। जमीन अधिग्रहित की गई (फरवरी 2010) तथा रेलवे क्रासिंग अनुमति भी प्राप्त किया गया (मार्च 2011), जब कि वन विभाग से अनुमति अब भी अपेक्षित था (जून 2012)। ग्रि.उ.के. तथा संबंधित संचरण लाईनों को अभी तक पूर्ण होना बाकी है (नवम्बर 2012)।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा वन एवं रेलवे पारगमन अनुमति प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों में विलंब को स्वीकार किया।

2.14.6 चतरा में ग्रि.उ.के. तथा चतरा-लातेहार एवं पी.टी.पी.एस. - चतरा संचरण लाइन

कार्य के क्रियान्वयन के लिए कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं करने के कारण जून 2012 तक 15 माह के अवधि के लिए झारखण्ड सरकार से प्राप्त ₹ 30 करोड़ ऋण बिना उपयोग के रह गया।

चतरा में ग्रि.उ.के. तथा चतरा-लातेहार एवं पी.टी.पी.एस.-चतरा संचरण लाइनों के निर्माण के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 193.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2010)। हमने अवलोकित किया कि बोर्ड ने झारखण्ड सरकार से ₹ 30 करोड़ का ऋण प्राप्त किया (मार्च 2011) जिसे बोर्ड के वैयक्तिक लेखा खाते में रखा गया तथा जून 2012 तक 15 माह की अवधि तक बिना उपयोग के रहा जिस पर ₹ 4.88 करोड़[29] का ब्याज का दायित्व उपार्जित हो गया था। बोर्ड ने कार्य के कार्यान्वयन के लिए कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं किया (जून 2012)। कार्य के वास्तविक कार्यान्वयन के साथ ऋण की निकासी समक्रमिक होती तो ब्याज दायित्व को टाला जा सकता था।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2013) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है तथा निविदा का मूल्यांकन कार्य प्रगति में है। यद्यपि उत्तर ब्याज दायित्व के विषय में मौन है।

संविदा प्रबन्धन

2.15 बोर्ड द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि में प्रदान की गई अथवा कार्यान्वित की गई निविदाओं की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गई और संविदा शर्त्तो तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन नहीं करने के निम्नलिखित बिन्दुओं को पायाः

[29] 13 प्रतिशत की दर से ₹ 30 करोड़ (जून 2012 तक 15 माह के लिए)।

❖ दुमका-देवघर के लिए 132 के.वी. संचरण लाइन तथा दुमका में ग्रि.उ.के. (पैकेज-ए), दुमका-लालमटिया-साहेबगंज में 132 के.वी. (पैकेज-बी) एवं दुमका-पाकुड़ में 132 के.वी. (पैकेज-सी) संचरण लाइनों के संरचना के लिए एक निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) निर्गत किया गया (अक्टूबर 2003)। निविदा खुलने की नियत तिथि नवम्बर 2003 थी। निविदा शर्त्तों में से एक यह था कि निविदा खोलने की तिथि/निविदा जमा करने की तिथि से एक माह पूर्व में इण्डियन इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स मेनुफेक्चरर्स एशोसिएशन (आई.ई.ई.एम.ए.[30]) के सूचकांक के अनुसार, मूल्य परिवर्तन को आधार तिथि माना जाएगा तथा मोल-तोल के मामले में मोल-तोल तिथि के एक माह पूर्व को आधार तिथि माना जाएगा। पैकेज ए तथा बी के निविदादाताओं के साथ अक्टूबर 2004 तथा पैकेज-सी के निविदादाताओं के साथ दिसम्बर 2004 में मोल-तोल किया गया। मोल-तोल के आधार पर निविदादाताओं द्वारा मूल्य को कम किया गया। तथापि, क्रय आदेश/कार्यादेश (पी.ओ./डब्ल्यू.ओ.) निर्गत करते समय (जनवरी 2005 से मई 2005) बोर्ड ने एन.आई.टी. की शर्त्तों का अनुपालन नहीं किया तथा निविदा की तिथि से एक माह पूर्व को मूल्य परिवर्त्तन के लिए आधार तिथि माना जो गणना करने पर मोल-तोल की तिथि से पैकेज ए तथा बी के लिए 11 माह तथा पैकेज सी के लिए 13 माह पहले होता है। बोर्ड ने मूल्य परिवर्तन के लिए पैकेज ए, बी तथा सी के लिए क्रमशः ₹ 22.70 करोड़, ₹ 4.34 करोड़ तथा ₹ 9.86 करोड़ का भुगतान किया (मई 2012)। बोर्ड द्वारा आई.ई.ई.एम.ए. बुलेटिन की सदस्यता ग्रहण नहीं करने के कारण बोर्ड को आई.ई.ई.एम.ए. मूल्य सूचकांक प्राप्त करने के लिए आपूर्त्तिकर्त्ता पर निर्भर था। हमने मोल-तोल की तिथि से एक माह पूर्व को आधार तिथि मानकर अनुमान्य मूल्य परिवर्तन की संगणना किया तथा यह पाया गया कि बोर्ड द्वारा पैकेज ए, बी एवं सी के लिए क्रमशः ₹ 5.53 करोड़, ₹ 2.26 करोड़ तथा ₹ 2.51 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

बोर्ड ने एन.आई.टी. की शर्त्तों में बदलाव के कारण मूल्य परिवर्तन के लिए ₹ 10.38 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

❖ लोहरदगा तथा लातेहार (पैकेज-ए) तथा पाकुड़ ,साहेबगंज एवं कांके (पैकेज-बी) में 132/33 के.वी. ग्रि.उ.के. के निर्माण के लिए जिसके निविदा खुलने की नियत तिथि (दिसम्बर 2005) थी, न्यूनतम निविदादाता मेसर्स एरीवा टी. एण्ड डी. ने मोल-तोल के पश्चात (जुलाई 2006) पैकेज ए तथा बी के मूल्य से क्रमशः ₹ 77.19 लाख तथा ₹ 22.81 लाख कम किया। बोर्ड ने पैकेज-ए के लिए ₹ 2.12 करोड़ का भुगतान किया (अप्रैल 2012)। हमने मोल-तोल की तिथि से एक माह पूर्व को आधार तिथि मानकर मूल्य परिवर्तन की संगणना किया तथा यह पाया कि बोर्ड द्वारा ₹ 8.34 लाख[31] का अधिक भुगतान किया गया। बोर्ड ने पैकेज बी के मूल्य परिवर्तन के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया था (अप्रैल 2012) अतः आई.ई.ई.एम.ए. सूचकांक का अनुपालन नहीं किए जाने का असर, अगर कोई हो तो, निर्धारणीय नहीं है।

[30] उपयुक्त मासिक कच्चा सामग्री के मूल्य तथा सूचकांक को वितरित करते हुए आई.ई.ई.एम.ए. उचित एवं समान मूल्य परिवर्तन अनुबंध (पी.वी.सी.) को विकसित तथा परिचालित करता है।

[31] मूल्य परिवर्तन की संगणना केवल ₹ 13.15 लाख के भुगतान पर किया गया चूँकि बोर्ड के पास आई.ई.ई.एम.एस. मूल्य सूचकांक इस सीमा तक उपलब्ध था।

सरकार ने जवाब दिया (जनवरी 2013) कि आधार तिथियों में बदलाव बोर्ड की शासी निकाय द्वारा किया गया था।

तथ्य यह रह जाता है कि अनुबंध के शर्त्तों का अनुपालन नहीं करने पर बोर्ड की वित्तीय हित की हानि हुई चूँकि मूल्य बोली की मोल-तोल की तिथि को मूल्य के परिवर्तन निर्धारित करने के लिए आधार तिथि माना जाना चाहिए था।

❖ ₹ 4.68 करोड़ के चलन्त खाता विपत्र के भुगतान में 9-12 माह के विलम्ब के कारण तथा सामग्री जाँच प्रतिवेदन, मात्रा सूची के अनुमोदन में विलम्ब, तथा बोर्ड द्वारा रोड परमिट की व्यवस्था करने, भूमि अधिग्रहण, वन तथा रेलवे अनुमति में विलम्ब के कारण संवेदक आर.पी.सी.एल. द्वारा दुमका में ग्रि.उ.के. तथा 132 के.वी. दुमका-देवघर (पैकेज-ए) तथा दुमका-पाकुड़ (पैकेज-सी) संचरण लाइन का निर्माण कार्य पैकेज-ए के लिए निर्धारित समय (जून 2006) तथा पैकेज-सी के लिए निर्धारित समय (अक्टूबर 2006) में पूर्ण नहीं किया जा सका। आर.पी.सी.एल. द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अभिवेदन दिया गया (जनवरी 2007)। मध्यस्थ द्वारा आर.पी.सी.एल. के पक्ष में निर्णय दिया गया (फरवरी 2008) तथा बोर्ड को क्षतिपूर्त्ति हेतु ₹ 11 करोड़ का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया गया। बोर्ड द्वारा संवेदक को ₹ 11 करोड़ का भुगतान किया गया (मई 2008)। मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) के अनुसार निर्णय की तिथि से चार माह के पश्चात् निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन नहीं दिया जा सकता है। तथापि, बोर्ड ने तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात् सब-जज, राँची के कोर्ट में मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती दिया (जनवरी 2011) जिसके कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं थे।

बोर्ड के द्वारा सामग्री जाँच प्रतिवेदन के अनुमोदन, मात्रा सूची, भूमि अधिग्रहण, वन अनुमति इत्यादि में विलंब के कारण मध्यस्थता हुई जिस पर ₹ 11 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार ने जवाब दिया (जनवरी 2013) कि निर्णय को चुनौती देने का मामला विचारित था, कानूनी सलाह ली गई तथा बोर्ड द्वारा तदनुसार मध्यस्थ के निर्णय को चुनौती देने का निर्णय लिया गया (जनवरी 2011)।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम मे दर्शाए गए चार माह की अवधि के विरूद्ध बोर्ड द्वारा तीन वर्ष के पश्चात निर्णय को चुनौती दिया गया।

दुमका-पाकुड़ लाइन के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी. से विद्युत क्रय पर बोर्ड द्वारा ₹ 53.58 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

इसके अलावा, दुमका में ग्रि.उ.के. तथा दुमका-देवघर एवं दुमका-पाकुड़ में संचरण लाईन के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण बोर्ड को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी. से उच्च दर पर विद्युत क्रय करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप अन्य स्त्रोतों से विद्युत के क्रय लागत की तुलना में ₹ 53.58[32] करोड़ का अधिक व्यय करना पड़ा।

[32] (डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी. से विद्युत क्रय का औसत लागत - डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी. को छोड़कर झा.रा.वि.बो. द्वारा विद्युत क्रय का औसत लागत)। डब्ल्यू.बी.एस.इ.बी. से क्रय की गई कुल इकाई उ (₹ 5.04 - ₹ 2.60)। 219.57 एम.यू.।

- केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी.वी.सी) के दिशानिर्देशों (नवम्बर 2002) के अनुसार प्रस्ताव को तकनीकी तथा वित्तीय रूप से अनुमान्य पाये जाने पर, कार्य को बिना किसी विलम्ब के निर्गत किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि लोहरदगा-लातेहार (पैकेज-ए) तथा लातेहार-डाल्टेनगंज (पैकेज-बी) में 220 के.वी. संचरण लाईन के निर्माण के लिए निविदा खुलने की नियत तिथि नवम्बर 2006 के साथ एन.आई.टी. प्रकाशित की गई। इसके विरूद्ध, बोली के लिए केवल दो निविदाकर्त्ताओं ने भाग लिया। यह देखा गया कि बोर्ड ने एक निविदाकर्त्ता द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी विवरण में त्रुटियों के कारण उस निविदाकर्त्ता को अयोग्य करार देने में नौ माह का समय लगाया (अगस्त 2007)। तथापि एकल निविदाकर्त्ता, आई.वी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस लिमिटेड का वार्तातय (नवम्बर 2007) मूल्य ₹ 34.06 करोड़ तथा ₹ 34.80 करोड़, क्रमशः पैकेज ए एवं बी के अनुमानित मूल्य ₹ 35.48 करोड़ तथा ₹ 35.67 करोड़ से कम था, बोर्ड द्वारा एल.ओ.आई. निर्गत नहीं किया गया तथा इसके स्थान पर निविदाकर्त्ता द्वारा दिये गये दर के औचित्य की तुलना के लिए पी.जी.सी.आई.एल. को लागत अनुमान तैयार करने हेतु आग्रह किया (नवम्बर 2007)। पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा जनवरी 2008 में उद्धत किए गये अनुमानित मूल्य पैकेज ए तथा बी के लिए क्रमशः ₹ 38.54 करोड़ तथा ₹ 36.48 करोड़ था जो वार्तातय मूल्य से अधिक था। अंततः आई.वी.आर.सी.एल. को निविदा खुलने की तारीख से 15 माह के पश्चात एल.ओ.आई. निर्गत किया गया (मई 2008)। अतः, सी.वी.सी. दिशा निर्देशों के उल्लंघन करते हुए, संविदा के आबंटन में अनुचित विलम्ब हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा कहा कि एकल निविदाकर्त्ता होने के कारण उद्धत दर को पी.जी.सी.आई.एल. के दर से तुलना की गई।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि बोर्ड ने निविदाकर्त्ता के दर को पी.जी.सी.आई.एल. की दर से तुलना करने में छः माह का विचारणीय समय लिया।

संचरण प्रणाली का निष्पादन

2.16 बोर्ड का निष्पादन मुख्यतः न्यूनतम अवरोधों के साथ गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्त्ति के लिए संचरण प्रणाली के दक्षतापूर्ण रख-रखाव पर निर्भर करता है। उपकेन्द्रों तथा लाईनों के संचालन के दौरान, अंगीभूत उप-प्रणालियों के अंतर्गत आपूर्त्ति-माँग प्रोफाइल की पहचान की जाती है तथा लाइन क्षति को कम करने के लिए प्रणाली सुधार योजना शुरू किया जाता है तथा वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने के द्वारा उर्जा की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जाता है। ये योजनायें वर्तमान ट्रांसफरमर क्षमता के संवर्धन, अतिरिक्त ट्रांसफरमर की अधिस्थापना, अतिरिक्त लाईनों को लगाने तथा कैपेसिटर बैंकों के अधिष्ठापन के लिए हैं। प्रणाली के परिचालन तथा अनुरक्षण (ओ.एण्ड एम.) को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निष्पादन की चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है।

रूपांतरण क्षमता

2.17 उत्पादन संयंत्रों से उर्जा की निकासी तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए भार को पूरा करने के लिए बोर्ड विभिन्न वोल्टेजों पर लाइन तथा ग्रि.उ.के. का निर्माण करता है। उपकेन्द्र में ट्रांसफरमर काफी उच्च क्षमता के साथ ए.सी. वोल्टेज तथा विद्युत धारा को भिन्न वोल्टेज तथा धारा में परिवर्तित करता है। प्रक्रिया में न्यूनतम हानि के साथ ए.सी. वोल्टेज के बढ़ाने तथा घटाने के लिए वोल्टेज स्तर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उर्जा की निकासी सामान्यतः 220 के.वी. ग्रि.उ.के. से किया जाता है। मार्च 2012 को अंत हुए पांच वर्षो की अवधि में निर्मित 220 के.वी. के ग्रि.उ.के.[33] पर रूपांतरण क्षमता के साथ ही साथ बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में रूपांतरण क्षमता (पूर्त्ति की गई शीर्ष माँग) निम्नलिखित हैः

रूपांतरण क्षमता (एम.वी.ए. में)				
वर्ष	अधिष्ठापित	मार्जिन के लिए 30 प्रतिशत को छोड़कर[34]	शीर्ष मांग	आधिक्य/कमी
1.	2.	3=(2 का 70 प्रतिशत)	4.	5 = (3-4)
2007-08	1050	735	1606	(-)871
2008-09	1050	735	1698	(-)963
2009-10	1050	735	1774	(-)1039
2010-11	1050	735	1836	(-)1101
2011-12	1050	735	1885	(-)1150

(*स्रोत* : बोर्ड के अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से अवलोकित किया गया कि जरूरत के हिसाब से कुल रूपांतरण क्षमता काफी कम थी। वास्तव में, 2007-08 में कमी 871 एम.वी.ए. से बढ़कर 2011-12 में 1,150 एम.वी.ए. हो गया। इस प्रकार, ग्रि.उ.के. का निर्माण अपूर्ण रहने के कारण व्यस्ततम मांग की पूर्त्ति करने में बोर्ड अक्षम रहा।

2.18 ट्रांसफॉरमर विद्युत के संचरण तथा वितरण में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए अधिष्ठापित एक स्थिर यंत्र है। ग्रि.उ.के. से उच्च वोल्टेज (220/132 के.वी.) पर प्राप्त उर्जा को वितरण के लिए उपलब्ध कराने के लिए निम्न वोल्टेज (132/33 के.वी.) तथा 132/33 के.वी. ग्रि.उ.के. से 33/11 के.वी. पी.एस.एस. में रूपांतरित किया जाता है। समस्त संबंधित लोड की पूर्त्ति के लिए पर्याप्त रूपांतरण क्षमता होनी चाहिए। ट्रांसफारमर को जलने/क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए वितरण ट्रांसफरमर का अनुकूलतम बर्दास्त क्षमता अपने निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत है। बोर्ड की वर्ष 2007-08 से 2011-12 के वर्षो की अवधि में संबद्ध भार साथ ही साथ 80 प्रतिशत की दर पर रूपांतरण क्षमता नीचे की तालिका में दर्शायी गई हैः

[33] हटिया (300 एम.वी.ए.), चाण्डिल (300 एम.वी.ए.) तथा रामचन्द्रपुर (450 एम.वी.ए.) में 220 के.वी. ग्रि.उ.के.।

[34] ग्यारहवीं योजना - उर्जा पर कार्यरत समूह की अनुशंसा।

वर्ष	220/132 के.वी. क्षमता (एम.वी.ए.)	132/33[35] के.वी. क्षमता (एम.वी.ए.)	33/11 के.वी. क्षमता (एम.वी.ए.)	132/33 के.वी. ग्रि.उ.के. के अनुकूल 220/132 के.वी. की अपेक्षित क्षमता	कमी/अधिकता (एम.वी.ए.)	33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र के अनुकूल 132/33 के.वी. की अपेक्षित क्षमता	कमी/ अधिकता (एम.वी.ए.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=$\frac{100}{80}$ x (3)	(6=5-2)	(7)= $\frac{100}{80}$ x (4)	(8=7-3)
2007-08	1050	1338	2092	1673	(623)	2615	(1277)
2008-09	1050	1628	2182	2035	(985)	2728	(1100)
2009-10	1050	1898	2305	2373	(1323)	2881	(983)
2010-11	1050	1908	2491	2385	(1335)	3114	(1206)
2011-12	1050	1918	2661	2398	(1348)	3326	(1408)

(स्रोतः बोर्ड के अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 220/132 के.वी. की रूपांतरण क्षमता में कमी का अंतराल 2007-08 में 623 एम.वी.ए. से बढ़कर 2011-12 में 1,348 एम.वी.ए. हो गया जबकि 132/33 के.वी. में कमी का अन्तराल 2007-08 में 1,277 एम.वी.ए. से घटकर 2009-10 में 983 एम.वी.ए. हो गया एवं पुनः यह अंतराल 2011-12 में बढ़कर 1408 एम.वी.ए. हो गया। रूपांतरण क्षमता में ऐसा बेमेल होने के कारण देवघर, जामताड़ा, खरसावाँ, जादूगोड़ा तथा केन्दपोसी ग्रि.उ.के. की वर्तमान भार माँग की पूर्त्ति को पूर्ण करने में बोर्ड सक्षम नहीं था। डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में ग्रि.उ.के. तथा संचरण लाइन का उपलब्ध नहीं होना रूपांतरण क्षमता में बेमेल होने का मुख्य कारण था।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में भी बोर्ड को संचरण लाईन निर्माण करने की अनुमति है। तथापि, बोर्ड ने अपनी संचरण प्रणाली की स्थापना नहीं की तथा डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में आपूर्त्ति के लिए विद्युत की निकासी डी.वी.सी. से 33 के.वी. पर की जाती है तथा वितरण प्रणाली से वितरित की जाती है। हमने पाया कि जिस दर पर डी.वी.सी. से विद्युत क्रय किया गया वह बोर्ड द्वारा विद्युत क्रय के औसत लागत से अधिक था। परिणामस्वरूप, 2011-12 के दौरान विद्युत क्रय में बोर्ड को ₹ 299.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा (बोर्ड की वितरण कार्यकलाप पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में पहले से प्रतिवेदित ₹ 1,325 को छोड़कर)। यह डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में संचरण प्रणाली की रचना में अवैज्ञानिक योजना को दर्शाता है।

सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2013) कि उनके अपने कमान क्षेत्र में रूपांतरण क्षमता व्यस्ततम माँग से अधिक था, कुछ ग्रि.उ.के. में आगत उर्जा 132 के.वी. पर है तथा डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में आगत 33 के.वी. पर भी है एवं ग्रि.उ.के. की अभिवृद्धि तथा संवर्धन करने का प्रयास भी किया जा रहा था।

तथापि, तथ्य रह जाता है कि डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में बोर्ड की कोई संचरण प्रणाली नहीं थी तथा उनके अपने कमान क्षेत्र में पाँच ग्रि.उ.के.[36] अतिभारित थे।

[35] इसमें अक्टूबर 2007,जनवरी 2009 तथा दिसम्बर 2009 में निर्मित क्रमशः डाल्टेनगंज, लातेहार तथा काँके स्थित प्रत्येक 100 एम.वी.ए. क्षमता का ग्रि.उ.के. शामिल नहीं है जिन्हें अभी तक उर्जान्वित नहीं किया गया (नवम्बर 2012)।

[36] देवघर, जामताड़ा, खरसावाँ, जादूगोड़ा तथा केन्दपोसी।

उप-केन्द्र

उप-केन्द्रों की पर्याप्तता

2.19 संचरण योजना मापदण्ड की नियमावली (एम.टी.पी.सी.) विभिन्न ग्रि.उ.के. के लिए मान्य अधिकतम क्षमता को निर्दिष्ट करता है यथा 220 के.वी. ग्रि.उ.के. के लिए 320 एम.वी.ए. तथा 132 के.वी. के लिए 150 एम.वी.ए.।

ग्रि.उ.के. के अधिकतम क्षमता स्तर की जाँच में पता चला कि आदित्यपुर स्थित 132 के.वी. ग्रि.उ.के. का भार 150 के.वी.ए. से अधिक था जो मान्य स्तर से अधिक था। यह भी पाया गया कि प्रत्येक 132 के.वी.ए. एवं उससे अधिक की क्षमता वाले ग्रि.उ.के. में कम से कम दो ट्रांसफॉरमर होना चाहिए पर चक्रधरपुर स्थित ग्रि.उ.के. में 20 एम.वी.ए. का सिर्फ एक ट्रांसफॉरमर था। पुनः जनवरी 2009 में जारी की गई झा.रा.वि.नि.आ. (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 के अनुसार ग्रि.उ.के. में ट्रांसफॉरमरों की संख्या तथा आकार का योजना इस तरह से बनाया जाए कि किसी एक ट्रांसफॉरमर के आउटेज की स्थिति में शेष ट्रांसफॉरमरों या प्रणाली पर अत्यधिक भार न हो जाय। नमूना जाँच किये गये 20[37] ग्रि.उ.के. में से केवल रामचन्द्रपुर तथा लोहरदगा ग्रि.उ.के. ही किसी एक ट्रांसफॉरमर की आउटेज की दशा में भार संचारण कर सकता है। अपर्याप्त रूपांतरण क्षमता के कारण बोर्ड बढ़ती हुई भार माँग की पूर्त्ति कर पाने में असमर्थ है। अतः, रूपांतरण क्षमता का तत्कालिक संवर्धन आवश्यक है।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा उत्तर दिया कि रूपांतरण क्षमता का संवर्धन सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

वोल्टेज प्रबंधन

2.20 अंतर्राज्यीय संचरण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को सीमाओं के अंतर्गत ही ग्रिड वोल्टेज सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार, एस.टी.यू. को 400 के.वी., 220 के.वी. तथा 132 के.वी. लाईन के लिए वोल्टेज श्रेणी को क्रमशः 380-420 के.वी., 198-245 के.वी. तथा 122-145 के.वी. पर बनाए रखना है।

लेखापरीक्षा जाँच की अवधि के दौरान दो अंचलों के पाँच प्रमण्डलों के 13 ग्रि.उ.के. के 220/132 के.वी. बस वोल्टेज की जाँच में पता चला कि हटिया-II स्थित 220 के.वी. ग्रि.उ.के. में 212 के.वी. तथा 247 के.वी. वोल्टेज का स्तर अंकित की गई जबकि छः[38] 132 के.वी. ग्रि.उ.के. में 112 के.वी. तथा 145 के.वी. श्रेणी के अंतर्गत वोल्टेज अंकित की गई। गुणवत्तापूर्ण उर्जा प्रदान करने तथा संचरण हानि को कम करने के लिए बोर्ड को मानक के अनुसार अधिकतम तथा न्यूनतम वोल्टेज कायम रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

---

[37] देवघर, जामताड़ा, गढ़वा, जपला, हटिया-II , हटिया-I, नामकुम, लोहरदगा, गोइलकेरा, खरसावाँ, चक्रधरपुर, केन्दपोसी, नोवामुण्डी, आदित्यपुर , रामचन्द्रपुर , चाण्डिल-I, चाण्डिल-II, गोलमुरी, जादूगोड़ा तथा धालभूमगढ़।

[38] नामकुम, चाण्डिल-II, जपला, गढ़वा, धालभूमगढ़ तथा गोलमुरी।

सरकार ने लेखपरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा कहा कि ग्रि.उ.के. को वोल्टेज को सीमा से अधिक होने की स्थिति में वोल्टेज को मान्य सीमा के अंतर्गत रखने का निर्देश दिया गया है।

बस-बार प्रोटेक्शन पैनल (बी.बी.पी.पी.)

2.21 बस बार का प्रयोग विद्युत उप-केन्द्र में ट्रांसफारमर एवं प्रवाहित प्रवेशी और निर्गामी संचरण लाइनों के बीच अंतःसंबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। बी.बी.पी.पी. बस-बार के दोष को पूरे पावर नेटवर्क में फैलने नहीं देता जो अनावश्यक ट्रीपिंग को रोकता है और सिर्फ चुनिंदा ब्रेकरों को ही ट्रीप होने देता है जिन्हें बस-बार के दोष को दूर करने के लिए ट्रीप कराना आवश्यक होता है। संचरण पद्धति के ग्रिड मानकों एवं उत्तम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, बी.बी.पी.पी. का प्रयोग किया जाता है ताकि ग्रिड डिस्टरबेंस के समय सभी 220 के.वी. ग्रि.उ.के. के दोषों का जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके।

हमने पाया कि तीन 220 के.वी. ग्रि.उ.के. (एक डबल बस ग्रि.उ.के. और दो ट्रीपल बस ग्रि.उ.के.) में से जहाँ बीबीपीपी लगाया जाना था, बोर्ड सिर्फ हटिया ग्रि.उ.के. को ही एक बी.बी.पी.पी. मुहैया कराया था, शेष दो ग्रि.उ.के. रामचंद्रपुर और चांडिल में बी.बी.पी.पी. का प्रबंध कराया जाना बाकी था।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) एवं उत्तर में बतलाया गया कि फरवरी 2013 तक रामचंद्रपुर और चांडिल में बी.बी.पी.पी. स्थापित करने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

अनुरक्षण

करंट ट्रांसफॉरमर (सी.टी.) एवं पावर ट्रांसफॉरमर (पी.टी.) का निष्पादन

2.22 ग्रि.उ.के. की विद्युतीय उर्जा आपूर्त्ति तंत्र में सी.टी. एवं पी.टी. सबसे जरूरी एवं मूल्यवान घटकों में एक है। अतः इसके रख रखाव के खर्च को कम करते हुए इसके जीवन काल को बढ़ाने की विशेष आवश्यकता है। सी.टी. एवं पी.टी. की परिचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए प्रायः विभिन्न प्रकार के तेल विश्लेषण जैसे मानक तेल में घुलित गैस विश्लेषण (डी.जी.ए.) परीक्षण किये जाते हैं। सी.टी. एवं पी.टी. अवरोधन के लिए एक अवरोधी द्रव एवं ठोस अवरोधन से भरा हुआ मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस अवरोधी प्रणाली की वास्तविक स्थिति के मूल्यांकन के लिए प्रायः डी.जी.ए.परीक्षण किया जाता है। सी.टी. एवं पी.टी. के अंदर खराबी के कारण द्रव अवरोधन निम्न स्तर का इस प्रकार हो जाता है कि गैसों का मिश्रण विफलता के कारण को पहचान में सक्षम सिद्ध करता है। 2007-2012 की अवधि में बोर्ड ने सी.टी. के लिए डी.जी.ए. एवं अवरोधी तेल परीक्षण नहीं किया था। यद्यपि, उसी दौरान किये गये विभिन्न ग्रि.उ.के. के 16 पी.टी. का डी.जी.ए. एवं अवरोधी तेल परीक्षण में एसिटीलीन ($सी_2एच_2$), अम्लता एवं अवरोधता मूल्य के उल्लंघन, कीचड़ के अवशेष को दर्शाया जिसके कारण तेल का पुनःउद्धार/बदली नौ पी.टी. में आवश्यक थे। अम्लता एवं कीचड़ पी.टी. के उम्र को प्रभावित करता है तथा तेल का पुनःउद्धार/बदली

2007-12 की अवधि के दौरान डी.जी.ए.एवं अवरोधी तेल परीक्षण पी.टी. पर किये गये थे परंतु सी.टी.पर नहीं। नौ पी.टी. में निर्धारित मानकों का उल्लंधन देखा गया था जहाँ कि तेल पुनःउद्धार/बदली की आवश्यकता थी जो परीक्षणों से पाँच से 48 महीनों तक नहीं किया गया।

ट्रांसफॉरमरों के जीवन काल को बढ़ायेगी। यद्यपि, डी.जी.ए. एवं अवरोधी तेल परीक्षणों के पाँच से 48 माह गुजरने के बाद भी तेल पुनःउद्धार/बदली नहीं किये गये थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) एवं उत्तर दिया कि मरम्मत/वार्षिक रखरखाव के दौरान छनाई के द्वारा तेल की स्थिति को उन्नत करने के प्रयास किये गये थे।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि तेल का पुनःउद्धार/बदली नहीं किया गया था यद्यपि पिछले डी.जी.ए. एवं अवरोधी तेल परीक्षणों से पाँच से 48 महीनों का समय व्यतीत हो गया है।

अर्थ मेस के संवर्द्धन तथा कवच तार के बिना ट्रांसफॉरमर की स्थापना करने के परिणामस्वरूप इसके मरम्मत पर ₹ 1.13 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान जाँच किए गए 48 पी.टी. में चार पी.टी. विफल हुआ। यह देखा गया कि तीन पी.टी. 23 वर्ष पुराने थे तथा हटिया-। ग्रि.उ.के. में स्थित 2 x 20 एम.वी.ए. के एक पी.टी. को 50 एम.वी.ए. के पी.टी. से बिना अर्थ मेस को संबद्धित एवं शक्तिशाली बनाये तथा न्यूनतम तेल सर्किट अवरोधक के पुनरूद्धार किये बदली किया गया (फरवरी 2005)। तड़ित के प्रभाव के कारण पीटी ट्रीप कर गया (जुलाई 2008)। यह भी प्रेक्षित किया कि पी.टी. रिले पैनेल के रखरखाव और रिले का कैलीब्रेसन नहीं किया जा रहा था तथा पी.टी. के अग्रभाग की प्लीन्थ सहित कई गैन्ट्री कॉलम में तड़ित के विरूद्ध सुरक्षा के लिए आवश्यक कवच तार नही था। पी.टी. को ₹ 1.13 करोड़ के परिहार्य व्यय से मरम्मत कर पुनः स्थापित किया गया (जून 2011)।

सरकार ने लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा कहा कि पी.टी. को अर्थ मेस के संवर्द्धन एवं शक्तिशाली करने एवं कवच स्थापित करते हुए पुनः स्थापित किया गया।

हॉट लाइन प्रमंडल एवं उप प्रमंडल के कार्य

2.23 संचरण प्रणाली के बिना व्यवाधान परिचालन के लिए इसके निरन्तर तथा समय-समय पर अनुरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। लाइन के निर्धारित निगरानी के अलावा लाइन के अनुरक्षण के लिए निम्न तकनीकों को देश में संचरण प्रणाली में सर्वोत्तम प्रयोगो को अद्यतन करने की समिति के प्रतिवेदन (जनवरी 2002) में निर्दिष्ट किया गया है:

- ❖ हॉट लाइन अनुरक्षण
- ❖ हॉट लाइन धुलाई
- ❖ इन्सुलेटर के पंचर का हॉट लाइन से पता लगाना
- ❖ पोर्टेबल अर्थिंग हॉट लाइन टूल के प्रयोग से निवारक रखरखाव
- ❖ लाईन में कम्पन की माप
- ❖ थर्मो स्कैनिंग
- ❖ उपकरणों की प्रदूषण माप

हॉट लाइन तकनीक (एच.एल.टी) ग्रि.उ.के. तथा लाईन का स्विच बंद किये बिना हॉट स्पॉट के रखरखाव कार्य, नट वोल्ट को कसने, कंडक्टर के नुकसान, इंसुलेटर को बदलने इत्यादि को समाहित करता है। इसके अंतर्गत सभी लाइनों तथा ग्रि.उ.के. के बचाव उन्मूख रख रखाव हेतु थर्मो स्कैनिंग शामिल है। भारत में एच.एल.टी 1958 में प्रारम्भ हुआ।

मार्च 2012 को बोर्ड का कोई हॉटलाइन प्रमण्डल नहीं था बोर्ड ने ग्रि.उ.के. के बचाव उन्मूख रखरखाव की परिचालन एवं रख रखाव नियमावली एवं अनुसूची परिचालन एवं रख रखाव नियमावली तैयार नहीं किया था। मात्र खराबी का रख रखाव किया जा रहा था।

सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि समय के साथ अद्यतन तकनीक अपनाया जाएगा।

संचरण हानि

2.24 जब उर्जा को संचरण एंव वितरण (टी.एण्ड डी.) प्रणाली के द्वारा उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है तब कुछ उर्जा की हानि होती है जिसे संचरण एंव वितरण हानि कहते हैं। संचरण हानि उत्पादन केन्द्र/ग्रिड से प्राप्त उर्जा तथा बोर्ड के आपूर्त्ति क्षेत्र को भेजी गयी उर्जा का अन्तर है।

2007-08 से 2011-12 तक संचरण हानि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	वर्ष				
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	संचरण के लिए प्राप्त उर्जा	एम.यू.	7412	8122	8663	9344	9560
2.	शुद्ध संचारित उर्जा	एम.यू.	एन. ए.	7713	8168	8742	9034
3.	वास्तविक संचरण हानि (1-2)	एम.यू.	एन. ए.	409	495	602	526
		प्रतिशतता	एन. ए.	5.04	5.71	6.44	5.50
4.	सी.ई.ए. मानकों के अनुसार लक्षित संचरण हानि	प्रतिशतता	4	4	4	4	4
5.	झा.रा.वि.नि.आ. मानको के अनुसार लक्षित सचरण हानि	प्रतिशतता	एन. ए.	5	5	5	5
6.	झा.रा.वि.नि.आ. के मानकों से अधिक संचरण हानि (3-5 प्रतिशत x 1)	एम.यू.	एन. ए.	3	62	135	48
7.	प्रति इकाई वसूली का मूल्य	दर प्रति इकाई में (₹)	1.84	1.87	1.82	1.99	*[39]
8.	कुल हानि (7) x (6)	₹ करोड़ में	एन. ए.	0.56	11.28	26.87	*

(स्रोतः बोर्ड द्वारा उपलब्ध की गई आँकड़े)

[39] 2011-12 के लेखों को अंतिमीकृत करना बाकी है।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि संचरण हानि बढ़ोत्तरी के प्रवृत्ति में है और सभी चार वर्षों में सी.ई.ए. के चार प्रतिशत मापदण्ड साथ ही झा.रा.वि.नि.आ. के तय वार्षिक मानकों से भी अधिक है। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान बोर्ड द्वारा झा.रा.वि.नि.आ. के तय मानकों से 200 एम.यू. अधिक का संचरण हानि हुआ जिसका मूल्य ₹ 38.71 करोड़ था।

सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि हानि में क्षेत्रीय संचरण हानि सम्मिलित हैं, तथा इसे छोड़कर बोर्ड की संचरण हानि झा.रा.वि.नि.आ. के मानकों के अंदर है। सरकार ने यह भी कहा कि यह संचरण हानि अनुमानित है क्योंकि सभी फीडर में मीटर नहीं था तथा कुछ मीटर पुराने एवं खराब हैं। बोर्ड 100 प्रतिशत मीटर स्थापित करने की योजना बना रही थी।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि बोर्ड ने न तो क्षेत्रीय संचरण हानि का कोई आँकड़ा रखा है और न ही अपने उत्तर के समर्थन में यह प्रस्तुत किया है।

ग्रिड प्रबंधन

ग्रिड का अनुरक्षण तथा एस.एल.डी.सी. का निष्पादन

2.25 उत्पादन केन्द्र से वितरण कम्पनियों/उपभोक्ताओं को उर्जा की अबाध निष्कासन के लिए संचरण एवं ग्रिड प्रबंधन एक आवश्यक कार्य है। ग्रिड प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि उर्जा प्रणालियों के विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता तथा दक्षता को ध्यान में रखने के लिए हर समय अन्तर्संबंधित उर्जा प्रणालियों में उर्जा संतुलन बना रहे। भारत में ग्रिड प्रबंधन सी.इ.ए. के द्वारा जारी ग्रिड कोड में दिये गये मानकों/निर्देशनों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड में पाँच क्षेत्र अर्थात उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण ग्रिड शामिल है, इनमें प्रत्येक के पास एक शीर्ष निकाय, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर.एल.डी.सी.) है, जो संबंधित क्षेत्र में उर्जा प्रणाली के एकीकृत परिचालन को सुनिश्चित करता है। झारखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) जो पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (ई.आर.एल.डी.सी.), कोलकत्ता का घटक है, राज्य में उर्जा प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31 का अनुपालन न करते हुए एस.एल.डी.सी. का कार्यकलाप बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है और राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से यह अधिसूचित नहीं किया है कि एस.एल.डी.सी. का परिचालन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 31 के अनुसार

"(I) राज्य सरकार इस मामले के अन्तर्गत शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य को करने के उद्देश्य से एस.एल.डी.सी. के नाम से एक केन्द्र स्थापित करेगा।

(II) राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित कोई भी सरकारी कम्पनी या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित कोई प्राधिकार अथवा निगम के द्वारा एस.एल.डी.सी. का संचालन होगा।

(अ) बशर्ते, राज्य सरकार के द्वारा कोई सरकारी कम्पनी या प्राधिकार या निगम अधिसूचित न होने तक राज्य संचरण संस्था एस.एल.डी.सी. को संचालित करेंगे"

बोर्ड का विभाजन नहीं होने के कारण एस.एल.डी.सी. के कार्य बोर्ड द्वारा किये जा रहे हैं, यद्यपि राज्य सरकार ने औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं किया है कि एस.एल.डी.सी. का परिचालन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) और कहा कि एस.एल.डी.सी. का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन करने की प्रक्रिया जारी है।

भार अनुश्रवण के लिए आधारभूत संरचना

2.26 सभी ग्रि.उ.के. के लिए ग्रिड मानकों के अनुसार, एस.एल.डी.सी. में आपातकालीन स्थिति में संचरण प्रणाली की दक्षता तथा भार के अनुश्रवण के लिए रिमोट टर्मिनल इकाई/उप-केन्द्र प्रबंधन प्रणाली (आर.टी.यू./एस.एम.एस.) आवश्यक है।

220 और 132 के.वी. ग्रि.उ.के. के आठ रिमोट टर्मिनल इकाई छः महीने से नौ वर्ष तक अपर्याप्त बैटरी बैंक तथा तीन पैनलों पर संबद्धता में रूकावट के कारण कार्यरत नहीं था जो एस.एल.डी.सी. की भार अनुश्रवण केन्द्र की तरह कार्य करने की योग्यता को कम करता है।

हमने देखा कि 220 के.वी. के तीन ग्रि.उ.के., 132 के.वी. के 22 ग्रि.उ.के. और तीन उर्जा उत्पादन संयत्र में से 220 के.वी. के दो (67 प्रतिशत) और 132 के.वी. के नौ ग्रि.उ.के. (41 प्रतिशत) तथा सभी तीन (100 प्रतिशत) उत्पादन संयंत्रों को दक्षतापूर्ण उर्जा प्रबंधन प्रणाली हेतु आँकड़ों के वास्तविक समय पर अंकन के लिए आर.टी.यू. उपलब्ध कराया गया था। तथापि, 220 के.वी. व 132 के.वी. के ग्रि.उ.के. के आठ आर.टी.यू. छः महीने से नौ वर्षों तक अपर्याप्त बैटरी बैंक और जामताड़ा, देवघर और गढ़वा पैनल में संबद्धता में रूकावट के कारण कार्यरत नहीं थे। आर.टी.यू. के कार्यरत नहीं होने से एस.एल.डी.सी. की भार अनुश्रवण केन्द्र के रूप में कार्य करने की योग्यता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, एस.एल.डी.सी. की आँकड़ा संग्रहण सुविधा केवल एक वर्ष तक की है।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) और कहा कि बैटरी बैंक शीघ्र ही बदल दिये जाएगें और संबद्धता के पुनर्स्थापन का मामला पी.जी.सी.आई.एल के साथ उठाया गया है। तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि 14 में से आठ आर.टी.यू. छः महीनों से नौ वर्षों तक कार्यरत नहीं थे।

बारम्बारता प्रबंधन द्वारा ग्रिड अनुशासन

2.27 ग्रिड कोड के अनुसार, ग्रिड के दक्षतापूर्ण कार्यवाही के लिए संचरण संस्थानों को ग्रिड अनुशासन बनाये रखना आवश्यक है। ग्रिड के सभी संघटक सदस्यों के लिए अपेक्षित है कि प्रणाली बारम्बारता 49.2 और 50.3 हर्ट्ज के बीच रखा जाए। उत्पादन क्षमता में कमी, उच्च माँग, भार उत्पादन संतुलन में ग्रिड अनुशासन नहीं होने, अपर्याप्त भार अनुश्रवण तथा प्रबंधन के कारण प्रणाली बारम्बारता कायम नहीं रहता है। इस तरह, ग्रिड बारम्बारता अनुमत बारम्बारता स्तर से निम्न या उच्च स्तर पर चला जाता है। अनुशासन बनाये रखने के लिए एस.एल.डी.सी. तीन प्रकार के उल्लंघन संदेश (ए, बी, सी) जारी करता है। जब बारम्बारता 49.2 हर्ट्ज से कम हो और अधिक निकासी 50 एम.डब्ल्यू. से उपर या निर्धारित निकासी का 10 प्रतिशत, इनमें से जो कम हो, तब संदेश "ए" जारी किया जाता है। जब बारम्बारता 49.2 हर्ट्ज से कम हो और अधिक निकासी 50 से 200 एम.डब्ल्यू. के बीच दस मिनट से अधिक समय के लिए हो या 200 एम.डब्ल्यू. पाँच मिनट से अधिक के लिए हो, तब उल्लंघन संदेश

"बी" जारी किया जाता है। संदेश "बी" के जारी होने के 15 मिनट के बाद जब 49.2 हर्ट्ज से कम बारम्बारता जारी रहे और अधिक निकासी 100 एम.डब्ल्यू. से अधिक या निर्धारित निकासी 10 प्रतिशत में से जो कम हो, तब संदेश "सी" सूचना (गंभीर प्रकृति) जारी किया जाता है।

हमने देखा कि एस.एल.डी.सी. घंटावार बारम्बारता अंकित करता है। अक्टूबर 2009 से मार्च 2012 के दौरान 227 दिनों में 443 अवसरों पर प्रणाली बारम्बारता 49.2 हर्ट्ज से कम और 50.3 हर्ट्ज से अधिक था, परंतु निकासी 50 एम.डब्ल्यू. से नीचे था। अतः बोर्ड ग्रिड अनुशासन को बनाए रखा था। यद्यपि, एस.एल.डी.सी. के पास अप्रैल 2007 से सितम्बर 2009 तक की अवधि के लिए आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

बैकिंग डाउन निर्देशन (बी.डी.आई.)

2.28 जब बारम्बारता आदर्श सीमा से अधिक होता है जैसे वह परिस्थिति जहाँ उत्पादन अधिक है और निकासी कम है (50 हार्टज से अधिक की बारम्बारता पर) एस.एल.डी.सी. ग्रिड की एकीकृत परिचालन तथा राज्य में उर्जा प्रणाली के परिचालन में अधिकतम मितव्ययिता एवं कार्य क्षमता सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन में कमी के लिए उत्पादकों को बी.डी.आई. निर्गत करता है। राज्य में तीन उर्जा उत्पादक शक्ति केन्द्र हैं, एक तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाली 420 एम. डब्ल्यू. (210 x 2) का तेनुघाट वाष्प शक्ति केन्द्र (टी.टी.पी.एस.) तथा बोर्ड के स्वामित्व वाले दो उत्पादन केन्द्र यथा, 770 एम.डब्ल्यू. (ह्रासित शक्ति दर) का पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (पी.टी.पी.एस.) तथा 130 एम.डब्ल्यू. का स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना (एस.आर.एच.पी.) थी। टी.टी.पी.एस. से उत्पादित ऊर्जा दो संचरण लाइन द्वारा बी.एस.इ.बी. के बिहार शरीफ स्थित ग्रिड एवं बोर्ड के पी.टी.पी.एस. स्वीचयार्ड (400 के.वी. का एकल परिपथ) को संचारित किया जाता है। यद्यपि, दोनों लाईन का परिचालन 220 के.वी. क्षमता पर हो रहा है। जब भी एक लाइन ब्रेक डाउन होता है, टी.टी.पी.एस. को अपने उर्जा उत्पादन को बैक डाउन करना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक लाइन के तारों की मांग एवं क्षमता सिर्फ 250 एम.डब्ल्यू. है। इस तरह, टी.टी.पी.एस. में उत्पादित कुल उर्जा का निष्कासन अंतिम छोर पर 400 के.वी. ग्रि.उ.के. उपलब्ध न होने के कारण नहीं होता है।

बिहार शरीफ में 400/200 के.वी. ग्रि.उ.के. के साथ 400 के.वी.एकल परिपथ टी.टी.पी.एस.- बिहार शरीफ संचरण लाइन को परस्पर जोड़ने में विलंब के कारण उच्च दर पर उर्जा क्रय में ₹ 102.41 करोड़ का परिहार्य व्यय।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान एस.एल.डी.सी. ने टी.टी.पी.एस. को 77 बी.डी.आई. निर्गत किये जिनका अनुपालन हुआ, जिसमें टी.टी.पी.एस. को 603.38 एम.यू. उत्पादन हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 140.09 करोड़ था। टी.टी.पी.एस. से उत्पादित सभी उर्जा बोर्ड को बेची गई। टी.टी.पी.एस. में पर्याप्त निष्कासन क्षमता के अभाव में बोर्ड को 2007-08 से 2011-12 की अवधि में अन्य स्रोतों से उच्च दरों पर 603.38 एम.यू. उर्जा क्रय करने में ₹ 102.41 करोड़ अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। इस समस्या से उबरने के लिए बोर्ड ने 400 के.वी. एकल परिपथ (एस/सी) टी.टी.पी.एस.-बिहारशरीफ सचंरण लाइन को 400/220 के.वी. ग्रि.उ.के., बिहारशरीफ से परस्पर जोड़ने के लिए लागत जोड़ लाभ के आधार पर ₹ 8.20 करोड़ का कार्यादेश पी.जी.सी.आई.एल. को निर्गत किया (मई 2008)। पी.जी.सी.आई.एल. ने कार्य स्थगित कर दिया, क्योंकि बोर्ड ने सिर्फ ₹ 2.94 करोड़ के प्रथम चलन्त विपत्र (आर.ए.) का

भुगतान किया तथा ₹ 7.06 करोड़ मूल्य का शेष दो चलन्त विपत्र का भुगतान धन के अभाव में नहीं किया (जून 2012)।

आगे, टी.टी.पी.एस. ने पी.जी.सी.आई.एल. को लागत जोड़ लाभ के आधार पर अपने परिसर के 400 के.वी. स्वीचयार्ड में 400 के.वी. के पाँच खण्ड के निर्माण हेतु ₹ 22.70 करोड़ में कार्य सौंपा। कार्य 24 माह में समाप्त होना निर्धारित था परन्तु कार्यक्षेत्र के निर्धारण में देरी होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया (मई 2012)।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा कहा कि उद्देश्य ग्रिड अनुशासन स्थापित करना था तथा टी.टी.पी.एस. के बैकिंग डाउन के कारण उर्जा क्रय पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ।

सरकार ने अपने उत्तर में विषय को संबोधित नहीं किया चूँकि बैकिंग डाउन समस्या के निराकरण के लिए दोनों लाइनों के समन्वय कार्य प्राथमिकता के आधार पर पहले करना चाहिए था। टी.टी.पी.एस. के बैकिंग डाउन के कारण बोर्ड को अन्य स्रोतों से उच्च दर पर उर्जा का क्रय करना पड़ा।

आपदा प्रबंधन

2.29 आपदा प्रबंधन (डी.एम.) का उद्देश्य किसी प्रणाली के वृहद पैमाने पर ठप हो जाने से पड़ने वाले प्रभाव को कम करना तथा इसको न्यूनतम संभव समय में पुनर्स्थापित करना है। देश के संचरण प्रणाली में सर्वोत्तम पद्धति को अद्यतन करने की समिति के प्रतिवेदन (जनवरी 2002) के अनुसार, सभी उर्जा संस्थानों को डी.एम. स्थापित करना चाहिए ताकि वृहद पैमाने पर विफलता की स्थिति में संचरण प्रणाली तुरंत पुनर्स्थापित हो सके। यह आपातकालीन पुनर्स्थापन प्रणाली (ई.आर.एस.), डीजल जेनरेटर (डी.जी.) सेट, वाहनों, अग्निशमन उपकरणों तथा कुशल एवं विशेषज्ञ मानव शक्ति के नियोजन के द्वारा किया जाता है। आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन केन्द्र, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, नई दिल्ली, केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है।

आपदा प्रबंधन के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ

- एस.एल.डी.सी. ने राज्य की दो वाष्प शक्ति उत्पादन करने वाली प्रतिष्ठानों टी.टी.पी.एस. और पी.टी.पी.एस. तथा एक जल विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना, एस.आर.एच.पी. को चिन्हित किया, जिसमें से केवल एस.आर.एच.पी. में ब्लैक स्टार्ट[40] सुविधा उपलब्ध थी जो आपदा प्रबंधन की अपर्याप्त तैयारियों को दर्शाती थी। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में ब्लैक स्टार्ट के दौरान उत्पादन केन्द्र को चालू करने हेतु केवल एक बार कृत्रिम अभ्यास किया गया था (नवम्बर 2011)।

[40] आंशिक अथवा पूर्ण ब्लैक आउट से निकलने की आवश्यक प्रक्रिया।

- ग्रि.उ.के. एवं उत्पादन इकाइयों में डिजल जेनरेटर (डी.जी.) सेट्स एवं सिन्क्रोस्कोप्स[41] डी.एम. सुविधाओं के अंग हैं। हमने पाया कि तीन उत्पादन इकाईयों में से एस.आर.एच.पी में 2007-08 से 2011-12 की अवधि में सिन्क्रोस्कोप्स कार्य नहीं कर रहे थे एवं पी.टी.पी.एस. में डीजल जेनेरेटर उपलब्ध नहीं थे। 220 के.वी. के तीन ग्रि.उ.के. में से केवल हटिया-II ग्रि.उ.के. पर डीजल जेनेरेटर सेट उपलब्ध था जो 2011-12 की अवधि में कार्य नहीं कर रहा था। यद्यपि सभी 220 के.वी. के ग्रि.उ.के. पर सिन्क्रोस्कोप्स उपलब्ध थे, चाण्डिल-I एवं रामचन्द्रपुर में वे पाँच वर्षों से अधिक समय से काम नहीं कर रहे थे।

- मेटल डिटेक्टर के प्रावधान के लिए बोर्ड ने असुरक्षित अधिष्ठापनों को चिन्हित नहीं किया। ग्रि.उ.के. की सुरक्षा होम गार्ड के जवानों द्वारा किया जा रहा है जो भविष्य में नक्सल हमलों, तोड़-फोड़ एवं बम के खतरों के कारण उत्पन्न कोई भी संकट का सामना करने में अपर्याप्त है।

मई 2010 से अप्रैल 2012 की अवधि में पाँच टावरों के गिरने के बावजूद बोर्ड ने ₹ 7.61 करोड़ से क्रय की गई आपदा पुनर्स्थापन प्रणाली का उपयोग नहीं किया।

- बोर्ड ने ई.आर.एस. में शामिल तोरण प्रकार व्यवस्था वाले हल्के वजन के टावर्स को मेसर्स पी.सी.आई.लि. से ₹ 7.61 करोड़ की लागत पर खरीदा था (अक्टूबर 2009) जिसे बिजली आपूर्त्ति बहाल करने हेतु आसानी से परिवहनीय एवं छः से आठ घंटों के भीतर खड़ा किया जा सकता है। संस्थान ने बोर्ड के अधिकारियों एवं संचरण लाईन के गश्ती, कंडक्टरों एवं इंस्युलेटरों के मरम्मत, ग्रि.उ.के. के वार्षिक अनुरक्षण संविदा आदि में नियुक्त छः[42] एजेसियों के 30 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया था (जनवरी 2010)। हटिया-II ग्रि.उ.के. में ई.आर.एस. निष्क्रिय पड़ा हुआ था (अक्टूबर 2009)। मई 2010 से अप्रैल 2012 की अवधि में पाँच टावरों के गिरने के बावजूद बोर्ड ने ई.आर.एस. का उपयोग किये बिना इन टावरों को खड़ा करने में पाँच से 23 दिनों का समय लगाया जिसके कारण वैक्लपिक व्यवस्था होने तक 12 दिनों तक बिजली आपूर्त्ति बाधित रही। चूँकि ई.आर.एस. का प्रयोग अभी तक (अप्रैल 2012) नहीं हुआ था, अतः इनके खरीद पर ₹ 7.61 करोड़ का व्यय बिना किसी लाभ के निष्क्रिय साबित हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा मन्तव्य को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा कहा कि ई.आर.एस. को अब दो प्रक्षेत्रों राँची तथा दुमका को वितरित किया जा चुका है तथा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता को ई.आर.एस. अधिष्ठापन करने हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि ई.आर.एस. का इस्तेमाल इसकी अधिप्राप्ति के तीन वर्षो तक नहीं किया गया एवं जमशेदपुर संचरण क्षेत्र के पास ई.आर.एस. नहीं है।

[41] ए.सी. विद्युतीय उर्जा प्रणाली मे यह एक यंत्र है जो यह दर्शाता है कि दो प्रणाली जेनरेटर या उर्जा प्रणाली परस्पर किस स्तर तक सिन्क्रोनाइज्ड है।

[42] ट्रांस मेक, सिद्धार्थ पावर, आर.एस.इलेक्ट्रीकल एण्ड इंजीनियरिंग, राम इरेक्शन वर्क्स, भारत इंजीनियरिंग वर्क्स तथा यू.एस. कंस्ट्रक्सन।

उर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा

2.30 संचरण हानि के आकलन एवं कमी के संबंध में उर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कदम है। उर्जा लेखांकन में जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा प्रवाह एवं एक निर्धारित समय में कुल उपलब्ध मात्रा का खपत कैसे किया गया है का लेखाकंन तैयार करना सम्मिलित है, उर्जा लेखापरीक्षा में उर्जा लेखा के आँकड़ों का सार्थक तरीके से विश्लेषण किया जाता है ताकि प्रणाली में रिसावों एवं हानियों को कम करने हेतु आवश्यक नियत्रंण एवं संतुलन के तरीकों को विकसित किया जाए एवं तकनीकी निष्पादन को भी बेहतर किया जाए।

प्रभावी उर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सभी स्तरों जैसे फीडर, ग्रि.उ.के. एवं विद्युत उप-केन्द्र (पी.एस.एस.) पर एक समान के मीटर लगाये जायें तथा मीटर पाठन नियमित रूप से लिये जाये एवं उनका मिलान किया जाए ताकि रिसाव क्षेत्र की पहचान हो एवं सुधारात्मक कदम उठाए जाए। उर्जा लेखांकन एक बार की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह लगातार किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में उर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा नहीं किया गया था क्योंकि एक ग्रि.उ.के. (जादूगोड़ा) के फीडरों में मीटर नहीं लगे हुये थे, जबकि सात ग्रि.उ.के.[43] के मीटर दोषपूर्ण थे तथा पाँच वर्षो से अधिक समय से बदले नहीं गये थे एवं पाँच से 24 वर्षों से जाँचे नहीं गये थे यद्यपि प्रत्येक चार वर्षों के पश्चात जाँचने की आवश्यकता थी।

हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 13 ग्रि.उ.के. में से आठ[44] ग्रि.उ.के. में उर्जा का निर्यात आयातित उर्जा से ज्यादा था जो यह इंगित करता है कि मीटर दोषपूर्ण थे। पुनः, तेनुघाट वाष्प शक्ति केन्द्र (टी.टी.पी.एस.) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि पी.टी.पी.एस. स्वीचयार्ड को उर्जा संचारित करने के क्रम में, पी.टी.पी.एस. स्वीचयार्ड में जनवरी से मार्च 2012 के दौरान हानि सात से 21 प्रतिशत के बीच था। पी.टी.पी.एस., हटिया-I एवं हटिया-II ग्रि.उ.के. को उर्जा संचारित करता था जिसमें लेखापरीक्षा संवीक्षा अवधि के दौरान हानि (-9) से 51 प्रतिशत के बीच था। पी.टी.पी.एस. एवं ग्रि.उ.के. पर हानि प्रतिशत उच्च संचरण हानि को दर्शाते थे, जो इंगित करता था कि मीटर दोषपूर्ण थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा मंतव्य को स्वीकार किया (जनवरी 2013) एवं कहा कि संचरण में 100 *प्रतिशत* मीटर अधिष्ठापन प्रक्रिया में है।

सामग्री प्रबंधन

2.31 सामग्री प्रबंधन का मुख्य कार्य सामग्री नियंत्रण नीति का निर्धारण, सामग्रियों की अधिप्राप्ति एवं पुराने सामग्रियों का निपटारा करना है। हमने पाया कि मितव्ययी

[43] आदित्यपुर, चाण्डिल, गोलमुरी, रामचन्द्रपुर, गढ़वा रोड, हटिया-I तथा धालभूमगढ़।
[44] आदित्यपुर, चाण्डिल, जादूगोड़ा, गोलमुरी, रामचन्द्रपुर, गढ़वा रोड, हटिया-I तथा धालभूमगढ़।

अधिप्राप्ति एवं सामग्री पर दक्षतापूर्ण नियत्रंण हेतु बोर्ड ने कोई क्रय नीति एवं सामग्री नियंत्रण तंत्र निर्धारित नहीं किया था।

2.32 वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान उपभोग एवं अंतिम रहतिया का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपभोग (प्रतिवर्ष)	उपभोग (प्रतिमाह)	शुद्ध अंतिम रहतिया (आर्थिक चिट्ठा के अनुसार)	माह के संदर्भ में उपभोग के विरूद्ध अंतिम रहतिया
1	2	3 = (2)/12	4	5 = (4)/(3)
2007-08	3.98	0.33	6.42	19
2008-09	9.36	0.78	4.90	6
2009-10	21.32	1.78	6.59	4
2010-11	3.93	0.33	5.98	18

(स्रोतः बोर्ड मुख्यालय के अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मासिक उपभोग की संख्या के संदर्भ में अंतिम रहतिया 2007-08 के दौरान 19 माह था जो 2009-10 में घटकर चार माह हो गया परन्तु पुनः 2010-11 में यह बढ़कर 18 माह हो गया जो सामग्री नियंत्रण तंत्र के अभाव को इंगित करता था। बोर्ड ने अपनी सामग्री आवश्यकताओं का न तो कभी ए.बी.सी. विश्लेषण किया न ही कोई अधिकतम/न्यूनतम मानक स्तर या पुनः आदेश स्तर निर्धारित किया था।

हमने आगे पाया कि बोर्ड के पास 17 सी.टी. एवं 24 किलोमीटर जेबरा कंडक्टर का रहतिया होने के बावजूद तत्काल आवश्यकता के आधार पर 83 सी.टी. (अगस्त 2009) एवं 40 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. जेबरा कंडक्टर (सितम्बर 2009) की अधिप्राप्ति ₹ 2.04 करोड़ की लागत पर किया था। हालाँकि पुराने रहतिया में से केवल 11 सी.टी. तथा 2.55 किलोमीटर जेबरा कंडक्टर निर्गत किये गये (मार्च 2012)। इस प्रकार, तत्काल आधार पर खरीदे गये सामग्री भंडार में अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि सी.टी. एवं जेबरा कंडक्टर का क्रय परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में रखने हेतु किया गया।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि बोर्ड ने जिस सामग्री की अधिप्राप्ति तात्कालिक आवश्यकता के लिए किया था वह अभी तक उपभोग हेतु निर्गत नहीं किया गया है।

भंडार में सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

2.33 राँची, जमशेदपुर तथा देवघर में बोर्ड के नियंत्रण में तीन क्षेत्रीय भंडार है। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में उनका भौतिक सत्यापन (पी.वी.) नहीं किया गया था। अप्रचलित, अधिशेष, पुराने, बेकार एवं स्क्रैप सामग्री का मूल्य जमशेदपुर के भंडार में केवल 2010-11 एवं 2011-12 के लिए उपलब्ध था जो ₹ 0.55 करोड़ से बढ़कर ₹ 0.62 करोड़ हो गया था। सामग्री का मिलान नहीं किया जा सका क्योंकि भंडार का पी.वी. नहीं किया जा रहा था। भंडारपाल की सेवा निवृत्ति (फरवरी 2012) के पश्चात

जून 2012 से देवघर का भंडार बंद था जबकि राँची के भंडार में स्क्रैप सामग्री का मूल्य दिये बिना केवल मात्रा का संधारण किया गया था (मार्च 2012). बोर्ड ने बेकार/पुराने सामग्री के निपटारे के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी तथा भंडार में अन्य सामग्रियों को रखने के लिए जगह बनाया जा सकता था।

लेखापरीक्षा मंतव्य को सरकार ने स्वीकार किया (जनवरी 2013) एवं कहा कि उनके पास सामग्री नियंत्रण, सामग्री अधिप्राप्ति एवं बेकार भंडार के निपटारे की कोई नीति नहीं है। उन्होंने पुनः कहा कि समस्त भंडार के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परामर्शी की नियुक्ति की गई है।

अनुश्रवण एवं नियंत्रण

2.34 राज्य की अर्थव्यवस्था में बोर्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक संस्था के मितव्ययी, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी संचालन हेतु, परिचालन, सेवा मापदण्ड तथा लक्ष्य के लिए एक अच्छी प्रलेखित प्रबंधन सूचना प्रणाली होनी चाहिए। पुनः, मानक लक्ष्य एवं मानदंडों की उपलब्धि को प्रतिवेदित करने हेतु एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) होनी चाहिए। ग्रि.उ.के. एवं 400/220/132 के.वी. लाइन के विभिन्न पैरामीटरों यथा अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज स्तर, विफलता, वोल्टेज प्रोफाइल का निष्पादन ग्रिड कोड मानकों के अनुरूप दर्ज/अनुरक्षित होना चाहिए।

इस संबंध में हमने निम्नलिखित अवलोकित कियाः

- ग्रि.उ.के. एवं लाइनों के वार्षिक निष्पादन के मूल्याकंन हेतु बोर्ड स्तर पर ग्रि.उ.के. एवं लाइनों के वर्षवार संचयी निष्पादन न तो दर्ज न ही संकलित किये जा रहे थे। हालाँकि, संचरण इकाईयों के क्षेत्रीय प्रमण्डल मासिक एम.आई.एस. प्रतिवेदन संकलित कर रहे थे जिनमें इकाईयों एवं अधिष्ठापित उपकरणों का निष्पादन दर्शाया जा रहा था, यद्यपि, ये प्रतिवेदन बोर्ड कार्यालय को प्रेषित नहीं किये जा रहे थे जैसा कि होना चाहिए था, और न ही बोर्ड स्तर पर इनके प्राप्ति का अनुश्रवण हो रहा था।

- एम.आई.एस. प्रतिवेदन के सत्यापन से यह पता चला कि परिपथ अवरोधक जैसे उपकरणों के मरम्मत से संबंधित कार्यक्रम, तेल बदलने की अगली निर्धारित तिथि, भारित नल परिवर्तक परिचालन, अनुरक्षण कार्य की तिथियाँ, ग्रि.उ.के. के बैटरियों का निष्पादन, रिले का निष्पादन एवं फीडर विफलता के कारण-वार विश्लेषण के विवरण प्रतिवेदित नहीं किये जा रहे थे। इस प्रकार बोर्ड रक्षात्मक अनुरक्षण के बजाय केवल विफलता का अनुरक्षण कर रहा था।

- यद्यपि, बोर्ड ने संचरण संरचना के निर्माण के लिए पाँच वार्षिक योजनाओं में विभाजित एक दीर्घकालिक योजना तैयार किया था, वार्षिक योजना कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुश्रवण तंत्र नहीं था।

- ❖ शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में सहायता करने के लिए संचरण तंत्र पर एक विश्वसनीय एवं व्यापक एम.आई.एस. अस्तित्व में नहीं था तथा बोर्ड को बार-बार क्षेत्रीय इकाईयों से आँकड़े इकट्ठा करना पड़ता था।

- ❖ बोर्ड ने उर्जा आंकलनों का अनुश्रवण नहीं किया, क्योंकि निर्गत उर्जा आगत उर्जा से अधिक थी।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.35 बोर्ड के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आई.ए.डब्ल्यू.) है, परन्तु आई.ए.डब्ल्यू. को स्वीकृत बल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। तथापि, आई.ए.डब्ल्यू. में सात व्यक्ति कार्यरत[45] थे। आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल के अनुसार, आई.ए.डब्ल्यू. को त्रैमासिक कार्य योजना तैयार करना है। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए इकाईयों के चुनाव एवं मानवबल के तैनाती के लिए कार्य योजना नहीं बनाया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को मुख्यतः स्थापना संबंधी यथा वेतन निर्धारण, वेतनवृद्धि, पेंशन इत्यादि की समवर्त्ती लेखापरीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। ये अधिकारी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उत्तर देने के लिए बोर्ड की विभिन्न शाखाओं से भी सम्पर्क में रहते थे।

निष्कर्ष

बोर्ड के पास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त निधि नहीं थी एवं निधि के लिए जी.ओ.जे./आर.ई.सी. पर निर्भर था जिसके कारण, उन्हें विभिन्न ग्रि.उ.के.एवं संचरण लाइन के क्रियान्वयन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, जी.ओ.जे. द्वारा आवंटित एवं आर.ई.सी. द्वारा निर्गत किए गये निधियों का पूर्ण उपयोग योजना अवधि मे नहीं हो पाया। बोर्ड ने संचरण परियोजनाओं के लिए कार्यबल के प्रतिवेदन की अनुशसांओं का अनुपालन नहीं किया, जिसके कारण समयावृद्धि हुई और परियोजनाएँ मितव्ययी एवं दक्षतापूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई। संविदा/कार्यादेश निर्गत करते समय एन.आई.टी. के शर्तों एवं सी.वी.सी. के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। बोर्ड ने परिचालन एवं अनुरक्षण मैनुअल तथा ग्रि.उ.के. के रक्षात्मक अनुरक्षण की अनुसूची नहीं बनाई, अतः केवल विफलता अनुरक्षण कार्य किया जा रहा था। ग्रिड कोड के आवश्कतानुसार अधिक आहरण के संदर्भ में ग्रिड अनुशासन का पालन किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए क्रय किये गये आपातकालीन पुनर्स्थापन प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया। पी.टी.पी.एस. में डीजल जेनरेटर उपलब्ध नहीं थे तथा ग्रि.उ.के. में कार्य नहीं कर रहे थे। नमूना जाँचित ग्रि.उ.के. में से एक ग्रि.उ.के. के फीडर में मीटर नहीं लगा था एवं सात ग्रि.उ.के. में मीटर दोषपूर्ण थे जिसके कारण झा.रा.वि.नि.आ. द्वारा तय मानक से ज्यादा संचरण हानि हुई। यह एक अपर्याप्त उर्जा लेखांकन प्रणाली को इंगित करता है। बोर्ड ने मेटल डिटेक्टर के

[45] एक निदेशक, एक उपनिदेशक, दो लेखा अधिकारी, एक लेखापाल, एक लेखा सहायक तथा एक लेखा लिपिक (दिसम्बर 2012 तक)।

प्रावधान के लिए अतिसंवेदनशील अधिष्ठापनों की पहचान नहीं की। बोर्ड ने मितव्ययी अधिप्राप्ति एवं भंडार पर दक्षतापूर्ण नियंत्रण के लिए कोई अधिप्राप्ति नीति और भंडार नियंत्रण तंत्र का निर्धारण नहीं किया। शीर्ष स्तर पर त्वरित निर्णय लेने से संबंधित संचरण प्रणाली पर विश्वसनीय एवं व्यापक एम.आई.एस. अस्तित्व में नहीं था। आंतरिक लेखापरीक्षा का आकार बोर्ड की गतिविधियों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं था।

अनुशंसाएँ

बोर्ड विचार कर सकता है:

- कार्य बल के अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए संचरण योजनाओं को पूरा करने हेतु समयाविधि का पालन करे ताकि निधियों का उपयोग, मितव्ययी एवं प्रभावी तरीके से हो सके एवं उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाया जा सके।

- सभी ग्रि.उ.के. एवं फीडरों में उपयुक्त मीटर हों एवं दोषपूर्ण मीटरों को शीघ्रता से बदला जाए;

- डी.वी.सी. कमान क्षेत्र में संचरण लाईन स्थापित हो जिससे कम कीमत पर उर्जा क्रय का लाभ प्राप्त हो; तथा

- उच्च संचरण हानि के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जिससे यह झा.रा.वि.नि.आ. द्वारा तय अनुमेय सीमा के अंदर लाया जाए।

अध्याय-III

लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

अध्याय - III

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगम के लेन-देन की नमूना जाँच करने पर पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सन्निहित हैं।

सरकारी कम्पनियाँ

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

3.1 आयकर एवं अग्रिम कर की कम अदायगी के फलस्वरूप आयकर तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर विवरणी दाखिल करने में विलम्ब के कारण वर्ष 2007-08 के व्यापार लाभ के विरूद्ध वर्ष 2005-07 के दौरान हुए व्यापार हानि के विकलन में विफलता और 2007-10 वर्षों के लिए अग्रिम कर की नहीं/कम अदायगी करने के फलस्वरूप आयकर एवं आयकर पर ब्याज ₹ 85.51 लाख का परिहार्य भुगतान।

(क) आयकर अधिनियम,1961 (अधिनियम) की धारा 72 निर्दिष्ट करती है कि किसी कर-निर्धारण वर्ष में "व्यापार या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्ष में एक कम्पनी के द्वारा शुद्ध परिणाम हानि हो तो ऐसे हानि अगले क्रमवार आठ कर-निर्धारण वर्षों तक अग्रेषित की जा सकती है तथा क्रमवार वर्षों के लाभ, यदि कोई हो तो, विकलित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 80 यह निर्दिष्ट करती है कि कम्पनी उस हानि को अग्रेषित एवं विकलित तभी कर सकती है जब आयकर विवरणी को निर्धारित तिथि के दिन या पहले धारा 139 (1) के अधीन दाखिल किया हो।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों से हमने यह पाया (अक्टूबर 2011) कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 का आयकर विवरणी, क्रमशः ₹ 1.09 करोड़ और ₹ 11.02 लाख का घाटा दर्शाते हुए दाखिल किया। फिर भी आयकर विवरणियों को निर्धारित तिथि अर्थात संबंधित वर्ष के 30 सितम्बर तक दाखिल नहीं किया था, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित था। वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के आयकर विवरणियों को क्रमशः 31 मार्च 2008 और 9 जनवरी 2009 को दाखिल किया गया जिसकी वजह से कम्पनी हानि के अग्रेषण और विकलन करने के फायदे से वंचित रही। इस प्रकार, कम्पनी ने यद्यपि वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 2.93 करोड़ का लाभ अर्जित किया, वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान हुये कुल हानि ₹ 1.20 करोड़ को इस लाभ के विरूद्ध विकलित

नहीं कर सका। इस प्रकार, कम्पनी को ₹ 40.83 लाख[1] आयकर का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(ख) इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय है, जहाँ प्रत्येक मामले में वर्ष के दौरान करदाता के द्वारा देय कर दस हजार रूपये[2] या अधिक है। अधिनियम की धारा 234(बी) निर्दिष्ट करती है कि जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में, एक करदाता जो धारा 208 के अधीन अग्रिम कर की अदायगी के लिए उत्तरदायी है, कर अदायगी में चूक करता है या जहाँ करदाता द्वारा भुगतान किये गये अग्रिम कर, निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है तो करदाता को निर्धारित कर के विरूद्ध कम भुगतान किये गये अग्रिम आयकर पर अप्रैल की पहली तिथि से प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 234(सी), यह प्रावधान करती है कि यदि करदाता अग्रिम कर के भुगतान में चूक करता है या देय कर के अग्रिम कर का भुगतान 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर एवं 31 मार्च तक क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत से कम है तो करदाता उस कम राशि पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज अदायगी के लिए दायी होगा। धारा 234(ए) के प्रावधानों के अधीन, यदि किसी निर्धारित वर्ष का आयकर विवरणी, निर्धारित तिथि के बाद दाखिल किया जाता है तो प्रत्येक माह या माह के भाग पर, निर्धारित कर से कम भुगतान किये गये अग्रिम देय कर और कर-कटौती/स्रोत संग्रहण पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज भारित होता है।

हमने पाया कि कम्पनी ने अधिनियम की धाराएँ 234(ए), 234(बी) और 234(सी) के आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2009-10 का आयकर विवरणी निर्धारित तिथि के अंदर न तो दाखिल किया न ही अग्रिम-कर की अदायगी की, जिसकी वजह से ₹ 40.81 लाख ब्याज का भुगतान करना पड़ा। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए, अग्रिम कर के भुगतान किस्त में करने के बजाय एक करोड़ का भुगतान ₹ 95.52 लाख के निर्धारित कर के विरूद्ध मार्च 2009 में किया। जिसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 234(सी) के अंतर्गत ₹ 3.87 लाख का परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2012) कि आयकर विवरणी जमा करने में विलम्ब, लेखों के अंतिमीकरण में देरी के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, कम्पनी वर्ष 2007-08 में नीलामी द्वारा केन्दु पत्ते की बिक्री से प्राप्ति में अचानक वृद्वि को कल्पित नहीं कर सकी। उत्तर लेखाओं के समय पर अंतिमीकरण के निश्चितता में विफलता को रेखांकित करता है जिसके परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 में यद्यपि कम्पनी का बजटीय लाभ ₹ 5.80 करोड़, वास्तविक लाभ ₹ 2.88 करोड़ से बहुत अधिक था, कम्पनी अग्रिम-कर की अदायगी में विफल रही।

---

[1] ₹ 1,20,12,604 पर 30 प्रतिशत का आयकर (₹ 36.04 लाख) जोड़ आयकर राशि पर 10 प्रतिशत का अधिभार (₹ 3.60 लाख) जोड़ 3 प्रतिशत का शैक्षणिक उपकर (₹ 1.19 लाख)।

[2] वित्त अधिनियम, 2009 द्वारा 01.04.2009 से "पाँच हजार" का स्थानापन्न।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा निर्धारित समय के अंदर लेखों के अंतिमीकरण, अपने आय का सही आकलन, निर्धारित तिथि के अंदर आयकर विवरणी को दाखिल करने, देय अग्रिम-कर की राशि का निर्धारण और नियत समय के अंदर इसके प्रेषण में विफलता के परिणामस्वरूपः

- वर्ष 2007-08 के व्यापार लाभ के विरूद्ध, वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान हुए व्यापारिक हानियों के अग्रेषण एवं विकलन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से ₹ 40.83 लाख आयकर की अदायगी करनी पड़ी; तथा

- वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए अधिनियम की धारा 234(ए), 234(बी) और 234(सी) के अधीन ब्याज के रूप में ₹ 44.68 लाख का भुगतान करना पड़ा।

मामला सरकार को मई 2012 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2013)।

झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड

3.2 *श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली नहीं करना*

ठेकेदारों के विपत्रों से श्रमिकों के कल्याण उपकर की वसूली नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 18.28 लाख का अतिरिक्त दायित्व, इसके अलावा ब्याज एवं जुर्माना देय।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) को अधिसूचित किया (अगस्त 1996)। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, एक नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से निर्माण कार्य पर किये गये कुल लागत का कम से कम एक प्रतिशत उपकर लगाना और संग्रहित करना है। प्रावधान यह भी किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में उपकर का संग्रहण स्रोत पर कटौती के माध्यम से सा.क्षे.उ. के द्वारा किया जाएगा। अधिनियम की धारा 8 निर्दिष्ट करता है कि यदि नियोक्ता निर्धारण के आदेश में निहित समय के भीतर उपकर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस भुगतेय राशि पर दो प्रतिशत की दर से प्रत्येक महीने या प्रत्येक महीने के भाग पर, ब्याज भुगतान के लिए उस समय तक उत्तरदायी होगा जब तक की उस राशि का वास्तविक भुगतान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, धारा 9 उल्लेख करता है कि निर्धारण अधिकारी उपकर की राशि में चूक से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकता है।

राज्य सरकार ने झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (कल्याण बोर्ड) का गठन किया (जुलाई 2008)। अधिनियम की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य सरकार सभी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य

सरकारी एजेंसियों/निकायों, जो कोई भवन और अन्य निर्माण में कार्यरत हैं, को कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर की कटौती को लागू करने और उस राशि को कल्याण बोर्ड में प्रेषित करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2008)।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2012) कि झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने जनवरी 2009 से मार्च 2010 तक की अवधि के दौरान, ठेकेदारों को भवन और अन्य निर्माण कार्य हेतु ₹ 18.28 करोड़ का ठेका दिया, लेकिन निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के शर्त्तों में उपकर की वसूली से संबंधित विशिष्ट उपवाक्य सम्मिलित नहीं किया। परिणामतः, राज्य सरकार के विशेष निर्देश (दिसम्बर 2008) के बावजूद कम्पनी ने ठेकेदारों को भुगतान करते समय ₹ 18.28 लाख की उपकर की कटौती नहीं की। कम्पनी ने मार्च 2010 के बाद ठेकेदारों से किये गये संविदाओं में उपकर की कटौती का प्रावधान सम्मिलित किया और उपकर की नियमित वसूली तथा जमा कल्याण बोर्ड को करता रहा है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा जनवरी 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान निर्गत एन.आई.टी. में उपकर के लागू करने से संबंधित उपवाक्य को सम्मिलित करने में विफलता के परिणामस्वरूपः

i) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ;

ii) स्रोत पर उपकर की कटौती न करने से ₹ 18.28 लाख का अतिरिक्त दायित्व;

iii) उपकर की कटौती एवं जमा न होने पर ब्याज एवं जुर्माने का दायित्व;

iv) उपकर की कटौती नहीं होने तक कल्याण बोर्ड के संसाधनों में संवर्धन नहीं हुआ।

मामला प्रबंधन/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012); उनके उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2013)।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

3.3 कंडक्टर की अधिप्राप्ति पर निधियों का अवरोध

कार्य निष्पादन के लिए ठोस योजनाओं के बिना ए.सी.एस.आर. डॉग कंडक्टर की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप ₹ 95.74 लाख निधि का अवरोध और कम्पनी को ₹ 78.83 लाख का परिहार्य ब्याज का बोझ।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी), अपने तेनुघाट वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (टी.टी.पी.एस.) से उर्जा उत्पादन करता है और इसे दो फीडरों बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बिहारशरीफ ग्रीड और झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) के पतरातू स्वीचयार्ड द्वारा आपूर्त्ति करता है। उर्जा की विफलता के दौरान, टी.टी.पी.एस. को झा.रा.वि.बो. के कथारा-लालपनिया 33 के.वी. लाइन (लाइन) से बैक-अप उर्जा लेने की व्यवस्था थी। तथापि, कम्पनी को यह बैक-अप उर्जा का वैकल्पिक स्रोत जनवरी 2004 से उपलब्ध नहीं था चूँकि पावर कंडक्टर की चोरी हो जाने के कारण लाइन संचालन में नहीं था। लाइन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने लाइन के पुनर्स्थापन कार्य को करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2006)।

हमने पाया (मार्च 2012) कि कम्पनी ने 128 किलोमीटर का ए.सी.एस.आर. डॉग कंडक्टर[3] (कंडक्टर) की आपूर्त्ति हेतु एक क्रय आदेश तत्कालिक आधार पर जारी किया (जुलाई 2006)। 12 जुलाई 2006 को सामग्री प्राप्त हुआ और ₹ 99.87 लाख का भुगतान माल ढुलाई भाड़ा, उत्पाद शुल्क और करों सहित किया गया (20 जुलाई 2006)।

तथापि, हमने पाया कि लाइन के महत्व को देखते हुए कार्य की अत्यावश्यकता के बावजूद कम्पनी ने लाइन के निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञता के कमी के कारण, इसके पुनर्स्थापन का कार्य नहीं किया था। फलस्वरूप, कंडक्टर जो लाइन के निर्माण के लिए तत्कालिक आधार पर अधिप्राप्त की गई थी, इसके अधिप्राप्ति के छः वर्ष के बाद भी बिना उपयोग के रही। कम्पनी कंडक्टर का उपयोग अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए भी नहीं कर सका और टी.टी.पी.एस. के टाउनशिप के रख रखाव के कार्य के लिए केवल 5.291 किलोमीटर कंडक्टर जारी किया (नवम्बर 2012 तक)।

प्रबंधन, ने तथ्य को स्वीकारते हुए, कहा (जुलाई 2012) कि कार्य को पूर्ण कराने के लिए झा.रा.वि.बो. को कई बार अनुरोध किया गया था और अभी उन्होंने तथ्य की जाँच करने तथा कार्य को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि लेखापरीक्षा के द्वारा मामले को उजागर करने के बाद ही कम्पनी ने झा.रा.वि.बो. से लाईन की पुनर्स्थापन के मामले को लिया था (जून 2012)।

[3] ए.सी.एस.आर (अल्युमुनियम कंडक्टर स्टील रिइन्फोसर्ड) कंडक्टर महीन मजबूत लेपित इस्पात कोर के साथ अल्युमुनियम तार के कई परत से बना होता है। इनका प्रयोग संचरण एवं वितरण केबल के रूप में होता है, डॉग कंडक्टर का आकार 36/4.72 ॐ 7/1.57 मि.मी. का होता है।

इस प्रकार, लाईन के पुनर्स्थापना के लिए बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञता के ही कंडक्टर की अधिप्राप्ति की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.74 लाख[4] की निधि अवरूद्ध हुई और कम्पनी को अवरूद्ध निधि पर ₹ 78.83 लाख[5] ब्याज का परिहार्य बोझ हुआ।

मामला सरकार को जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

3.4 झारखण्ड राज्य के सरकारी कम्पनियों में निगमित शासन

3.4.1 प्रस्तावना

निगमित शासन प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सिद्धान्तों का एक समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी का शासन सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है। निगमित शासन एक सैद्धांतिक प्रक्रिया और संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से कम्पनी के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यह मूलतः प्रणाली को सूचित करता है जिसके द्वारा हितधारकों के हित में निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) द्वारा कम्पनी को निर्देश और नियंत्रण किया जाता है। निगमित शासन, कम्पनी के मामले में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता हैः

- निगमित उद्धेश्यो की प्राप्ति हेतु पर्याप्त प्रकटीकरण और प्रभावी निर्णय;
- व्यापारिक लेनदेनों में पारदर्शिता;
- सांविधिक और कानूनी अनुपालन;
- शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा;
- व्यापार के मूल्यों और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता; तथा
- बेहतर और ससमय वित्तीय प्रतिवेदित करना।

निदेशक मंडल अपनी कम्पनी के शासन के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य घटकें जो निगमित शासन की तंत्रों की रचना करते हैं वे निदेशक मंडल, निदेशकों के प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा समिति के गठन से संबंधित मामले है।

भारत में निगमित शासन के लिए कानूनी और नियामक ढाँचे कम्पनी अधिनियम, 1956 और सेबी के दिशा-निर्देशों से, जो सूचीबद्ध कम्पनियों में लागू है, शासित है। झारखण्ड में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है (***परिशिष्ट-9***), जिनमें से कोई भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध नहीं है। अतः सेबी के दिशा–निर्देश, उन पर लागू नहीं होते हैं।

[4] ₹ 99,86,847 x 122.709/128।

[5] ₹ 95,74,041 पर 13 प्रतिशत की दर से (नवम्बर 2012 तक 76 महीने के लिए)।

हमने, 2007 -08 से 2011-12 की अवधि के लिए नौ कम्पनियों[6] में निगमित शासन के प्रणाली का, विभिन्न सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं पर इन कम्पनियों के अनुपालन के निर्धारण के उद्देश्य से, समीक्षा किया।

3.4.2 *निदेशक मंडल*

सुशासन का उत्तरदायित्व निगम मंडल पर निहित होता है जिसका प्राथमिक कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित शासन के लिए कानून में सन्निहित सिद्धान्तों का स्वेच्छा से पालन हो रहा है और हितधारकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस प्रयोजन हेतु यह अत्यावश्यक है कि प्रत्येक कम्पनी को नियमित अंतराल पर निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करनी चाहिए। प्रत्येक निदेशक को इन बी.ओ.डी. की बैठकों में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने के लिए और कम्पनी के मामलों में मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित होना चाहिए।

निदेशक मंडल की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक कम्पनी को अपने बी.ओ.डी. की बैठक, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार और प्रत्येक वर्ष कम से कम चार ऐसे बैठक का आयोजन करनी चाहिए। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान आयोजित बी.ओ.डी. के बैठक से संबंधित विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट- 10*** में दर्शाये गये हैं।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि सभी नौ कम्पनियाँ, जिसकी निगमित शासन की प्रणाली की जाँच की गई थी, कम्पनी अधिनियम की धारा 285 के प्रावधान का पाँच से 15 बार तक उल्लंघन किया था। जिडको ने 15 ऐसे बैठक आयोजित नहीं किया जब कि टी.वी.एन.एल., जे.पी.एच.सी.एल., जे.टी.डी.सी., जे.एस.एम.डी.सी. और जी.आर.डी.ए. ने दस या उससे अधिक अवसरों पर सांविधिक प्रावधानों से विचलित हुए। जे.एस.एम.डी.सी. और जिडको के दो बी.ओ.डी. की बैठक के बीच में अधिकतम अंतराल क्रमशः 25 महीने और 21 महीने था।

हमने पुनः पाया कि टी.वी.एन.एल. में पिछले बैठक से 10 महीने से 15 महीने के अन्तराल पर बी.ओ.डी. की तीन बैठक[7] हुई। मई 2010 को हुई बी.ओ.डी. की 27वीं बैठक में अध्यक्ष ने पाया कि त्वरित नीतिगत निर्णय सुनिश्चित करने के लिए बी.ओ.डी. की बैठक कम अंतराल पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी के बी.ओ.डी. की बैठक आयोजित करने में देरी के कारण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय, जिसे लेने का अधिकार केवल बोर्ड पर निहित था,

[6] झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको), झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.), झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.), झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.), ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.) तथा झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)।

[7] 22वीं बैठक दिसम्बर 2007 में, 26वीं बैठक मई 2009 में और 27वीं बैठक मई 2010 में हुआ।

अध्यक्ष के द्वारा लिये गये तथा उन्हें बोर्ड की अगली बैठक में पोस्ट फैक्टों अनुमोदन के लिए रखा गया।

इस प्रकार, इन कम्पनियों के प्रबंधक कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान को पालन करने में विफल रहे थे।

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

परिशिष्ट-11 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान, आठ कम्पनियों[8] में हुए बी.ओ.डी. की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निर्दिष्ट करता है। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि हमारे द्वारा समीक्षा किये गये अवधि के दौरान टी.वी.एन.एल. में बोर्ड की सभी बैठक में सभी निदेशक उपस्थित थे। अन्य सात कम्पनियों में, इस अवधि के दौरान निदेशक अपने कार्यकाल में 131 बैठक में से 39 बैठक में ही उपस्थित थे, चार कम्पनियों[9] से संबंधित आठ निदेशक बोर्ड के किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं थे जबकि 23 निदेशक अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की दो से 10 बैठक में से एक से चार बैठक में ही उपस्थित हुए। यह इंगित करता है कि निदेशकों ने कम्पनियों के प्रबंधन मामले में और कम्पनियों/हितधारकों के हित की रक्षा से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भाग नहीं लिया।

प्रबंध निदेशकों के बारम्बार परिवर्तन एवं निदेशकों की रिक्तियाँ

शीर्ष कार्यकारियों में बारम्बार परिवर्त्तन से कम्पनी के सुचारू कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ***परिशिष्ट-12*** 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान प्रबंध निदेशकों का विवरणी दर्शाता है जिनके कार्यकाल एक वर्ष से कम थे। यह देखा जा सकता है कि 2007-12 की समयावधि में, हमारे द्वारा समीक्षा किये गये नौ कम्पनियों में से पाँच कम्पनियों जैसे टी.वी.एन.एल., जे.पी.एच.सी.एल., जे.टी.डी.सी., जे.एस.एम.डी.सी. और जी.आर.डी.ए. के आठ प्रबंध निदेशक के कार्यकाल 23 दिनों से 11 महीने 21 दिनों के बीच में थे। इसके अलावा, 2007-12 की अवधि के दौरान टी.वी.एन.एल. के अध्यक्ष का पद करीब 19 महीने[10] तक और प्रबंध निदेशक का पद दो महीने सात दिनों तक रिक्त थे। अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के पद में बारम्बार परिवर्तन और रिक्तियों के परिणामस्वरूप, नियमित रूप से और समय पर बी.ओ.डी. की बैठक नहीं हो सकी। जे.एस.एम.डी.सी. में प्रबंध निदेशक का पद दो महीने और 14 दिनों तक रिक्त था। 2007-12 की अवधि में जे.पी.एच.सी.एल. में एक निदेशक का पद कई दौर में कुल दो वर्ष सात महीने के अवधि के लिए रिक्त था।

[8] झालको द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी।

[9] जिडको, जे.एस.एफ.डी.सी., जे.एस.एम.डी.सी. और जे.टी.डी.सी.।

[10] 01.04.2007 से 17.12.2007; 18.06.2008 से 01.03.2009 और 29.05.2011 से 05.08.2011।

निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त का प्रस्तुतीकरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 193 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक आम सभा तथा निदेशक बोर्ड या बोर्ड की प्रत्येक समिति की, प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त, प्रत्येक ऐसे बैठक के समाप्ति के तीस दिनों के अंदर बनाकर रखना होगा, जिसे एक पंजी में दर्ज किया जाएगा जिसके पन्नों पर क्रमागत संख्या अंकित रहनी चाहिए, प्रत्येक पन्ने में अध्यक्ष का अद्याक्षर और अंतिम पृष्ठ पर उसी बैठक के अध्यक्ष या अगले बैठक के अध्यक्ष के तिथि सहित हस्ताक्षर होनी चाहिए।

हमने निम्नलिखित अवलोकित कियाः

- यद्यपि जे.टी.डी.सी. कार्यवृत्त पुस्तक का अनुरक्षण किया, लेकिन इनमें 2007-08 से प्रविष्टियाँ नहीं की थी।

- जी.आर.डी.ए. में, आयोजित आठ बैठक में से केवल एक बैठक की कार्यवृत्त हस्ताक्षरित थी।

- झारक्राफ्ट में, आयोजित 13 बैठक में से चार बैठक की कार्यवृत्त बिना तिथि के हस्ताक्षरित थे, सात बैठक की कार्यवृत्त एक महीना 27 दिनों से छः महीने दो दिनों की देरी के बाद हस्ताक्षरित हुए थे तथा 13वीं बैठक की कार्यवृत्त मार्च 2012 तक अहस्ताक्षरित थे।

- 2007-08 के दौरान जे.पी.एच.सी.एल. में 15 आयोजित बैठक में से, बैठक की तीन कार्यवृत्त बिना तिथि के हस्ताक्षरित थे तथा शेष बैठक की कार्यवृत्त के हस्ताक्षर में 16 दिनों से आठ महीने आठ दिनों तक की देरी हुई थी।

- जे.एस.एफ.डी.सी. में 16 आयोजित बैठकों में से केवल एक बैठक की कार्यवृत्त पर अद्याक्षर एवं हस्ताक्षर थे; 13 बैठक में कार्यवृत्त के हस्ताक्षर में 15 दिनों से चार महीने 20 दिनों तक की देरी पायी गयी जबकि दो बैठक में कार्यवृत्त न तो हस्ताक्षरित थे न ही अद्याक्षरित किए गए थे।

- टी.वी.एन.एल. में, 14 बैठक के केवल एक कार्यवृत्त उचित समय पर हस्ताक्षरित था, दो कार्यवृत्त पर अद्याक्षर थे लेकिन कार्यवृत्त-पुस्तक के अंतिम पृष्ठ अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे जबकि बैठकों की शेष कार्यवृत्त न ही हस्ताक्षिरत न ही अद्याक्षरित थे।

शेयरधारकों को निदेशकगणों का प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 217(2एए), अपेक्षा करता है कि बी.ओ.डी. शेयरधारकों को प्रतिवेदित करेगा कि कम्पनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी के साथ लेखा अभिलेखों का रख रखाव किये गये हैं। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठा के साथ बी.ओ.डी. के एक प्रतिवेदन, निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित विवरण सहित कम्पनी के वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जाना है।

हमने पाया कि सभी नौ कम्पनियाँ, कम्पनी के वार्षिक आम सभा (ए.जी.एम.) में प्रत्येक आर्थिक चिट्ठा के साथ निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित विवरणी को सम्मिलित किए थे।

लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए अपेक्षा करता है कि प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जिसकी चूकता पूँजी पाँच करोड़ रूपये से कम न हो, बोर्ड स्तर पर, एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगा।

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के निर्धारण और समीक्षा करने का है तथा यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरणियाँ सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है। वार्षिक लेखे के अंतिमीकरण के पहले यह समिति, सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ सभी मुद्दों पर अनुवर्तन और विचार-विमर्श करता है। यह आंतरिक नियत्रंण प्रणाली की पर्याप्तता और अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखापरीक्षक के साथ विचार-विमर्श करता है एवं उस पर अनुवर्त्ती कार्यवाही की समीक्षा करता है। यह वित्तीय और जोखिम प्रबंधन की भी समीक्षा करता है और आंतरिक छानबीन के निष्कर्षो का मूल्यांकन करता है, जहाँ कोई संदिग्ध धोखाधड़ी, अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वृहद प्रकृति के विफलता है तथा इस संबंध में बोर्ड को प्रतिवेदित करता है।

हमारे द्वारा समीक्षित नौ कम्पनियों में से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए केवल एक कम्पनी[11] अर्थात्, झारक्राफ्ट में वर्ष 2009-10 से लागू था। तथापि, हमने अवलोकित किया कि कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन न करते हुए अब तक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है।

हमने, पुनः अवलोकित किया कि टी.वी.एन.एल. एक विद्युत उत्पादन से जुड़ी निजी लिमिटेड कम्पनी, जिसका चुकता पूँजी ₹ 105 करोड़ है, का 16 वर्षों से वार्षिक लेखे 1996-97 से बकाये है। अतः कम्पनी लेखे के त्वरित अंतिमीकरण एवं अनुश्रवण के लिए लेखापरीक्षा समिति के गठन पर विचार कर सकती है।

[11] अन्य आठ कम्पनियाँ जो सरकारी कम्पनियाँ भी है, पर निजी कम्पनी की तरह पंजीकृत है इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए की आवश्यकता से मुक्त है।

3.4.3 प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता

कम्पनी निबंधक के पास वार्षिक रिटर्न का दाखिल करना

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी के शेयर पूँजी होने पर, अपने पंजीकृत कार्यालय, इसके सदस्यों एवं ऋण धारकों का विवरण, अंश पूँजी और ऋण-पत्र इत्यादि और इसके निदेशकों, प्रबंध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करते हुए, वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्रोफार्मा में कम्पनी निबंधक को वार्षिक आम सभा आयोजित होने के दिन से 60 दिनों के अंदर दाखिल करेगा। यदि किसी वर्ष में किसी कम्पनी का वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं होता है, जिस दिन को वार्षिक आम बैठक होनी चाहिए उस दिन से 60 दिनों के अंदर या इससे पहले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिटर्न निबंधक के पास दाखिल करना होगा।

कम्पनी के द्वारा कम्पनी निबंधक को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी से संबंधित विवरणी ***परिशिष्ट-13*** में निर्दिष्ट किया गया है। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि 2007-12 के अवधि के दौरान, जे.एस.एम.डी.सी. ने वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, टी.वी.एन.एल. ने 1993-94 से वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है जबकि चार कम्पनियाँ अर्थात् झालको, जिडको, झारक्राफ्ट और जे.टी.डी.सी. एक से चार वित्तीय वर्षो का वार्षिक रिटर्न को दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा, सभी सात कम्पनियों ने प्रायः सभी वर्षों में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने मे 20 दिनों से तीन वर्ष दस महीने तक की देरी की है।

आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता का कम्पनी निबंधक को दाखिल करना

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 निर्दिष्ट करता है कि कम्पनी के वार्षिक आम बैठक में आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता प्रस्तुत करने के पश्चात उसे 30 दिनों के अंदर कम्पनी निबंधक को दाखिल करेगा। यदि किसी वर्ष में किसी कम्पनी का वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं होता है, जिस दिन को वार्षिक आम बैठक होनी चाहिए उस दिन से 30 दिन के अंदर या इससे पहले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता निबंधक के पास दाखिल करना होगा।

कम्पनियों के द्वारा 2007-08 से 2011-12 के अवधि के दौरान आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता कम्पनी निबंधक के पास दाखिल करने संबंधित विवरणी ***परिशिष्ट-14*** में निर्दिष्ट है। हमने पाया कि जे.एस.एम.डी.सी. और जी.आर.डी.ए. अपने स्थापना से ही आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता कम्पनी निबंधक को जमा नहीं किया था जबकि झालको ने वर्ष 2004-05 से आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता कम्पनी निबंधक को जमा नहीं किया है। टी.वी.एन.एल. ने भी अपने आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता दाखिल नहीं किया है चूँकि कम्पनी ने 1996-97 से अपने वार्षिक लेखे का अंतिमीकरण नहीं किया है। 2007-12 की अवधि

के दौरान पाँच[12] कम्पनियाँ आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता को दाखिल करने में एक महीना 17 दिनों से चार वर्ष चार महीने तक की देरी की है।

3.4.4 *सामान्य*

कम्पनी सचिव की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383(ए) यह निर्दिष्ट करता है कि सभी कम्पनियाँ जिनकी चुकता पूँजी पाँच करोड़[13] रूपये से कम न हो, एक पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त करेगा। 15 मार्च 2009 तक छः कम्पनियों[14] के पास दो करोड़ से अधिक की चुकता अंश पूँजी थी जिसमें से केवल दो (जिडको और जे.एस.एम.डी.सी.) कम्पनियों में पूर्णकालिक कम्पनी सचिव कार्यरत थे। 15 मार्च 2009 के पश्चात यद्यपि पाँच कम्पनियों (झालको, जिडको, झारक्राफ्ट, जी.आर.डी.ए. और टी.वी.एन.एल.) के पास पाँच करोड़ रूपये से अधिक की चुकता अंश पूँजी थी, केवल झालको और जी.आर.डी.ए. में इस अवधि में अंशकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त किया था जबकि टी.वी.एन.एल. ने 17 मई 2011 तक अशंकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त किया था और 5 सितम्बर 2011 से पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त किया। झारक्राफ्ट ने 23 मार्च 2011 तक कोई पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति नहीं किया जबकि 2008-09 से इसे एक पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता थी। इस प्रकार कम्पनियाँ ने 2007-12 के अधिकांश अवधि के दौरान या तो कम्पनी सचिव की नियुक्ति नहीं की या अंशकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति की और इस प्रकार कम्पनी अधिनियम की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया।

वार्षिक आम सभा एवं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति

अधिनियम की धारा 166 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी वार्षिक आम सभा के रूप में एक आम सभा प्रत्येक वर्ष आयोजित करेगा तथा इसके अगले सभा की तारीख के बीच पंद्रह महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कम्पनी, अधिनियम की धारा 210 के अनुसार कम्पनी का वार्षिक लेखा अर्थात् आर्थिक चिट्ठा और लाभ व हानि खाता, वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः महीने या एक कम्पनी के संबंध में प्रथम वार्षिक आम सभा के आयोजन के नौ महीने के अंदर बनाने का उत्तरदायी है।

2007-08 से 2011-12 के अवधि के दौरान कम्पनियों के द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा से संबंधित विवरणी ***परिशिष्ट-15*** में निर्दिष्ट किया गया है। हमने पाया कि 2007-12 के अवधि के दौरान दो कम्पनियाँ अर्थात् जे.पी.एच.सी.एल. और जे.एस.एफ.डी.सी. अपने वार्षिक आम सभा का आयोजन नियमित रूप से किए जब कि सात कम्पनियाँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया। टी.वी.एन.एल. इस अवधि के दौरान कोई वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं किया

[12] जिडको, झारक्राफ्ट, जे.पी.एच.सी.एल., जे.टी.डी.सी. और जे.एस.एफ.डी.सी.।

[13] 15 मार्च 2009 से ₹ पाँच करोड़, पहले यह ₹ दो करोड़ था।

[14] झालको, जिडको, जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी. और टी.वी.एन.एल.।

चूँकि इसने इस दौरान किसी भी वर्ष के लेखे का अंतिमीकरण नहीं किया। अन्य छः कम्पनियाँ अर्थात् जे.टी.डी.सी., झारक्राफ्ट, झालको, जे.एस.एम.डी.सी., जी.आर.डी.ए. और जिडको ने एक से पाँच वर्षो तक अपने वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किये और इस प्रकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहे।

झारक्राफ्ट में, बोर्ड सात निदेशकों से समाविष्ट थे जिसमें इस अवधि के दौरान आयोजित पाँच वार्षिक आम सभा में से चार वार्षिक आम सभा में केवल दो से चार निदेशक उपस्थित हुए जबकि जे.एस.एफ.डी.सी. में सात पदस्थापित निदेशकों में से दो से पाँच की वार्षिक आम सभा में उपस्थिति थी। जे.पी.एच.सी.एल. में कम्पनी के द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा में (पाँचवीं स्थगित वार्षिक आम सभा को छोड़कर) आठ पदस्थापित निदेशकों में से केवल तीन से चार निदेशक ही उपस्थित थे।

मामला प्रबंधन/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2012); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

3.4.5 निष्कर्ष

- अधिकांश कम्पनियों में बोर्ड की बैठक का नियमित रूप से आयोजन नहीं किया गया जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन था;
- बोर्ड की बैठक और वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति अनियमित था;
- अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार निदेशक मंडल के बैठक की कार्यवृत्त उचित ढंग से नहीं रखे गये थे;
- झारक्राफ्ट के द्वारा लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था;
- अनिवार्य अनुपालन संबंधित दाखिले अर्थात् वार्षिक रिटर्न और आर्थिक चिट्ठे तथा लाभ व हानि खाता को निर्धारित तिथि के अंदर कम्पनी निबंधक को नहीं किये गये थे;
- अधिनियम के आवश्यकतानुसार कम्पनी सचिवों की नियुक्ति नहीं की गयी थी;
- कम्पनियों ने प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया; और
- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159, 166, 193, 220, 292 (ए) और 383 (ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना एक दण्डनीय अपराध है जिसमें जेल और ₹ 500 से ₹ 50,000 तक का जुर्माना होता है। इस प्रकार, दोषी कम्पनियाँ कानूनी आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दण्डात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी है।

सांविधिक निगम

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

3.5 डी.सी.एस. नियंत्रक काड्र्स की अधिप्राप्ति में देरी के कारण उत्पादन की हानि

वार्षिक रख-रखाव अनुबंध करने में बोर्ड की विफलता, अतिरिक्त नियंत्रक काड्र्स की भंडार में अनुपलब्धता और वितरित नियंत्रण प्रणाली के लिए नियंत्रक काड्र्स की अधिप्राप्ति में विलंब के परिणामस्वरूप पी.टी.पी.एस. की इकाई संख्या-4, 516.50 घंटा तक बंद रहा। इसके फलस्वरूप 17.97 एम.यू. की विद्युत उत्पादन की हानि तथा ₹ 2.53 करोड़ के अंशदान की हानि हुई।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का एक वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान पतरातू में है। पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (पी.टी.पी.एस.) की इकाई संख्या-4 का संचालन वितरित नियंत्रण प्रणाली (डी.सी.एस.) द्वारा नियंत्रित होता है। ए.बी.बी. लिमिटेड ने ₹ 1.07 करोड़ की लागत पर पी.टी.पी.एस. की इकाई संख्या-4 (40 मेगावाट क्षमता) के डी.सी.एस. (डेल निर्मित) को एक वर्ष के वारंटी के साथ 2008 में स्थापित और चालू किया था। इसमें पाँच कार्य स्थलों (डाटा पहुँचाने और तार्किक कार्य के लिए एक अभियांत्रिकी स्थल सहित), सर्वर और अन्य डी.सी.एस. पैनल इकाई नियंत्रण कक्ष में शामिल था।

हमने पाया (फरवरी 2012) कि इकाई संख्या-4 के डी.सी.एस. के दो कार्य स्थल, उनके लघु कम्प्यूटर प्रणाली इन्टरफेस (एस.सी.एस.आई.) नियंत्रक कार्ड्स जो कम्प्यूटर और सर्वर के बीच संवाद का काम करता है की क्षति होने के कारण क्रमशः 18 सितम्बर 2010 और 3 अक्टूबर 2010 को बंद हो गये। पी.टी.पी.एस. के द्वारा वितरित नियंत्रण प्रणाली (डी.सी.एस.) के मरम्मत/रख-रखाव का वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए.एम.सी.) नहीं किया गया था और एस.सी.एस.आई. नियंत्रक काड्र्स/अतिरिक्त कम्प्यूटर प्रणाली भी पी.टी.पी.एस. के भंडार में उपलब्ध नहीं थे। पी.टी.पी.एस. के उपयोगकर्त्ता विभाग[15] ने ए.बी.बी. से मालिकाना आधार पर डेल निर्मित डी.सी.एस. के लिए कम्प्यूटर के पूरे सेट की अधिप्राप्ति के लिए तत्काल आवश्यकता प्रस्तुत किया (9 नवम्बर 2010)। संयंत्र प्रबंधन ने एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड्स के क्रय के लिए 26 नवम्बर 2010 को डेल इंडिया, बंगलोर और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आई.एल., कोटा) से 17 जनवरी 2011 को पूछताछ किया था, परन्तु उनसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बावजूद, बोर्ड ने मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए एस.सी.एस.आई. नियंत्रक कार्ड की आपूर्ति के लिए किसी अन्य आपूर्तिकर्त्ता को खोजने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसी बीच अन्य तीन कार्य स्थलों (अभियांत्रिकी स्थल सहित) के एस.सी.एस.आई. नियत्रंक कार्ड्स 20 जुलाई 2011, 2 अगस्त 2011 और 22 अगस्त 2011 को खराब हो गये जिसके कारण इकाई संख्या-4 को 22 अगस्त 2011 से बंद करना

[15] इकाई संख्या-4 का विद्युत अनुरक्षण विभाग।

पड़ा। इकाई बंद होने के बाद ही बोर्ड द्वारा एस.सी.एस.आई. नियत्रंक काड्र्स के लिए एक अन्य आपूर्तिकर्त्ता (जाको कम्प्यूटर्स, मुम्बई) को इंटरनेट के माध्यम से खोजा (26 अगस्त 2011) तथा ₹ 71,400 के मूल्य पर पाँच एस.सी.एस.आई. नियत्रंक कार्ड्स के क्रय हेतु एक आदेश निर्गत किया (30 अगस्त 2011)। एस.सी.एस.आई. नियत्रंक कार्ड्स की प्राप्ति और स्थापना (11 सितम्बर 2011) होने के बाद इकाई संख्या-4 में विद्युत उत्पादन 12 सितम्बर 2011 से पुनः प्रारम्भ हो गया। पी.टी.पी.एस. की इकाई संख्या-4, 22 अगस्त 2011 से 11 सितम्बर 2011 (516.50 घंटे) तक बंद रही जिसके कारण 17.97 एम.यू.[16] की उत्पादन हानि और ₹ 2.53 करोड़[17] की अंशदान हानि हुई। कंट्रोलर काड्र्स की लागत जो मात्र ₹ 0.71 लाख थी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की अर्कमणयता बोर्ड के हितो के लिए हानिकारक साबित हुआ।

बोर्ड ने कहा (सितम्बर 2012) कि संयंत्र के लिए डी.सी.एस. नया था और वे अनभिज्ञ थे कि मूल आपूत्तिकर्त्ता को छोड़कर कहाँ से नियंत्रक कार्ड्स की प्राप्ति की जाय। कई बार सम्पर्क करने के बाद भी फर्म (आई.एल., कोटा) से प्रतिक्रिया की कमी की वजह से ए.एम.सी. नहीं हो सका। ए.एम.सी. करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्तर, ए.एम.सी. करने में तथा एस.सी.एस.आई. नियत्रंक कार्ड्स की समय पर अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने में बोर्ड की विफलता की पुष्टि करता है।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा ए.एम.सी. करने में विफलता, अतिरिक्त नियत्रंक काड्र्स न रखने तथा इकाई संख्या-4 के डी.सी.एस. के लिए नियंत्रक काड्र्स की अधिप्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप इकाई बंद रही जिसके कारण 17.97 एम.यू. की उत्पादन हानि तथा ₹ 2.53 करोड़ की अंशदान की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012); उनके उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2013)।

सामान्य

3.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

3.6.1 भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों मे रखे गए खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यकारी से प्रतिक्रिया तथा उपयुक्त समय में उत्तर प्राप्त करें।

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः जुलाई 2009 ,अगस्त 2010, अगस्त 2011 एवं सितम्बर 2012 में रखे गये थे। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित चार विभागों के अन्तर्गत पाँच सा.क्षे.उ. से संबंधित 25 कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा में से

[16] 87 % पी.एल.एफ. पर 40 एम डब्ल्यू. भार x 516.50 परिचालन घंटे/1000।

[17] 17.97 एम.यू. x ₹ 1.41 {अंशदान की हानि प्रति इकाई अर्थात 2010-11 में औसत बिक्री वसूली प्रति इकाई (₹ 2.96) - परिवर्तनीय लागत प्रति इकाई (₹ 1.55)}।

24 कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित उत्तर सरकार से 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए हैं जैसा की नीचे इंगित किया गया है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2007-08	9	3	8
2008-09	5	2	5
2009-10	7	2	7
2010-11	4	3	4
कुल	**25**		**24**

विभागावार विश्लेषण ***परिशिष्ट-16*** में दिया गया है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.6.2 वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, 35 कंडिकाएं तथा आठ निष्पादन लेखापरीक्षाएं सम्मिलित की गयी थी। इनमें से 30 सितम्बर 2012 तक सात कंडिकाओं तथा तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 2001-02 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तीन कंडिकाओं एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में कोपू ने अनुशंसाएँ की थी।

कोपू की कार्य प्रणाली नियमावली के अनुसार संबंधित विभागों को कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एन.) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालाँकि विभागों द्वारा ए.टी.एन. हमें कोपू द्वारा ए.टी.एन. की चर्चा के समय ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.6.3 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तथा तत्काल निस्तारित ना हुए लेखापरीक्षा अवलोकनों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, संबंधित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से छः सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मार्च 2012 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि 357 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1388 कंडिकाएं सितम्बर 2012 के अंत तक अनिस्तारित रही। 30 सितम्बर 2012 के अंत तक विभागावार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का विवरण ***परिशिष्ट-17*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिका एवं निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह के अंदर तथ्यों एवं आकंड़ों की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित प्रेषित की जाती है। मई से जुलाई 2012 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित पाँच प्रारूप कंडिकाओं एवं एक

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में से केवल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर सरकार से अभी तक (जनवरी 2013) प्राप्त हुए थे तथा प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2013) जिसका विवरण ***परिशिष्ट-18*** में दिया गया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) उन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में रहे जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ब) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिम/अधिभुगतान को वसूल करने की कार्यवाही हो और (स) लेखापरीक्षा अवलोकनों के उत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया गया है।

मृदुला सप्रू

राँची **(मृदुला सप्रू)**
दिनांक : **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक : **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2012 को प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति को दर्शाता अद्यतन विवरणी

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

(कॉलम 5(क) से 6(घ) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2011-12 के अन्त में बकाया ऋण				2011-12 के ऋण अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं संबद्ध													
1.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	27.3.2002	5.00	–	–	5.00	–	–	–	–	–	328
2.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.3.2002	500.00	–	–	500.00	525.00	–	–	525.00	1.05:1	236
प्रक्षेत्रवार कुल				**505.00**	**-**	**-**	**505.00**	**525.00**	**-**	**-**	**525.00**	**1.04:1**	**564**
आधारभूत संरचना													
3.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	15.12.2004	900.00	–	–	900.00	–	–	–	–	–	10
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	गृह	13.03.2002	200.00	–	–	200.00	–	–	–	–	–	70
5.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड	नगर विकास	23.01.2003	2500.00 (2450.00)	–	–	2500.00 (2450.00)	–	–	–	–	–	12
प्रक्षेत्रवार कुल				**3600.00 (2450.00)**	**-**	**-**	**3600.00 (2450.00)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92**
विनिर्माण													
6.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23.08.2006	950.00	–	–	950.00	–	–	725.00	725.00	0.76:1	255
7.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	खान एवं भूतत्व	07.05.2002	200.00	–	–	200.00	–	–	–	–	–	398
प्रक्षेत्रवार कुल				**1150.00**	**-**	**-**	**1150.00**	**-**		**725.00**	**725.00**	**0.63:1**	**653**
ऊर्जा													
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	26.11.1987	10500.00	–	–	10500.00	66500.00	–	–	66500.00	6.33:1	633
9.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	ऊर्जा	19.09.2008	–	–	5.00	5.00	–	–	1195.75	1195.75	239.15:1	❖
प्रक्षेत्रवार कुल				**10500.00**	**-**	**5.00**	**10505.00**	**66500.00**	**-**	**1195.75**	**67695.75**	**6.44:1**	**633**

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2011-12 के अन्त में बकाया ऋण				2011-12 के ऋण अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2012 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
सेवायें													
10.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	22.3.2002	250.00 (100.00)	–	–	250.00 (100.00)	–	–	–	–	–	92
11.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	उत्पाद एवं निषेध	26.11.2010	500.00 (300.00)	–	–	500.00 (300.00)	–	–	–	–	–	2
12.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	लोक वितरण एंव उपभोक्ता मामले	18.06.2010	500.00	–	–	500.00	33796.00	–	13000.00	46796.00	93.59:1	272
प्रक्षेत्रवार कुल				**1250.00 (400.00)**	**-**	**-**	**1250.00 (400.00)**	**33796.00**	**-**	**13000.00**	**46796.00**	**37.44:1**	**366**
कुल (क) (प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियां) (अंश आवेदन राशि)				**17005.00 (2850.00)**	–	**5.00**	**17010.00 (2850.00)**	**100821.00**	**-**	**14920.75**	**115741.75**	**6.80:1**	**2308**
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम								-		-			
ऊर्जा													
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा	20.3.2001	–	–	–	–	469419.00	–	17069.00	486488.00	–	5280
प्रक्षेत्रवार कुल				**-**	**-**	**-**	**-**	**469419.00**	**-**	**17069.00**	**486488.00**	**-**	**5280**
कुल (ख) (प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत संविधिक निगम)				**-**	**-**	**-**	**-**	**469419.00**	**-**	**17069.00**	**486488.00**	**-**	**5280**
सकल योग (क + ख)(अंश आवेदन राशि)				**17005.00 (2850.00)**	**-**	**5.00**	**17010.00 (2850.00)**	**570240.00**	**-**	**31989.75**	**602229.75**	**35.40:1**	**7588**
(ग) अकार्यरत सरकारी कम्पनियां		शुन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ) अकार्यरत सांविधिक निगम		शुन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सकल योग (क+ख+ग+घ) (अंश आवेदन राशि)				**17005.00 (2850.00)**	**-**	**5.00**	**17010.00 (2850.00)**	**570240.00**	**-**	**31989.75**	**602229.75**	**35.40:1**	**7588**

(कॉलम 5(क) एवं 5(घ) के कोष्ठक में आँकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते है)

$ प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि शामिल है।

❖ कंपनी के कार्य झा.रा.वि.बो. के अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते है।

(स्रोतः सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट - 2

अद्यतन वर्ष के लिए तैयार लेखे के अनुसार सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कंडिका 1.15 में संदर्भित)

(कॉलम 5(क) से (11) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किये गये	निवल लाभ(+)/हानि(-)				आवर्त्त	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/हानि (-)	निवेशित पूँजी@	निवेशित पूँजी से प्रतिफल$	निवेशित पूँजी से प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं मुल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मुल्य ह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(क)कार्यरत सरकारी कंपनियाँ														
कृषि एवं संबद्ध														
1.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	400.21	-	10.93	389.28	5845.76	-	5.00	1027.53	1027.58	389.28	37.88
2.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	(-)1.78	-	0.82	(-)2.60	160.65	-	500.00	(-)906.74	118.26	(-)2.60	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**398.43**	**-**	**11.75**	**386.68**	**6006.41**	**-**	**505.00**	**120.79**	**1145.84**	**386.68**	**33.75**
आधारभूत संरचना														
3.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2011-12	(-)13.62	-	3.87	(-)17.49	4.36	-	500.00	77.96	609.06	(-)17.49	-
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	323.76	-	5.84	317.92	313.44	-	200.00	1385.26	1583.00	317.92	20.08
5.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड	2005-06	2009-10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**310.14**	**-**	**9.71**	**300.43**	**317.80**	**-**	**700.00**	**1463.22**	**2192.06**	**300.43**	**13.71**
विनिर्माण														
6.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	85.70	12.74	47.82	25.14	1280.09	7.72	800.00	29.76	2343.41	37.88	1.62
7.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड[1]	2006-07	2012-13	1567.97	-	18.10	1549.87	5195.33	-	200.00	6429.45	8703.04	1549.87	17.81
प्रक्षेत्रवार कुल				**1653.67**	**12.74**	**65.92**	**1575.01**	**6475.42**	**7.72**	**1000.00**	**6459.21**	**11046.45**	**1587.75**	**14.37**

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किये गये	निवल लाभ(+)/हानि(-)				आवर्त्त	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव[#]	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/हानि (-)	निवेशित पूँजी[@]	निवेशित पूँजी से प्रतिफल[$]	निवेशित पूँजी से प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं मुल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मुल्य ह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ऊर्जा														
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड[1]	1995-96	2012-13	(-)487.23	8152.82	19.30	(-)8659.35	-	-	10000.00	(-)38686.73	87032.14	(-)506.53	-
9.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**(-)487.23**	**8152.82**	**19.30**	**(-)8659.35**		**-**	**10000.00**	**(-)38686.73**	**87032.14**	**(-)506.53**	**-**
सेवायें														
10.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2004-05	2012-13	15.61	-	4.19	11.42	103.38	1.47	50.00	44.3	93.67	11.42	12.19
11.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**15.61**	**-**	**4.19**	**11.42**	**103.38**	**1.47**	**50.00**	**44.3**	**93.67**	**11.42**	**12.19**
कुल (क) क्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कंपनियां				**1890.62**	**8165.56**	**110.87**	**(-)6385.81**	**12903.01**	**9.19**	**12255.00**	**(-)30599.21**	**101510.16**	**1779.75**	**-**
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम														
ऊर्जा														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	2010-11	2011-12	(-)27577.91	39606.01	5098.54	(-)72282.46	201069.03	10799.00	-	(-)607911.90	315756.00	(-)32676.59	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**(-)27577.91**	**39606.01**	**5098.54**	**(-)72282.46**	**201069.03**	**10799.00**	**-**	**(-)607911.90**	**315756.00**	**(-)32676.59**	**-**
कुल (ख) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम				**(-)27577.91**	**39606.01**	**5098.54**	**(-)72282.46**	**201069.03**	**10799.00**	**-**	**(-)607911.90**	**315756.00**	**(-)32676.59**	**-**
कुल योग (क + ख)				**(-)25687.29**	**47771.57**	**5209.41**	**(-)78668.27**	**213972.04**	**10808.19**	**12255.00**	**(-)638511.11**	**417266.16**	**(-)30896.84**	

टिप्पणीः झारखण्ड राज्य में कोई अकार्यरत सरकारी कंपनी/सांविधिक निगम नहीं है।

[#] लेखा टिप्पणी के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षक एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है, और लाभ में वृद्धि/हानि में कमी को (+) तथा लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को (-) से दर्शाया गया है।

[@] निवेशित पूँजी, निवल अचल परिसंपत्तियों (पूँजीगत प्रगतिशील कार्य सहित) और कार्यशील पूँजी को जोड़कर जहाँ वित्त कम्पनियों/निगमों के संदर्भ में नियोजित पूँजी को प्रदत्त पूँजी, मुक्त रिजर्व, वांडो, जमा और उधार (पुनर्वित सहित) के आरंभिक और अंत शेष के कुल का औसत से निकाला गया है, को छोड़कर दर्शाता है।

[$] निवेशित पूँजी से प्रतिफल लाभ एवं हानि लेखे में भारित ब्याज तथा लाभ को जोड़कर निकाली गई है।

[$$] कंपनी ने अभी तक पहला लेखा जमा नहीं किया है। ** वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान कोई वित्तीय गतिविधि नहीं होने के कारण कम्पनी द्वारा लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया गया है।

[1] टी.वी.एन.एल. (1994-95 और 1995-96) तथा जे.एस.एम.डी.सी. (2006-07) की पूरक लेखापरीक्षा प्रगति पर है।

परिशिष्ट - 3

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अंश पूँजी, ऋण, अनुदान तथा सहाय्य, प्राप्त प्रत्याभूति, बकायों की माफी, अपलिखित ऋण तथा अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण तथा मार्च 2012 की समाप्ति पर प्रत्याभूति प्रतिबद्धता, को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.11 में संदर्भित)

(कॉलम 3(क) से 6(घ) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहाय्य एवं अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति और वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान बकाये की माफी			
		अंश पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलिखित की गई पुनर्अदायगी ऋण	अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण	माफ किये गये ब्याज/दण्ड ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
(क) कार्यरत सरकारी कंपनियां													
आधारभूत संरचना													
1.	जी.आर.डी.ए.	1300.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रक्षेत्रवार कुल		**1300.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिर्माण													
2.	झारक्राफ्ट	150.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रक्षेत्रवार कुल		**150.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवायें													
3.	जे.टी.डी.सी.	100.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	जे.एस.वी.सी.एल	500.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	जे.एस.एफ.सी.एस.सी. एल	–	24396.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रक्षेत्रवार कुल		**600.00**	**24396.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कंपनियां		**2050.00**	**24396.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम													
ऊर्जा													
1.	झा.रा.वि.बो.	–	16495.00	–	75000.00	–	75000.00	–	–	–	–	–	–
प्रक्षेत्रवार कुल		-	**16495.00**	-	**75000.00**	-	**75000.00**	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम		–	**16495.00**	-	**75000.00**	-	**75000.00**	–	–	–	–	–	–
कुल योग (क + ख)		**2050.00**	**40891.00**	-	**75000.00**	-	**75000.00**	-	-	-	-	-	-

(स्रोतः सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट - 4

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में किए गए निवेश को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.23 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सा.क्षे.उ.का नाम	वर्ष जबतक लेखाओं को अंतिमीकृत किया गया है	अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	अवधि जिस दौरान से लेखें बकाया है	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में, जिसके लेखे बकाया है, किए गए निवेश			
					अंश पूँजी	ऋण	अनुदान	अन्य
कार्यरत सरकारी कम्पनी/निगम								
क. सरकारी कम्पनियाँ								
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	2008-09	500.00	2009-10	-	-	180.00	-
				2010-11 से 2011-12	-	-	-	-
2.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	2010-11	200.00	2011-12	-	-	-	-
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2004-05	50.00	2005-06	25.00	-	-	-
				2006-07	-	-	-	-
				2007-08	-	-	-	-
				2008-09	-	-	-	-
				2009-10	25.00	-	-	-
				2010-11	50.00	-	-	-
				2011-12	100.00			
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2010-11	5.00	2011-12	-	-	-	-
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2006-07	200.00	2007-08 से 2011-12	-	-	-	-
6.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2008-09	500.00	2007-08	100.00	-	-	-
				2008-09	100.00	-	-	-
				2009-10	100.00	-	-	-
				2010-11	100.00	-	-	-
				2011-12	-	-	-	-
7.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड	2005-06	-	2005-06	50.00	-	-	-
				2006-07	-	-	-	-
				2007-08	110.00	-	-	-
				2008-09	940.00	-	-	-
				2009-10	100.00	-	-	-
				2010-11	-	-	-	-
				2011-12	1300.00			
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	1995-96	10000.00	1995-96 से 2000-01	-	-	-	-
				2001-02	-	1500.00	-	-
				2002-03	-	1500.00	-	-
				2003-04	-	-	-	-
				2004-05	-	500.00	-	-
				2005-06	500.00	1400.00	-	-
				2006-07	-	800.00	-	-
				2007-08 से 2011-12	-	-	-	-
9.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एण्ड हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	2010-11	800.00	2011-12	150.00	-	-	-
10.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	-	-	2008-09 से 2011-12	-	-	-	-
11.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	-	-	2010-11	-	-	-	-
				2011-12	500.00	-	-	-

क्र. सं.	सा.क्षे.उ.का नाम	वर्ष जबतक लेखाओं को अंतिमीकृत किया गया है	अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	अवधि जिस दौरान से लेखें बकाया है	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में, जिसके लेखे बकाया है, किए गए निवेश			
					अंश पूँजी	ऋण	अनुदान	अन्य
12.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	-	-	2010-11	500.00	9400.00	-	-
				2011-12	-	24396.00	-	-
	कुल (क)				**4750.00**	**42596.00**	**180.00**	**-**
ख.	**सांविधिक निगम**							
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	2010-11	-	2011-12	-	16495.00	75000.00	-
	कुल (ख)				**-**	16495.00	75000.00	**-**
	कुल (क) + (ख)		**11255.00**		**4750.00**	**59091.00**	**75180.00**	**-**

(स्रोतः सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट - 5
सांविधिक निगम के वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.15 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड			
विवरण	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**
क. सम्पत्ति			
सकल ब्लॉक	1938.42	1982.01	2351.60
घटावः मूल्य ह्रास	1014.76	1064.55	1115.61
शुद्ध स्थायी सम्पत्ति	923.66	917.46	1235.99
पूँजीगत प्रगतिशील व्यय	1515.15	1815.03	1813.99
सम्पत्ति उपयोग में नहीं	2.29	2.29	2.29
निवेश	108.11	162.10	200.27
कुल चालू सम्पत्ति	4274.24	4013.19	4740.45
घाटा	4649.72	5356.29	6079.12
कुल (क)	**11473.17**	**12266.36**	**14072.11**
ख. दायित्व			
कार्यशील पूँजी से उधार	-	73.92	218.98
पूँजीगत दायित्व पर बकाया भुगतान	3559.90	3745.38	4481.13
पूँजी दायित्व	231.62	264.39	210.10
राज्य सरकार से निधि	3219.91	3005.93	2958.65
योगदान, अनुदान और सहाय्य	1396.20	1494.91	1570.38
कुल चालू दायित्व	3065.54	3681.83	4632.87
कुल (ख)	**11473.17**	**12266.36**	**14072.11**
ग. विनियोजित पूँजी*	**3647.51**	**3063.85**	**3157.56**

** विनियोजित पूँजी, शुद्ध स्थायी सम्पत्ति (पूँजीगत प्रगतिशील व्यय सहित) जोड़ कार्यशील पूँजी को दर्शाता है।*

परिशिष्ट - 6
सांविधिक निगम के कार्यकारी परिणाम का विवरणी
(कंडिका 1.15 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

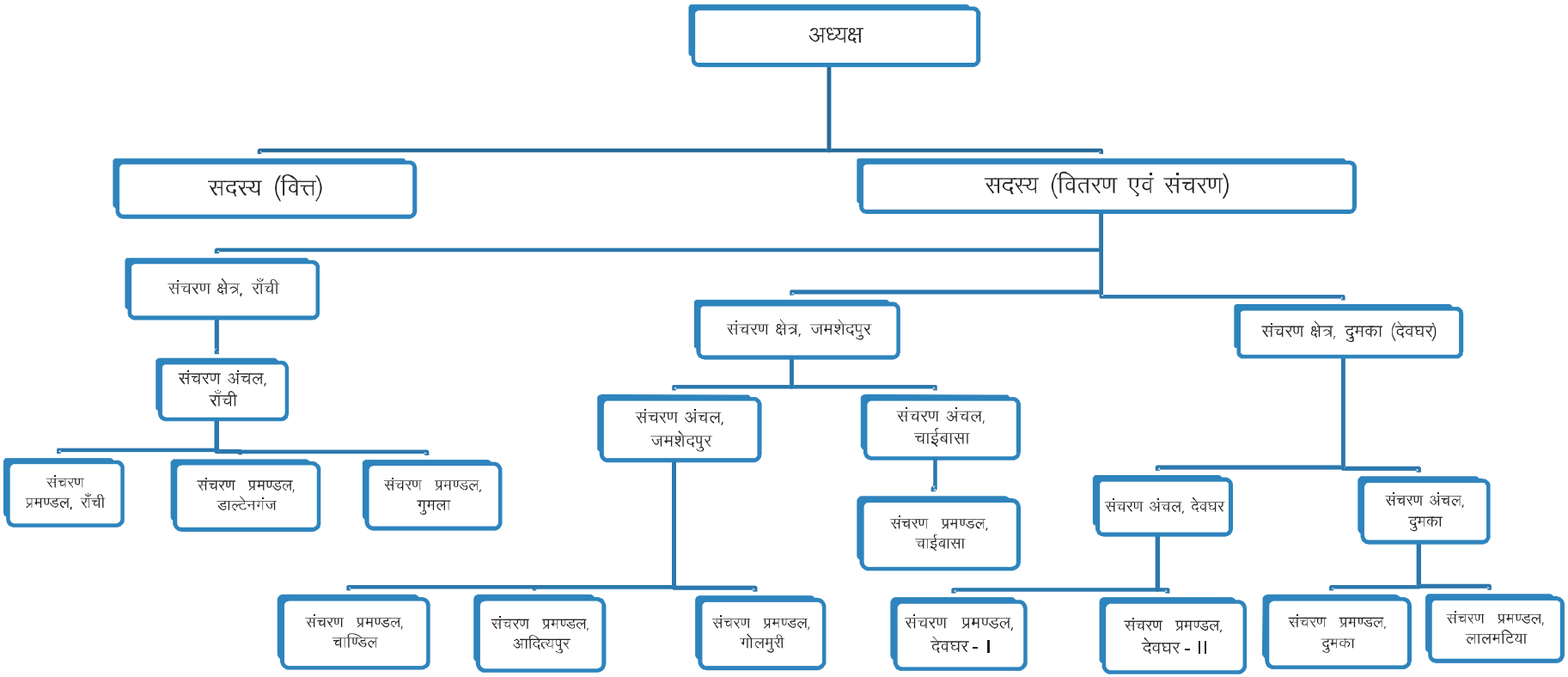
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड					
क्रम. सं.		**विवरण**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**
1.	क)	राजस्व प्राप्तियाँ	1584.91	1634.37	2010.69
	ख)	राजस्व सहाय्य, अनुदान एवं अन्य आय	365.08	701.44	652.85
	ग)	कुल	1949.99	2335.81	2663.54
2.		राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय, अमूर्त परिसंपतियों का अपलेखन सहित परंतु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर)	2444.79	2385.22	3036.58
3.		वर्ष का सकल आधिक्य (+)/घाटा(-) (ना.)	(-) 494.80	(-) 49.41	(-) 373.04
4.		गत वर्ष से संबंधित समायोजन (ना.)	(-) 47.98	(-) 147.44	97.26
5.		वर्ष का अंतिम सकल आधिक्य (+)/ घाटा(-)(3+4)	(-) 542.78	(-) 196.85	(-) 275.78
6.		विनियोग			
	क)	ह्रास	48.40	49.79	50.99
	ख)	पूंजी/ऋण पर ब्याज	559.13	609.75	554.67
	ग)	अन्य ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज	-	-	-
	घ)	ऋण पर कुल ब्याज (ख+ग)	559.13	609.75	554.67
	ङ)	घटाव - पूंजीगत ब्याज	102.08	149.82	158.61
	च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ-ङ)	457.05	459.93	396.06
7.		राज्य सरकार से प्राप्त सहाय्य के लेखांकन से पहले आधिक्य (+)/घाटा(-) (5-6क-6च-1ख) (केवल अनुदान)	(-) 1128.24	(-) 1106.57	(-) 1172.83
8.		शुद्ध आधिक्य (+)/घाटा(-) (5-6क-6च)	(-) 1048.24	(-) 706.57	(-) 722.83
9.		विनियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*(8+6च)	(-) 591.19	(-) 246.64	(-) 326.76
10.		विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत	-	-	-

* विनियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल, शुद्ध आधिक्य/घाटा जोड़ लाभ हानि खाता पर भारित ब्याज (घटावः पूंजीगत ब्याज) को दर्शाता है।

परिशिष्ट - 7

बोर्ड की संगठनात्मक संरचना

(कंडिका 2.2 में संदर्भित)



परिशिष्ट - 8

2011-12 तक पाँच वर्षों के दौरान वोल्टेजवार क्षमता के अनुसार अभिवृद्धि की योजना, वास्तविक अभिवृद्धि तथा कमी की विवरणी

(कंडिका 2.12 में संदर्भित)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400 के.वी. उप-केन्द्र (संख्या)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0	0	0	0
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि	0	0	0	1	5
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि	0	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में (1+3)	0	0	0	0	0
5	अभिवृद्धि में कमी (2-3)	0	0	0	1	5
400 के.वी. ट्रांसफॉर्मर क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0	0	0	0
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि/संवर्द्धन	0	0	0	630	3150
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि	0	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में कुल क्षमता (1+3)	0	0	0	0	0
5	अभिवृद्धि/संवर्द्धन में कमी (2-3)	0	0	0	630	3150
400 के.वी. लाइन (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	180	180	180	180	180
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि	0	0	0	100	1570
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि	0	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में (1+3)	180	180	180	180	180
5	अभिवृद्धि में कमी (2-3)	0	0	0	100	1570
220 के.वी. उप-केन्द्र (संख्या)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	2	3	3	3	3
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि	1	0	1	5	3
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि	1	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में (1+3)	3	3	3	3	3
5	अभिवृद्धि में कमी (2-3)	0	0	1	5	3
220 के.वी. ट्रांसफॉर्मर क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	750	1050	1050	1050	1050
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि/संवर्द्धन	300	0	300	1500	900
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि	300	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में कुल क्षमता (1+3)	1050	1050	1050	1050	1050
5	अभिवृद्धि/संवर्द्धन में कमी (2-3)	0	0	300	1500	900
220 के.वी. लाइन (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	783	903	903	903	903
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि	120	0	407	1654	100
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि	120	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में (1+3)	903	903	903	903	903
5	अभिवृद्धि में कमी (2-3)	0	0	407	1654	100

132 के.वी.उप-केन्द्र (संख्या)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	**17**	**18**	**22**	**26**	**26**
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि	**1**	**4**	**5**	**18**	**4**
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि	**1**	**4**	**4**	**0**	**0**
4	वर्ष के अंत में (1+3)	**18**	**22**	**26**	**26**	**26**
5	अभिवृद्धि में कमी (2-3)	**0**	**0**	**1**	**18**	**4**
132 के.वी. ट्रांसफॉर्मर क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	**1338**	**1438**	**1828**	**2198**	**2208**
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि/संवर्द्धन	**100**	**390**	**470**	**2210**	**400**
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि[1]	**100**	**390**	**370**	**10**	**10**
4	वर्ष के अंत में कुल क्षमता (1+3)	**1438**	**1828**	**2198**	**2208**	**2218**
5	अभिवृद्धि/संवर्द्धन में कमी (2-3)	**0**	**0**	**100**	**2200**	**390**
132 के.वी. लाइन (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के प्रारम्भ में	**1159**	**1252**	**1301**	**1301**	**1441**
2	वर्ष के लिए नियोजित अभिवृद्धि	**93**	**135**	**130**	**2046**	**480**
3	वर्ष के दौरान वास्तविक अभिवृद्धि	**93**	**49**	**0**	**140**	**0**
4	वर्ष के अंत में (1+3)	**1252**	**1301**	**1301**	**1441**	**1441**
5	अभिवृद्धि में कमी (2-3)	**0**	**86**	**130**	**1906**	**480**

[1] डाल्टेनगंज, लातेहार और कांके में प्रत्येक 100 एम.वी.ए. क्षमता का ग्रिड उप केन्द्र का निर्माण क्रमशः अक्टूबर 2007, जनवरी 2009 और दिसम्बर 2009 में हुआ लेकिन अभी तक आवेशित नहीं हुआ (नवम्बर 2012) समाहित है।

परिशिष्ट - 9
झारखण्ड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची एवं उनकी प्रदत्त पूँजी
(कंडिका 3.4.1 में संदर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	31 मार्च 2012 को प्रदत्त पूँजी (₹ करोड़ में)
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको)	5.00
2.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको)	9.00
3.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	9.50
4.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल)	105.00
5.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	2.00
6.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी)	2.50
7.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	0.05
8.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	25.00
9.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	2.00
10.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड (के.ई.एल.)	0.05
11.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल)	5.00*
12.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल)	5.00#

निगमित शासन की कंडिका में क्रम सं. 1 से 9 तक की कंपनियों को शामिल किया गया है।

* समामेलन की तिथि - 26.11.2010

समामेलन की तिथि - 18.06.2010

परिशिष्ट - 10

अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के उल्लंघन की विवरणी

(कंडिका 3.4.2 में संदर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	वैसी तिमाही जिसमें निदेशक मंडल की बैठक नहीं हुई	धारा 285 के उल्लंघन की सं.	निदेशक मंडल के दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) ^	अक्टूबर - दिसम्बर 2007, जनवरी - मार्च 2008, जुलाई - सितम्बर 2008, अक्टूबर - दिसम्बर 2008, अप्रैल - जून 2009, अक्टूबर - दिसम्बर 2009, जनवरी - मार्च 2010	7	11 महीना 3 दिन
2.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको)	जुलाई - सितम्बर 2007, जनवरी - मार्च 2008, अप्रैल - जून 2008, जुलाई - सितम्बर 2008, अक्टूबर - दिसम्बर 2008, जनवरी - मार्च 2009, अप्रैल - जून 2009, अक्टूबर - दिसम्बर 2009, जनवरी - मार्च 2010, जुलाई - सितम्बर 2010, अक्टूबर - दिसम्बर 2010, जनवरी - मार्च 2011, जुलाई - सितम्बर 2011, अक्टूबर - दिसम्बर 2011, जनवरी - मार्च 2012	15	21 महीना 20 दिन
3.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	अप्रैल - जून 2007, जनवरी - मार्च 2008, अप्रैल - जून 2008, अक्टूबर - दिसम्बर 2008, जनवरी - मार्च 2009, अक्टूबर - दिसम्बर 2009, अप्रैल - जून 2011, अक्टूबर - दिसम्बर 2011	8	7 महीना 3 दिन
4.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल)	अप्रैल- जून 2007, जुलाई - सितम्बर 2007, जुलाई - सितम्बर 2008, अक्टूबर - दिसम्बर 2008, जनवरी - मार्च 2009, जुलाई - सितम्बर 2009, अक्टूबर - दिसम्बर 2009, जनवरी - मार्च 2010, अक्टूबर - दिसम्बर 2010, जनवरी - मार्च 2012	10	15 महीना 21 दिन
5.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	जुलाई - सितम्बर 2007, अक्टूबर - दिसम्बर 2007, जनवरी - मार्च 2009, अक्टूबर - दिसम्बर 2009, जनवरी - मार्च 2010, अक्टूबर - दिसम्बर 2010, जनवरी - मार्च 2011, अप्रैल - जून 2011, अक्टूबर - दिसम्बर 2011, जनवरी - मार्च 2012	10	10 महीना 2 दिन
6.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी)	अक्टूबर - दिसम्बर 2007, जुलाई - सितम्बर 2008, अक्टूबर - दिसम्बर 2008, जनवरी - मार्च 2009, अक्टूबर - दिसम्बर 2009, जनवरी - मार्च 2010, जुलाई - सितम्बर, 2010, अक्टूबर - दिसम्बर 2010, जनवरी - मार्च 2011, अप्रैल - जून 2011, जुलाई - सितम्बर 2011, अक्टूबर - दिसम्बर 2011	12	18 महीना 5 दिन
7.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	अक्टूबर - दिसम्बर 2007, जनवरी - मार्च 2009, अप्रैल - जून 2009, जनवरी - मार्च 2010 ,जनवरी - मार्च 2011	5	8 महीना 5 दिन
8.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	जनवरी - मार्च 2007, जुलाई - सितम्बर 2007, अक्टूबर - दिसम्बर 2007, जनवरी - मार्च 2008, अप्रैल - जून 2008, जुलाई - सितम्बर 2008, अक्टूबर - दिसम्बर 2008, जनवरी - मार्च 2009,	11	25 महीना 05 दिन

		अप्रैल - जून 2009, अक्टूबर - दिसम्बर 2009, अप्रैल - जून 2010.		
9.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	अप्रैल - जून 2007, जुलाई - सितम्बर 2007, अक्टूबर - दिसम्बर 2007, जनवरी - मार्च 2008, अक्टूबर - दिसम्बर 2008, अप्रैल - जून 2009, जुलाई - सितम्बर 2009, अक्टूबर - दिसम्बर 2009, जनवरी - मार्च 2010, अप्रैल - जून 2010, अक्टूबर - दिसम्बर 2010, जनवरी - मार्च 2011, सितम्बर - दिसम्बर 2011	13	19 महीना 23 दिन

^ सूचना संबंधित कम्पनियों द्वारा संधारित कार्यवृत पंजी पर आधारित।

परिशिष्ट - 11

अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल में उपस्थिति की विवरणी

(कंडिका 3.4.2 में संदर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	निदेशकों का नाम	बैठकों की संख्या	
			कार्यकाल के दौरान बैठके	उपस्थिति
1.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको)	ए.के. बासु	4	1
		मुख्तयार सिंह	4	1
		श्रीमति राजवाला वर्मा	2	शुन्य
2.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी)	अमिताभ चौधरी	1	शुन्य
		के.एस.मीणा	1	शुन्य
3.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	श्रीमति राजवाला वर्मा	6	2
		मुख्तयार सिंह	2	1
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	श्रीमति राजवाला वर्मा	10	3
		मुख्तयार सिंह	2	1
		सुधीर त्रिपाठी	6	2
		सूर्यदेव प्रसाद	4	1
		योगेश्वर मोची	2	1
		सुखदेव सिंह	5	3
		जी.एस.रथ	3	1
5.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल)	अपने कार्य काल में निदेशक सभी बैठकों में उपस्थित हुए		
6.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	आर. के. जुत्सी	2	1
		सुधीर महतो	6	1
		सुदेश महतो	6	1
		ए.के. चुग	1	शुन्य
		श्रीमति राजवाला वर्मा	9	1
		सुखदेव सिंह	8	2
7.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको)	सूचना प्राप्त नहीं हुई		
8.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	वित्त विभाग के सचिव	4	शुन्य
		आर.एस.पोद्दार	2	1
		श्रीमति राजवाला वर्मा	3	शुन्य
		एस.के. चौधरी	3	शुन्य
		के.के. खण्डेलवाल	1	शुन्य
		ए.के. सरकार	9	4
		ए.पी.सिंह	8	1
9.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	अशोक कुमार सिंह	3	2
		नीतिन कुलकर्णी	5	3
		सुखदेव सिंह	6	3
		एल. खेंगटे	3	2

परिशिष्ट - 12
प्रबंध निदेशक, जिनका कार्यकाल एक साल से कम था, का विवरणी

(कंडिका 3.4.2 में संदर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	प्रबंध निदेशकों के नाम	कार्यकाल	अवधि
1.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल)	एस.एन. चौधरी	25.09.2010 से 18.10.2010	23 दिन
2.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	एच.के. मिश्रा	24.02.2009 से 21.12.2009	9 महीना 28 दिन
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी)	अब्राहम रौना	11.05.2009 से 07.12.2009	6 महीना 27 दिन
		नीलिमा केरकेट्टा	08.12.09 से 10.06.2010	7 महीना 2 दिन
4.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	भगवान प्रसाद	04.08.2009 से 07.06.2010	10 महीना 3 दिन
5.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	अरूण कुमार सिंह	01.01.2008 से 03.11.2008	11 महीना 2 दिन
		अरूण कुमार सिंह	23.10.2009 से 15.04.2010	5 महीना 22 दिन
		पी.के. जजोरिया	15.04.2010 से 06.04.2011	11 महीना 21 दिन

परिशिष्ट - 13

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अधीन कम्पनियों के निबंधक को कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये वार्षिक रिटर्न की विवरणी

(*कंडिका 3.4.3 में संदर्भित*)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष की वार्षिक रिटर्न	वार्षिक रिटर्न जमा करने की तिथि	वार्षिक रिटर्न जमा करने में देरी	वर्ष, जिसमें वार्षिक रिटर्न जमा नहीं की गई
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको)	2006-07	10.03.2008	3 महीना (लगभग)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
2.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको)	2006-07	24.07.2010	2 साल एवं 8 महीना (लगभग)	2009-10, 2010-11
		2007-08	08.07.2011	2 साल एवं 7 महीना (लगभग)	
		2008-09	08.07.2011	1 साल एवं 7 महीना (लगभग)	
3.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	2006-07	03.09.2010	2 साल एवं 9 महीना (लगभग)	2010-11
		2007-08	03.09.2010	1 साल एवं 9 महीना (लगभग)	
		2008-09	12.07.2011	1 साल एवं 7 महीना (लगभग)	
		2009-10	12.07.2011	7 महीना (लगभग)	
		2010-11	30.10.2011	कोई देरी नहीं	
4.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.)	1993-94 से वार्षिक रिटर्न जमा नहीं की गई			
5.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	2006-07	18.02.2009	1 साल एवं 3 महीना (लगभग)	-
		2007-08	21.01.2009	01 महीना एवं 24 दिन	
		2008-09	31.01.2011	1 साल एवं 02 महीना (लगभग)	
		2009-10	12.03.2011	01 महीना एवं 17 दिन	
		2010-11	22.03.2012	03 महीना एवं 23 दिन	
6.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.)	2006-07	जमा नहीं की गई	जमा नहीं की गई	2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11.
		2007-08	27.11.2008	20 दिन	
7.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	2006-07	12.03.2011	3 साल एवं 3 महीना (लगभग)	-
		2007-08	12.03.2011	2 साल एवं 4 महीना (लगभग)	
		2008-09	12.03.2011	1 साल एवं 4 महीना (लगभग)	
		2009-10	12.03.2011	4 महीना (लगभग)	
		2010-11	07.11.2011	कोई देरी नहीं	

8.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	आजतक वार्षिक रिटर्न जमा नहीं की गई			समामेलन से (7.5.2002 को समामेलित)
9.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	2007-08	23.09.2011	3 साल एवं 9 महीना 23 दिन	–
		2008-09	23.09.2011	2 साल एवं 9 महीना 23 दिन	
		2009-10	23.09.2011	1 साल एवं 9 महीना 23 दिन	
		2010-11	23.09.2011	2 महीना	

परिशिष्ट - 14

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अधीन कम्पनी निबंधक को वार्षिक लेखे दाखिल करने से संबंधित विवरणी

(कंडिका 3.4.3 में संदर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष के वार्षिक लेखें	वार्षिक लेखें जमा करने की तिथि	वार्षिक लेखें जमा करने में देरी	वर्ष जिसमें वार्षिक लेखें जमा नहीं की गई
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको)	2004-05 से आर्थिक चिट्ठा और लाभ-हानि खाता जमा नहीं की गई			
2.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको)	2006-07	24.07.2010	2 साल एवं 9 महीना (लगभग)	2009-10 एवं 2010-11
		2007-08	08.07.2011	2 साल एवं 9 महीना (लगभग)	
		2008-09	08.07.2011	1 साल एवं 8 महीना (लगभग)	
3.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	2006-07	07.07.2011	3 साल एवं 7 महीना (लगभग)	2010-11
		2007-08	08.07.2011	2 साल एवं 7 महीना (लगभग)	
		2008-09	12.07.2011	1 साल एवं 7 महीना (लगभग)	
		2009-10	12.07.2011	7 महीना (लगभग)	
4.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.भी.एन.एल.)	1993-94 से आर्थिक चिट्ठा और लाभ-हानि खाता जमा नहीं की गई			
5.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	2006-07	18.02.2009	1 साल एवं 04 महीना (लगभग)	
		2007-08	21.01.2009	02 महीना एवं 24 दिन	
		2008-09	31.01.2011	1 साल एवं 03 महीना (लगभग)	
		2009-10	12.03.2011	01 महीना एवं 17 दिन	
		2010-11	22.03.2012	04 महीना एवं 23 दिन	
6.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.)	2006-07	जमा नहीं की गई	जमा नहीं की गई	2006-07, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11.
		2007-08	27.11.2008	1 महीना एवं 20 दिन	
7.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	2006-07	28.02.2012	4 साल एवं 4 महीना (लगभग)	2010-11
		2007-08	28.02.2012	3 साल एवं 4 महीना (लगभग)	
		2008-09	17.03.2011	2 साल एवं 5 महीना (लगभग)	
		2009-10	07.11.2011	1 साल (लगभग)	
8.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	समामेलन (7 मई 2002) से आर्थिक चिट्ठा और लाभ-हानि खाता जमा नहीं की गई			
9.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	समामेलन (23 जनवरी 2003) से आर्थिक चिट्ठा और लाभ-हानि खाता जमा नहीं की गई			

परिशिष्ट - 15
कम्पनियों द्वारा किये गये वार्षिक आम सभा की विवरणी
(कंडिका 3.4.4 में संदर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	ए.जी.एम. का क्र. सं.	वित्त वर्ष	ए.जी.एम. की तिथि	जिस वर्ष में ए.जी.एम. नहीं हुआ
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको)	पांचवीं	2006-07	28.09.2007	2010-11
		छठीं	2007-08	24.09.2008	
		सातवीं	2008-09	02.02.2010	
		आठवीं	2009-10	27.09.2010	
2.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको)	पहली	2006-07	26.08.2009	2007, 2008, 2009, 2010 एवं 2011.
		दूसरी	2007-08	16.04.2010	
		तीसरी	2008-09	13.06.2011	
		चौथी	2009-10	13.06.2011	
3.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	पहली	2006-07	29.09.2007	2009 एवं 2010
		पहली स्थगित	2006-07	23.09.2008	
		दूसरी	2007-08	26.09.2008	
		तीसरी	2008-09	20.06.2011	
		चौथी	2009-10	20.06.2011	
		पांचवीं	2010-11	24.09.2011	
4.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल)	**कोई ए.जी.एम.नहीं हुआ**			
5.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	पांचवीं	2006-07	28.09.2007	ए.जी.एम. लगातार हुआ था
		पांचवीं स्थगित	2006-07	08.08.2008	
		छठीं	2007-08	27.09.2008	
		छठीं स्थगित	2007-08	19.12.2008	
		सातवीं	2008-09	16.09.2009	
		सातवीं स्थगित	2008-09	25.09.2009	
		आठवीं	2009-10	25.09.2010	
		आठवीं स्थगित	2009-10	05.08.2011	
		नवीं	2010-11	29.09.2011	
		नवीं स्थगित	2010-11	12.03.2012	
6.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी)	पहली	2002-03	18.09.2003	2007, 2010 एवं 2011
		पहली स्थगित	2002-03	28.04.2008	
		दूसरी	2003-04	12.08.2004	
		दूसरी स्थगित	2003-04	29.06.2009	
		तीसरी	2004-05	**नहीं हुआ**	
		चौथी	2005-06	25.09.2006	
		पांचवीं	2006-07	28.04.2008	
		छठीं	2007-08	29.09.2008	
		सातवीं	2008-09	07.09.2009	
7.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	पांचवीं	2006-07	28.09.2007	ए.जी.एम. लगातार हुआ था
		छठीं	2007-08	25.09.2008	

		सातवीं	2008-09	10.09.2009	
		आठवीं	2009-10	20.09.2010	
		नवीं	2010-11	29.09.2011	
8.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	पहली	2002-03	02.02.2012	2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11
		दूसरी	2003-04	02.02.2012	
		तीसरी	2004-05	02.02.2012	
		चौथी	2005-06	23-06-2012	
9.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	पहली से पांचवीं	2003-04 से 2007-08	26-06-2008	2007 एवं 2009
		छठीं	2008-09	30-09-2010	
		सातवीं	2009-10	30-09-2010	
		आठवीं	2010-11	27-09-2011	

परिशिष्ट - 16
कंडिकायें/निष्पादन लेखा परीक्षा, जिसका उत्तर अप्राप्त था, की विवरणी

(कंडिका 3.6.1 में संदर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था
1.	ऊर्जा	7	7	4	4	6	6	2	2
2.	वन एवं पर्यावरण	-	-	1	1	-	-	-	-
3.	गृह	1	1	-	-	1	1	1	1
4.	खान एवं भूतत्व	1	-	-	-	-	-	1	1
	कुल	**9**	**8**	**5**	**5**	**7**	**7**	**4**	**4**

परिशिष्ट - 17

विभागावार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) की विवरणी

(कंडिका 3.6.3 में संदर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. की सं.	लम्बित नि.प्र. की सं.	लम्बित कंडिकाओं की सं.	जिस वर्ष से कंडिका लम्बित है
1.	ऊर्जा	2	287	1119	2005-06
2.	वन एवं पर्यावरण	1	23	76	2006-07
3.	खान एवं भूतत्व	1	4	18	2010-11
4.	पर्यटन	1	10	38	2007-08
5.	उद्योग	2	5	21	2007-08
6.	गृह	1	13	63	2006-07
7.	जल संसाधन	1	13	41	2006-07
8.	नगर विकास	1	2	12	2009-10
कुल		**10**	**357**	**1388**	

परिशिष्ट - 18

विभागावार प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर, जो अप्राप्त थे, की विवरणी

(कंडिका 3.6.3 में संदर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की सं.	निर्गत करने की अवधि
1.	ऊर्जा	2	जून 2012 से जुलाई 2012
2.	वन एवं पर्यावरण	1	मई 2012
3.	गृह	1	मई 2012
4.	ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, गृह, उद्योग, पर्यटन एवं जल संसाधन	1	जुलाई 2012
	कुल	**5**	-